चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 13 मार्च– 19 मार्च 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

ये बनेंगे राष्ट्रपति

मनीष कुमार

इस वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होगा. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निर्विवादित कार्यकाल खत्म होने जा रहा है. वे एक शानदार राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे. आजादी के बाद शुरुआती दौर में राष्ट्रपति कोई राजनीतिक पद नहीं माना गया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन व जाकिर हुसैन जैसे महापुरुषों ने राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाई. लेकिन समाज और राजनीति के गिरते स्तर के साथ राष्ट्रपति के पद का भी राजनीतिकरण हुआ. भारत में अब न तो वो राजनीतिक संस्कृति बची है और न ही वैसे राजनेता हैं, जो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद की गरिमा को बचाने के लिए कोई छोटी सी भी पहल करें. संकुचित राजनीतिक संस्कृति के दौर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एक अपवाद थे. वे एक सर्वसम्मति से चुने हुए राष्ट्रपति थे. अच्छा तो ये होता कि इस बार भी कंसेंसस यानि सर्वसम्मति से उम्मीदवार को चुना जाता, लेकिन वर्तमान राजनीति का मिजाज ऐसा है, जिसमें इसकी कल्पना करना भी हास्यास्पद है. संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बना कर राजनीतिक–ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए राष्ट्रपति चुनाव न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि इस चुनाव से उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि देश का राजनीतिक माहौल ध्रुवीकरण की ओर अग्रसर है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती है, जो उनकी विचारधारा में विश्वास करने वाला नहीं हो, या जो सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी नापसंदगी या असंतोष व्यक्त कर दे. इसलिए ये उम्मीद करनी चाहिए कि इंदिरा गांधी के बाद के कांग्रेस से सीख लेते हुए भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसे उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाना चाहेगी, जो वाकई में महज नाममात्र हो. इसलिए अब बस यही सवाल बचा है कि क्या राष्ट्रपति का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा? क्या वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि का होगा? या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी गैर राजनीतिक पेशवर व्यक्ति को सामने लाएगी?

भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रपति को लेकर अभी काफी उहापोह की स्थिति है. कई लोग लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज के नाम को संभावित उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं. लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्य–प्रणाली से परिचित हैं, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे वरिष्ठ राजनेता को राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जिनके राजनीतिक–रिश्ते प्रधानमंत्री के साथ अच्छे नहीं हैं. लालकृष्ण आडवाणी की उम्र और यदा–कदा सरकार को नसीहत देने वाले बयानों की वजह से उन्हें इस पद के लिए चुनना शायद प्रधानमंत्री को स्वीकार्य नहीं होगा. मुरली मनोहर जोशी को पद्मविभूषण से सम्मानित कर उन्हें इस रेस से बाहर कर दिया गया है. हालांकि उन्होंने संघ के अधिकारियों के साथ मिल कर बहुत कोशिश की है और अभी भी प्रयासरत हैं. कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सुषमा स्वराज के नाम पर विचार हो रहा है. वे पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से वरिष्ठ रही हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है. उनके नाम पर विचार हो सकता है, अगर चुनाव का अंकगणित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न हो. राजनीतिक हलकों में ये भी अफवाह है कि प्रणब मुखर्जी को फिर से चुना जा सकता है. दरअसल, ये अफवाह ही है. अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते चुनाव जीतने लायक वोट मैनेज कर लेती है, तो नरेंद्र मोदी अपने पसंदीदा किसी गैर राजनीतिक पेशेवर व्यक्ति या फिर संघ की पृष्ठभूमि के किसी दलित नेता को सामने रख कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे.

> जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, तो इनके पास लोकसभा में बहुमत है, साथ ही 12 राज्यों में इनकी सरकार है. भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल इतने वोट नहीं हैं, जिससे ये अपने मनमुताबिक राष्ट्रपति बना सकें. राष्ट्रपति चुनाव का अंकगणित इतना पेचीदा है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10.98 लाख वोट पड़ते हैं. इसमें से आधा वोट सांसदों का है और आधा देश भर के विधायकों का है. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 लोग वोट डालेंगे. इनमें से 776 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और बाकी 4120 देश भर के विधायक हैं.

> बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की है. नीतीश ने हाल ही में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वाममोर्चा और ईंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं से दिल्ली में बातचीत की. नीतीश कुमार ने यह चिंता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकती है. इसलिए विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार को खड़ा करना जरूरी है. नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के महत्व और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का सटीक आकलन कर एक राजनीतिक पहल किया है.

अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बूते पर राष्ट्रपति चुनाव जीतने की क्षमता है? इस सवाल का सीधा जवाब है... नहीं. पूरे देश की नजर फिलहाल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर टिकी है. लेकिन मीडिया का ध्यान अभी तक इस पर नहीं गया है कि इन विधानसभा चुनावों का राष्ट्रपति चुनाव से क्या रिश्ता है. यहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव की तारीफ करनी पड़ेगी. उन्होंने ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की इस कमी को सामने रखा और विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की पहल की है. जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल मिला कर 1,03,757 वोट हैं. मतलब यह कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ रही है, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट भी इकट्ठा कर रही है. राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भारी संख्या में विधायक जिताने होंगे. खासकर, उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, तो इनके पास लोकसभा में बहुमत है, साथ ही 12 राज्यों में इनकी सरकार है. भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल इतने वोट नहीं हैं, जिससे ये अपने मनमुताबिक राष्ट्रपति बना सकें. राष्ट्रपति चुनाव का अंकगणित इतना पेचीदा है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ेगी. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10.98 लाख वोट पड़ते हैं. इसमें से आधा वोट सांसदों का है और आधा देश भर के विधायकों का है. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 लोग वोट डालेंगे. इनमें से 776 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और बाकी 4120 देश भर के विधायक हैं. फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 282 और राज्यसभा में 56 सांसद हैं और देश भर में कुल 1126 विधायक हैं. राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद के वोट की वैल्यू 708 है. भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने उम्मीदवार को जिताना है, तो इन्हें 5.49 लाख वोट चाहिए होगा, जो फिलहाल इनके पास नहीं है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ये बनेंगे राष्ट्रपति

पृष्ठ 1 का शेष

भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके गठबंधन सहयोगियों को भी मिला लें, यानि अगर नेशलनल डेमोक्रेटिक एलाएंस के वोट को एक साथ रखें, तो भी इनके पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले पूरे वोट का 50 फीसदी आंकड़ा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को अभी कम से कम 75,000 वोटों की जरूरत है. इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतना पड़ेगा. वरना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव जीतने में भी कठिनाई पैदा हो जाएगी. राष्ट्रपति चुनाव के नजरिए से उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण बन गया है. राष्ट्रपति चुनाव में पड़ने वाले सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में हैं. इस राज्य में हर विधायक के पास 208 वोट हैं, यानि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 83,824 वोट हैं. उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन राष्ट्रपति चुनाव में उसके लिए महंगा पड़ सकता है. ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की मदद ले सकती है. लेकिन तब उन्हें उम्मीदवार के चुनाव में समर्थन देने वाली पार्टियों के साथ सहमत होना पड़ेगा. दूसरी मुसीबत ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सामंजस्य बनाने में भी परेशानी होगी.

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं. वामपंथी पार्टियों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसकी भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. यानि कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी. ओडीशा के स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उससे नवीन पटनायक सहम चुके हैं. इसलिए बीजेडी से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है. शिव सेना से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में मदद मिलेगी, इस पर सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है. हालांकि तमिलनाडु से एआईडीएमके की मदद मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं होगी.

भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में फिलहाल अक्षम है. यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की है. नीतीश ने हाल ही में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वाममोर्चा और इंडियन नेशलन लोकदल के नेताओं से दिल्ली में बातचीत की. नीतीश कुमार ने यह चिंता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकती है. इसलिए विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार को खड़ा करना जरूरी है. नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं. उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के महत्व और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का सटीक आकलन कर एक राजनीतिक पहल किया है.

राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है. यानि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी के सदस्य उस पार्टी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार को ही वोट करेंगे. मतदान गुप्त होता है. यह पता नहीं चल पाता है कि किस सांसद/विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट दिया. ये पहलू भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है. माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और विधायक पार्टी की कार्य-प्रणाली से नाराज हैं. नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से सरकार और पार्टी को चला रहे हैं, उससे वे खफा हैं. विपक्षी पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी की इस दरार के बारे में पता है. अगर विपक्षी पार्टियां एक सुदृढ़ रणनीति और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ती हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस अंतर्कलह का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते है. राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के लिए एक मौका है, जब वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है. हालांकि इसके लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा और अपना एक सर्वसम्मत उम्मीदवार तय करना होगा. विपक्षी दलों में से किसी एक नेता या एक गुट को लीडरशिप लेनी होगी, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पहल की है. अब देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार की इस पहल को विपक्ष का समर्थन मिलता है, या फिर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के इस मौके को गंवा देता है. ■

manishbph244@gmail.com

ऐसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति

किसी भी संघीय प्रजातांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है. लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है. मतलब यह कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है. इसमें दोनों सदनों के चुने हुए सांसद और देश के हर राज्य के चुने हुए विधायक हिस्सा लेते हैं. इसमें मनोनित सांसद और विधानपरिषद के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 10.98 लाख वोट पड़ते हैं. इसमें से आधा वोट सांसदों का है और आधा देश भर के विधायकों का है. राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,896 लोग वोट डालते हैं. इनमें से 776 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं और बाकी 4,120 देश भर के विधायक हैं. समझने वाली बात ये है कि अलग-अलग राज्यों के विधायकों के पास एक जैसा वोट नहीं होता. सासंदों और विधायकों की वोटिंग की वोटिंग वैल्यू में भी अंतर होता है.

राष्ट्रपति का चुनाव एक खास तरीके से किया जाता है. राष्ट्रपति चुनाव के मतदाताओं का मत एक बराबर नहीं होता है. अलग-अलग मतदाताओं के वोटों की संख्या अलग-अलग होती है. राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट देते हैं. सांसदों के वोट की वैल्यू तो समान होती है, लेकिन हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू अलग-अलग होती है. विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या पर निर्भर होती है. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 अरब है, लेकिन चुनाव के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाता है. 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव संपन्न होंगे. सांसदों के वोट की वैल्यू विधायकों के वोट से ज्यादा होती है. हर राज्य के विधायकों के वोट भी बराबर नहीं होते हैं. बड़े राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू ज्यादा होती है. एक और बात, दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों के वोट की वैल्यू सभी राज्यों के विधायकों की कुल वोट वैल्यू के बराबर होती है.

एक राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू यानी संख्या निकालने के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या को वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है. परिणाम में आई हुई संख्या को 1,000 से भाग दिया जाता है. इससे जो संख्या आती है, वही उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी. इस तरह प्रत्येक राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है. जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है और बिहार के विधायक की वोट वैल्यू 173 है, वहीं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विधायकों की वोट वैल्यू सिर्फ 8 है. इस तरह जनसंख्या के आधार पर हर राज्य की भागादारी सुनिश्चित हो जाती है. सांसदों के वोट की वैल्यू विधायकों से ज्यादा होती है. इसकी वजह यह है कि सांसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए देश के सभी राज्यों के विधायकों के वोट और सांसदों के वोट को बराबर माना गया है. सांसदों के वोट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देश के हर राज्य के विधायकों के वोट का ग्रैंड-टोटाल किया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है. इससे जो परिणाम आता है वह एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है.

आम चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में एक और बड़ा फर्क है. आम चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है. जबकि राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट पाना आवश्यक होता है. मतलब यह कि 50 प्रतिशत के अलावा 1 और वोट उम्मीदवार के पक्ष में आना जरूरी है. राष्ट्रपति पद का चुनाव मल्टी कैंडिडेट इलेक्शन होता है, यानी इस चुनाव में दो से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं. इसलिए ज्यादातर यह संभव नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिल सके. इसलिए ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रावधान है. देश के छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी इस मामले में अपवाद रहे हैं. वे ऐसे राष्ट्रपति हुए, जिनके खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ था और इसीलिए वे निर्विरोध यानी अनअपोज्ड राष्ट्रपति बने थे.

राष्ट्रपति चुनाव में प्रिफ्रेंशियल सिस्टम वोटिंग होती है, यानि मतदाताओं के लिए यह जरूरी होता है कि वे अपनी पसंद के क्रम के अनुसार सभी प्रत्याशियों को वोट दें. उदाहरण के लिए, मान लें कि कुल चार उम्मीदवार हैं, तो मतदाताओं को अपनी इच्छा से पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी और फिर चौथी पसंद के क्रम के अनुसार वोट देने होंगे. अगर पहली गिनती में एक को 30 फीसदी, दूसरे को 12 फीसदी, तीसरे को 40 फीसदी और चौथे को 18 फीसदी वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोटों में मिले हुए सेकेंड प्रिफ्रेंस के वोट को उस उम्मीदवार के वोटों में शामिल कर दिया जाता है. एलिमिनेशन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट न मिल जाएं. हालांकि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सिर्फ एक बार दूसरे दौर की गिनती की गई है. वर्ष 1969 में सेकेंड प्रिफ्रेंस के हिसाब से वी वी गिरि निर्वाचित घोषित किए गए थे. यह एक अपवाद है. इसके अलावा आज तक सेकेंड प्रिफ्रेंस के वोटों की गिनती की आवश्यकता नहीं पड़ी है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 02
13 मार्च- 19 मार्च 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चौकीदारों की चौकीदारी कौन करेगा

चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा? केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो पूर्व प्रमुख कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के दायरे में है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व संयुक्त निदेशक जेपी सिंह और तीन अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है. सिंह पर इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी घोटाले और एक कथित हवाला ऑपरेटर अफरोज फाट्टा के खिलाफ 5000 करोड़ रुपये काले धन की जांच के दौरान रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लगाया गया है.

सीबीआई द्वारा सितंबर 2015 में मामला दर्ज करने के बाद 2000 बैच के कस्टम और एक्साइज कैडर के आईआरएस अधिकारी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय से बर्खास्त कर के मूल कैडर भेज दिया गया. सिंह को प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी संजय कुमार, मुंबई स्थित बिचौलिया बिमल अग्रवाल और गुजरात के सट्टेबाज चंद्रेश पटेल के साथ गिरफ्तार किया गया था. मौजूदा ईडी चीफ करनैल सिंह द्वारा की गई एक आंतरिक जांच से पता चला था कि सिंह और कुमार भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे.

सिंह ने हालांकि अपने खिलाफ साजिश रचने और रिश्वत मामले में फंसाने के लिए क्रिकेट सट्टेबाजों पर आरोप लगाया है. बहरहाल, कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों पर लगने वाले ऐसे आरोपों से सवाल उठता है कि इन चौकीदारों की चौकीदारी कौन करेगा? ■

त्यागी की नई पारी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भी अजय त्यागी दुखी हैं. वजह ये है कि उनके कार्यकाल में दो साल की कटौती हो गई है. त्यागी अब पांच की जगह तीन साल ही अध्यक्ष रहेंगे. केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. बाबू सर्किल में इस बात को लेकर कानाफूसी जारी है. त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के अधिकारी हैं. इन्हें चुनने के क्रम में केंद्र सरकार ने पावर सेक्रेटरी पी के पुजारी सहित कई वरिष्ठ नौकरशाहों के दावों को किनारे कर दिया था. सेबी में आने से एक हफ्ते पहले तक स्थिति ये थी कि त्यागी को उनके मूल कैडर में भेजा जाना था, ताकि वे प्रमोशन पा सकें. सूत्रों का कहना है कि वे अभी भी मुख्य सचिव वाला स्केल प्राप्त नहीं कर सकते.

लेकिन यह सब अतीत की बात है. अब सबकी निगाहें त्यागी और सेबी में उनके कार्यकाल पर होंगी. त्यागी लो प्रोफाइल रखने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ऐसे समय में सेबी का कार्यभार संभाला है, जब सेबी पूंजी बाजार की अखंडता को मजबूत बनाने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है. ■

बाबुओं का विद्रोह

बीएसएससी पेपर लीक मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से आईएएस अधिकारी गुस्से में हैं. ऐसी स्थिति आएगी, इसकी कल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नहीं की होगी. इस घटना ने प्रदेश में आईएएस और आईपीएस सेवाओं के बीच की प्रतिद्वंद्विता को उजागर किया है. सूत्रों का कहना है कि एसआईटी द्वारा सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी काफी गुस्से में है और इस लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए तैयार हैं. ये लोग कुमार को ईमानदार और सक्षम अधिकारी मानते हैं. संघ के सचिव विवेक कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि आईएएस अधिकारी आगे से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय समेत किसी भी उच्च कार्यालय से मिले मौखिक निर्देशों को नहीं मानेंगे. इसके अलावा, कोई भी सदस्य बीएसएससी में अध्यक्ष, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा नियंत्रक या तकनीकी सेवा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पद को स्वीकार नहीं करेगा.

एसोसिएशन ने संकल्प लिया है कि उसके सदस्य विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधेंगे और तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जातीं. ये गुस्सा पुलिस को ले कर भी है. संघ की मांग है कि इस मामले को स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित किया जाए. सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ बाबुओं का ये सबसे मजबूत विद्रोह है. ■

बात दूर तलक ले जाएंगे

लालू प्रसाद अच्छी तरह समझ रहे हैं कि शराबबंदी और बेहतर प्रशासन के कारण नीतीश कुमार की छवि इस समय जनता के बीच काफी अच्छी है. हाल में पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार ने जितना बोल्ड कदम उठाया, उससे भी जनता के बीच उनकी एक कुशल और कठोर प्रशासक की छवि गई है. लालू प्रसाद समझते हैं कि सत्ता परिवर्तन का यह सही समय नहीं है, इसलिए दबाव और केवल दबाव की रणनीति ही इस समय कारगर है. लालू प्रसाद इस समय यही काम कर रहे हैं. यह सभी मान रहे हैं कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के भी सियासी समीकरण बदलेंगे और जरूरतों के हिसाब से लालू प्रसाद अपने फैसले ले सकते हैं. लेकिन इस समय बस तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा को गरम कर जितना फायदा उठाया जा सकता है, वह किया जा रहा है.

सरोज सिंह

कहते हैं राजनीति में कोई बात यूं ही नहीं कही जाती. हर एक बात में कोई न कोई राज पैवस्त होता है और सही समय आने पर इस राज से परदा उठ भी जाता है. सूबे बिहार में इन दिनों सत्ता की बिसात पर कुछ ऐसी गोटियां बिछाई जा रही हैं, जो किसी की किस्मत बनाने और किसी की बिगाड़ने की ताकत रखती है. तय मानिए कि बिसात पर पसरी ये गोटियां आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली हैं. सत्ता की राजनीति के बड़े कलाकार लालू प्रसाद इन दिनों काफी संभल-संभल कर ये गोटियां फेंक रहे हैं और बहुत ही धैर्य के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब वे शह और मात का खेल अपनी शर्तों पर खेल सकें. यह अलग बात है कि इस खेल के पहले राउंड में तगड़ा झटका लालू प्रसाद को ही लग गया है. सत्ता के शतरंज के इस खेल में लालू प्रसाद के दो बड़े राजनीतिक सेनापति शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव मात खाकर जेल की दिवारों के पीछे जा चुके हैं. अपने इन दोनों सबसे ताकतवर सेनापतियों का जेल चले जाना लालू प्रसाद के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है. राजद का ये दर्द इसलिए भी दिख रहा है, क्योंकि सूबे में 80 विधायक राजद के हैं और जद्यू के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है. लालू प्रसाद के रणनीतिकार ये मानते हैं कि ये दोहरा झटका माय समीकरण पर सुशासन का सर्जिकल स्ट्राइक है और अगर समय रहते इस हमले से नहीं उबरा गया, तो फिर माय का किला बचाना मुश्किल हो जाएगा. कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद भी मौटे तौर पर इस आकलन को समझते हैं और इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने ये चाल चली है. वे माय समीकरण को मजबूत करने के साथ-साथ तेजस्वी यादव का भी कद भी मजबूत करना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि पार्टी के अंदर और बाहर तेजस्वी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में अगर कभी मुख्यमंत्री के तौर पर संभावित विकल्प की बात हो तो केवल और केवल तेजस्वी यादव का चेहरा ही चमकता हुआ दिखे.

सूबे के अलग-अलग हिस्सों में राजद कोटे से सांसद बुलो मंडल, आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर, पार्टी विधायक सुरेंद्र यादव, विधायक भाई वीरेंद्र सहित कई विधायकों ने इस चर्चा को गरमाने का काम किया कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए. पहले ऐसा लगा कि ऐसे सांसद व विधायक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने अपना स्कोर बढ़ाने के लिए ऐसी चर्चाओं को गरम कर रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे चर्चा गरम होती गई, वैसे-वैसे साफ होने लगा कि ये चर्चा यूं ही नहीं है, बल्कि इस अकेले तीर से कई निशानों को भेदने की योजना है. यह अलग बात है कि जब-जब इस तरह की बातें सामने आईं, खुद तेजस्वी और लालू प्रसाद ने इसका खंडन करने में जरा भी देरी नहीं लगाई. हाल के विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को जायज ठहरा कर बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी. बिहार विधानमंडल परिसर में उन्होंने कहा कि

उनके बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की राजद नेताओं की मांग उचित है. उनका कहना था कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं और जनता भी इसकी मांग कर रही है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा. हालांकि, देर रात राबड़ी देवी अपने बयान से मुकर गईं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं. मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. चर्चा जब और जोर पकड़ने लगी तो संत रविदास जयंती समारोह में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाचा बताया और कहा, चाचा सीएम रहे हैं और रहेंगे. राजद के नेताओं को भावना में बहकर कुछ भी नहीं कह देना चाहिए. तेजस्वी यादव ने कहा, 'कुछ लोग महागठबंधन को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाते रहते हैं. भ्रम फैलाने वालों से सचेत रहने की जरूरत है. हमारी लड़ाई आरएसएस से है. भाजपा आरएसएस की अंग है. आज तक गरीबों और वंचितों को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है. कुछ लोगों की इच्छा नहीं है कि वंचित मुख्यधारा में आएं. एकजुट होकर ही अधिकार लिया जा सकता है. हमारा इनसे दर्द का रिश्ता है. हमलोगों ने दर्द सहा है. केंद्र में दलित विरोधी सरकार है.' यह अलग बात है कि तेजस्वी जिस कार्यक्रम में यह बोल रहे थे, उसी के मेन गेट पर इनका बड़ा पोस्टर लगा था, जिसपर लिखा था, 'बिहार को यही पसंद है.' इतने पर भी जब बात नहीं थमी, तो खुद लालू प्रसाद को मैदान में कूदना पड़ा. उन्होंने कहा, महागठबंधन में सीएम पद के लिए वैकेंसी ही नहीं, विवाद का कहां सवाल है. हां, उम्र के हिसाब से युवाओं का ही भविष्य है. लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं. अभी तेजस्वी यादव की उम्र सीएम बनने की नहीं है. वे खुद कहते हैं कि बहुत सीखना है. हमारी और नीतीश कुमार की तो उम्र हो चली है, भविष्य तो युवाओं का ही है. लालू प्रसाद चाहे कोई भी सफाई दें, लेकिन जदयू ने इसे बहुत ही हल्के में नहीं लिया है.

पूर्व मंत्री व बिहार विधानसभा में उपनेता श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और महागंठधन के नेता हैं. ऐसे तो सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो चाहे वे बोल सकते हैं. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश दिया है और इस सरकार में जनादेश का पूरा सम्मान किया जा रहा है. राजद के विधायक अपने दल के नेता के बारे में कुछ कहते हैं, तो यह इनकी पार्टी का अंदरुनी मामला है. जहां तक सरकार की बात है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का एजेंडा मजबूती से लागू किया जा रहा है. देश और दुनिया में इनकी प्रशंसा हो रही है. वहीं, कांग्रेस विधायक डॉ अशोक कुमार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मामला राजद का अंदरुनी मामला है. इस पर राजद को तय करना है. फिलहाल नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.

इन बयानों से बाहर निकलेंगे, तो दो बातें साफ तौर पर इन चर्चाओं की पृष्ठभूमि में नजर आएंगी. जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद के सामने दो बहुत बड़ी चुनौती है. पहला तो यह है कि समय रहते केवल पार्टी ही नहीं बल्कि राजद के वोटरों के सामने तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित कर दिया जाए. लालू प्रसाद चाहते हैं कि जिस तरह राजद में बिना इनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वैसे ही तेजस्वी यादव का कद इतना बड़ा कर दिया जाए कि उनकी बात ही पार्टी में पत्थर की लकीर हो जाए. लालू प्रसाद यह भी चाहते हैं कि यादवों और मुसलमानों यानि कि माय का जो सत्ता बनाउ वोट बैंक उन्होंने अपनी राजनीतिक तपस्या से तैयार किया है, उसका अगला मालिक तेजस्वी यादव ही बनें और वे जिस प्रत्याशी को भी चाहें, उसे ये वोट दिलवा सकें. लालू प्रसाद यह बात जानते हैं कि इन सपनों पर अमल करने के लिए जनता, खासकर अपने वोटरों को कुछ सपने तो दिखाने ही होंगे. इसलिए उन्होंने अपने साख समर्थकों के माध्यम से अपने वोटरों को यह बड़ा सपना दिखाना शुरू कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. इसका दोहरा फायदा लालू प्रसाद को मिल रहा है. पहला तो यह कि पार्टी के अंदर जो नाममात्र की नाराजगी थी, वह पलक झपकते ही खत्म हो गई. राजद का ही मुख्यमंत्री होगा यह सपना पार्टी के लिए रामबाण का काम कर रहा है. अपने वोटरों के बीच लालू प्रसाद अब खुद दौरे पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव को प्रमंडलीय दौरे पर भेज रहे हैं. तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे हैं और राजद के वोटरों से रूबरू हो रहे हैं. वोटरों के सुख-दुख में शामिल हो रहे हैं. वे वोटरों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैं ही हूं, जो लालू प्रसाद की तरह आपकी चिंताओं को दूर करूंगा. तेजस्वी यादव के इन दौरों को पूरा समर्थन भी मिल रहा है. राजद के नेता और वोटर इनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं और अपना सुख-दुख बांट रहे हैं. गया में तो राजद के समर्थकों ने एक नायक के तौर पर इनका स्वागत किया. लालू प्रसाद भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के कोने-कोने में जाकर राजद समर्थकों को यह अहसास दिलाएं कि लालू प्रसाद तो हैं ही, अब मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हूं. मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी के नाम की चर्चा से राजद के वोटरों का जोश दोगुना हो गया है. राजद समर्थकों को लग रहा है कि देर सबेर लालू प्रसाद अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा ही देंगे. शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव के जेल चले जाने के बाद राजद समर्थकों का जो जोश ठंडा पड़ रहा था, उसे बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चर्चा ने गरमा दिया है. तेजस्वी यादव की सभाओं में लगने वाले ओजस्वी नारे इस बात की गवाही देते हैं कि बहुत तेजी से राजद के वोटर यह मानने लगे हैं कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद के असली उत्तराधिकारी हैं और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.

पार्टी के अंदर तेजस्वी को मजबूत करने के बाद लालू प्रसाद के सामने दूसरी बड़ी चुनौती तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने की है. इसके लिए लालू प्रसाद ने कांग्रेस के अलावा कई छोटी-छोटी पार्टियों के प्रमुखों को अपना संदेशा भेजवा दिया है. ऐसा लगता नहीं है कि बहुमत के लिए 123 का जादुई आंकड़ा जुटाने में लालू प्रसाद को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि वे इस खेल के माहिर खिलाड़ी रहे हैं. हालांकि जानकार बताते हैं कि भले ही लालू प्रसाद 123 की कवायद में लगे हों, लेकिन वे अंदरखाने ये नहीं चाहते हैं कि मौजूदा सरकार के तानेबाने में कोई फेरबदल हो. हां, अगर नीतीश कुमार अपने कारणों से कमजोर होते हैं, तो फिर लालू प्रसाद अपना ऑपरेशन चालू कर देंगे. लालू प्रसाद अच्छी तरह समझ रहे हैं कि शराबबंदी और बेहतर प्रशासन के कारण नीतीश कुमार की छवि इस समय जनता के बीच काफी अच्छी है. हाल में पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार ने जितना बोल्ड कदम उठाया, उससे भी जनता के बीच उनकी एक कुशल और कठोर प्रशासक की छवि गई है. लालू प्रसाद समझते हैं कि सत्ता परिवर्तन का यह सही समय नहीं है, इसलिए दबाव और केवल दबाव की रणनीति ही इस समय कारगर है. लालू प्रसाद इस समय यही काम कर रहे हैं. यह सभी मान रहे हैं कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के भी सियासी समीकरण बदलेंगे और इस समय की जरूरतों के हिसाब से लालू प्रसाद अपने फैसले ले सकते हैं. लेकिन इस समय बस तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा को गरम कर जितना फायदा उठाया जा सकता है, वह किया जा रहा है. इधर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने कहा है कि राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक कामों में उनका ज्यादा मन लगता है. जानकार कहते हैं कि निशांत के इस बयान से लालू प्रसाद के, पुत्र आगे बढ़ाओं अभियान को नैतिक झटका लगा है. लेकिन लालू प्रसाद को जानने वाले बताते हैं कि इस तरह के बयानों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. लालू ने जो बात चर्चा में ला दी है, उसे दूर तलक जाना है. बिहार की राजनीति की हर नब्ज से लालू वाकिफ हैं और अपने सभी राजनीतिक ऑपरेशन की समय व तारीख वह अपनी रणनीति के हिसाब से तय करते हैं. इसलिए यह मानकर चलिए कि अभी कुछ दिनों तक बयान और फिर इसके खंडन का दौर चलेगा, लेकिन लालू के अभियान का यह अंतिम सत्य नहीं है. तेजस्वी यादव को लेकर लालू बेहद गंभीर हैं और सही समय आने पर वे खुद राज पर से परदा उठाने से परहेज नहीं करेंगे. ■

लालू प्रसाद के सामने दो बहुत बड़ी चुनौती है. पहला तो यह कि समय रहते केवल पार्टी ही नहीं बल्कि राजद के वोटरों के सामने तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित कर दिया जाए. लालू प्रसाद चाहते हैं कि जिस तरह राजद में बिना इनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वैसे ही तेजस्वी यादव का कद इतना बड़ा कर दिया जाए कि उनकी बात ही पार्टी में पत्थर की लकीर हो जाए. लालू प्रसाद यह भी चाहते हैं कि यादवों और मुसलमानों यानि कि माय का जो सत्ता बनाउ वोट बैंक उन्होंने अपनी राजनीतिक तपस्या से तैयार किया है, उसका अगला मालिक तेजस्वी यादव ही बनें और वे जिस प्रत्याशी को भी चाहें, उसे ये वोट दिलवा सकें. लालू प्रसाद यह बात जानते हैं कि इन सपनों पर अमल करने के लिए जनता, खासकर अपने वोटरों को कुछ सपने तो दिखाने ही होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

आतंक के आरोप से बाइज़्ज़त बरी

...लेकिन ज़िन्दगी सज़ा बन गई

तसीम अहमद

'मेरे जीवन के बेशक़ीमती 11 साल 3 महीने 26 दिन कौन लौटाएगा? यहां सब कुछ बदल चुका है. जेल से रिहा होने के बाद घर जाते हुए मुझे लग रहा था कि घर पर मेरे माता-पिता और भाई-बहन सब मेरा इंतेज़ार कर रहे होंगे. मैं अपनी मां से मिलने के लिए बेताब था. मैं अभी घर से कुछ दूरी पर था, उस समय मेरी नज़रें मेरी मां को तलाश रही थीं. घर के क़रीब पहुंचने पर देखा कि दरवाज़े पर एक बेहद कमज़ोर, लाचार बूढ़ी औरत खड़ी है. मैंने सोचा कि यह मोहल्ले की कोई वृद्ध होगी. मैं जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ा, दरवाज़े पर खड़ी वही बूढ़ी औरत बेटा-बेटा कहकर मेरे गले से लिपट गई और फूट-फूट कर रोने लगी. तब मुझे पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरी मां हैं. उस समय मुझे अहसास हुआ कि इन 12 वर्षों ने मेरे जीवन से बहुत कुछ छीन लिया है. जिस मां को मैं स्वस्थ और तंदरुस्त छोड़ कर गया था, वो अब एक ढांचे में बदल चुकी है. एक तो मेरे बिछड़ने का ग़म और फिर फालिज के हमले ने रही-सही कर पूरी कर दी. इसी प्रकार बाप को भी बेटे से बिछड़ने के ग़म ने दिल का मरीज़ बना दिया. गिरफ्तारी से केवल दो महीने पहले मेरे गॉलब्लाडर का ऑपरेशन हुआ था. मैं खुद भी शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था. फिर भी किसी प्रकार अपने कश्मीरी पारंपरिक ऊनी शॉल के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है. मेरे माता-पिता जिन समस्याओं और बीमारियों का शिकार हुए, क्या कोई वह घाव भर सकता है?'

'चौथी दुनिया' को यह दर्दनाक कहानी सुनाते-सुनाते 43 वर्षीय मोहम्मद हुसैन फ़ाज़ली की आवाज़ भरभरा गई. फिर उन्होंने साहस जुटाते हुए अपनी कहानी के शेष हिस्से को बताया. '21 नवंबर 2005 के उस लम्हे को मैं कभी नहीं भुला सकता. रात के लगभग 8 बजे ईशा की नमाज़ के बाद मैं अपने घर में शॉल बुन रहा था कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई. पुलिस की एक टीम ने यह कहते हुए कि दिल्ली धमाकों के सिलसिले में पूछताछ करनी है, मुझे अपनी साथ ले गई. मुझे दो-तीन दिनों तक कार्गो इन्वेस्टिगेशन में रखा गया और फिर आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस मुझे अपने साथ ले गई. पौने दो महीने तक पुलिस कस्टडी में रहते हुए मुझे तरह-तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ा. फिर मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया. यहां शुरू के दिनों में मुझे बेहद खूंखार कैदियों वाले सेल में रखा गया. यहां रोज़ाना डेढ़ किलोमीटर तक झाड़ू देना पड़ता था और गंदगी साफ़ करनी पड़ती थी. इस अवधि में परिवार वालों से कभी मुलाक़ात नहीं हुई.' दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी, केवल मोहम्मद हुसैन फ़ाज़ली की नहीं है. टाडा, पोटा और फिर 9/11 के बाद आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार होकर सबूतों की अभाव में अदालत से बरी किए गए ऐसे 100 बदनसीब युवाओं की लंबी सूची है, जिन्हें अपने निर्दोष होने की सज़ा भुगतनी पड़ी. जेल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न बर्दाश्त करना पड़ा. अपने जीवन के क़ीमती साल इन्हें जेल में गंवाने पड़े, कितनों के मां-बाप खोए, मुक़दमे लड़ने में घरबार बिक गए, रिहाई के बाद समाज में मान-सम्मान भी नहीं रहा. अब सवाल यह है कि ऐसे निर्दोष और मासूम लोगों के जेल में बर्बाद हुए क़ीमती दिन कौन लौटाएगा? क्या उस गुनाह के लिए जो इन्होंने किया ही नहीं, जेल में बरसों गुज़ारने के बदले इन्हें हर्जाना भी मिलेगा? क्या इनका पुनर्वास भी होगा? ये वो सवाल हैं, जो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ज़हन को परेशान करते हैं.

'चौथी दुनिया' को फ़ाज़ली से बातचीत के दौरान यह भी मालूम हुआ कि कश्मीर का कोई निर्दोष युवा रिहाई पाने के बाद अपने घर जाता है, तो वहां का समाज उसके साथ सहानुभूति और अपनेपन का इज़हार करता है, क्योंकि वहां सभी अपने आपको मज़लूम मानते हैं. जबकि देश के अन्य राज्यों में ये स्थिति नहीं है. 2012 में रिहा होने वाले मोहम्मद आमिर ने चौथी दुनिया को बताया कि जो दाग़ लग जाता है, उसका धुलना बहुत मुश्किल होता है. समाज उसे संदिग्ध नज़रों से देखता है. बहरहाल, फ़ाज़ली के सामने अब सबसे बड़ी समस्या अपने कारोबार को फिर से संगठित करने की है. फ़ाज़ली ने कहा, 'मैं आपके अख़बार के माध्यम से बस यह इच्छा व्यक्त करना चाहता हूं कि जो निर्दोष लोग जेल या पुलिस हिरासत में मारे गए हैं, वे तो मज़लूम बनकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िन्दगी की बहाली और रिहाई के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए.'

गौरतलब है कि अभी हाल ही में मोहम्मद हुसैन फ़ाज़ली के साथ मोहम्मद रफ़ीक़ शाह को 16 फरवरी 2017 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया. 29 अक्टूबर 2005 को हिन्दुओं के भव्य पर्व दीवाली के समय दिल्ली के सरोजनीनगर मार्केट, पहाड़गंज और दक्षिणी दिल्ली में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोप से कोर्ट ने इन्हें बरी किया. कोर्ट ने तीसरे आरोपी तारिक डार को 10 वर्ष की सज़ा सुनाई है. हालांकि डार पहले ही 11 वर्ष की सज़ा काट चुका है. इसलिए अदालत ने उसकी सज़ा को पूरा मान लिया. इन तीनों युवाओं का संबंध कश्मीर से है. मोहम्मद हुसैन फ़ाज़ली को 21 नवंबर 2005 में जब गिरफ्तार किया गया, तो उस समय उनकी उम्र 31 वर्ष थी, जबकि अब उनकी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है.

उनके साथ जेल में बंद होने वाले मोहम्मद रफ़ीक़ शाह का भी यही हाल है. वे उस समय केवल 22 वर्ष के थे, जब उन्हें शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया. अब उनकी उम्र 34 वर्ष हो चुकी है. इनकी कहानी भी फ़ाज़ली से कम दर्दनाक नहीं है. लगभग 12 वर्षों बाद निर्दोष साबित होने वाले गंदार ज़िले के मोहम्मद शाह ने भी 'चौथी दुनिया' को बताया, '21-22 नवंबर 2005 की अर्द्धरात्रि के लगभग पौने ग्यारह बजे स्पेशल सेल के लोग मेरे घर आए. तब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमए अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था. जिस समय पुलिस आई, मैं पढ़ाई कर रहा था. पुलिस मुझे वहां से यह कहकर ले गई कि पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है. वहां से मुझे कागों इन्वेस्टिगेशन में ले जाया गया और लगभग डेढ़ महीने तक पुलिस ने मुझे अपनी कस्टडी में रखा. इस दौरान एक आरोपी को जिस शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, वो तो मुझे सहना ही पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी और पीड़ादायक बात यह थी कि कश्मीरी और मुसलमान होने के कारण पुलिस के ज़हरीले शब्द मेरे दिल को छलनी कर देते थे. इसके बाद मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां मेरी ज़िंदगी के क़ीमती साल बर्बाद हो गए. यहां तीन-चार महीने पर मेरे माता-पिता मुझसे मिलने आया करते थे.'

शाह का कहना है कि रिहाई के बाद सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा हूं और सभी ज़िम्मेदारियां मुझे अकेले ही पूरी करनी हैं. मेरे पिता फॉरेस्ट में कर्मचारी थे, उन्हें जो पेंशन मिलती है, अब उसी पर गुज़र बसर होता है. मैं अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहता हूं, लेकिन यह कैसे संभव होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा. उन्होंने यह भी बताया कि रिहाई के बाद यहां समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया. इसका कारण यह है कि कश्मीर के सभी लोग खुद को पीड़ित समझते हैं और वे दूसरे पीड़ितों के दर्द को महसूस करते हैं. यही वजह है कि रिहाई के बाद से लोग मुझसे निरंतर मिलने आ रहे हैं और मुझसे हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं.

9/11 के बाद 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके बाद से देश में मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी का नया दौर शुरू हुआ.

पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, इनपर मुकदमे चलते हैं और फिर इनमें से बहुत से अपर्याप्त सबूत की बुनियाद पर रिहा हो जाते हैं. प्रसिद्ध पत्रकार और ऐंकर रवीश कुमार ने एक बार जमीअत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से पूछा कि आख़िर कब तक आप इन्हें छुड़ाते रहेंगे और पुलिस इन्हें जेलों में बंद करती रहेगी? तो मौलाना ने जवाब दिया कि हम मज़लूमों का हौसला बनाये रखने के लिए इस काम को जारी रखेंगे. निश्चित ही मौलाना और उन सभी संगठनों का काम सराहनीय है, जो इन निर्दोषों के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तार किए गए नौजवान, जो नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर रिहा कर दिए जाते हैं और जिसके बाद उनकी बाक़ी ज़िंदगी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से नकारा बनकर रह जाती है, इसका सरकार के पास क्या हल है?

संसद में पेश की गई एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए युवाओं की संख्या 1,151 है. ज़ाहिर सी बात है कि इन गिरफ्तार होने वालों में जो प्रभावशाली हैं, वे खुद अपने मुकदमे लड़ रहे हैं और जो ग़रीब हैं, वकीलों की फीस और अन्य खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके मुक़दमों की अनुशंसा और सहयोग कई संगठन कर रहे हैं, जिनमें जमीअत उलेमा-ए-हिन्द (अरशद), जमीअत उलेमा हिन्द (महमूद), रिहाई मंच, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन, एपीसीआर और कुछ अन्य संगठनों के नाम शामिल हैं. इन संगठनों के प्रयासों से अब तक सैकड़ों युवाओं की रिहाई हो चुकी हैं. जिनकी रिहाई नहीं हो सकी है, उनके लिए कोशिशें जारी हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आख़िर न करने वाले गुनाहों की सज़ा का यह सिलसिला कब और कैसे बंद होगा?■

क्या कहती हैं चर्चित हस्तियां?

'चौथी दुनिया' ने मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोगों से बातचीत की और उनसे अदालत के हालिया निर्णय के बारे में सवाल पूछे, जिनके अंश प्रस्तुत हैं-

दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मुक़दमे में जो निर्णय आया है, वो कोई नया नहीं है. ऐसे निर्णयों से यह बात मज़बूत हो जाती है कि आतंकवाद के नाम पर फ़र्ज़ी आरोपों पर मुस्लिम युवाओं को पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से वे वर्षों जेलों में बंद रहते हैं और पर्याप्त सबूत न होने पर अदालत उन्हें बरी कर देती है. इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है कि आख़िर उन्हें फ़र्ज़ी आरोपों में क्यों गिरफ्तार किया जाता है और उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मुक़दमे के बरी किए गए तीनों लोगों को ही नहीं बल्कि पूर्व में भी बरी हुए ऐसे लोगों को हर्जाना मिलना चाहिए और इनका पुनर्वास होना चाहिए.

-हर्षमंदर, डायरेक्टर, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ और अध्यक्ष, अमन बिरादरी

यह अफसोसनाक ही नहीं, एक सभ्य समाज और देश के लिए बेहद शर्मनाक भी है. न किए जाने वाले गुनाहों की सज़ा वर्षों तक कुछ लोगों को काटनी पड़ती है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज़िंदगी के क़ीमती दिन इनसे छीन लिए गए, जिसे लौटाया नहीं जा सकता है, न ही इसके मुआवज़े की कोई बात होती है. कश्मीर के ये नौजवान कितने बदनसीब हैं कि इन्हें सब कुछ खोना पड़ा. मान-सम्मान, ज़िंदगी के क़ीमती दिन, सब कुछ चला गया. अब वे जाएं तो कहां जाएं? मुआवज़ा और पुर्नवास के लिए क्रिमिनल जस्टिस में संशोधन किया जाना चाहिए. ऐसी परंपरा अन्य देशों में पाई जाती है.

-डॉ. मनोज कुमार झा, प्रोफेसर सोशल वर्क, दिल्ली यूनिवर्सिटी

न्यायपालिका की भूमिका अच्छी है. निर्दोष और मासूम लोग बरी होकर बाहर आ जाते हैं. दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट के ये आरोपी, न करने वाले गुनाहों की सज़ा काटकर बाहर आ गए, लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश के क़ानून का यह रवैया अन्य मामलों की तरह इन्हें मुआवज़ा दिलवाने और पुनर्वास के मामले में अलग क्यों रहता है? इंसाफ़ की यह लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, ताकि आगे से कोई मासूम फ़र्ज़ी आरोपों की बुनियाद पर गिरफ्तार न हो सके और उसे वर्षों तक न करने वाले गुनाह की सज़ा न काटनी पड़े.

- अपूर्वानन्द , हिन्दी विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी

अदालतें अपर्याप्त सबूतों की बुनियाद पर नौजवानों को रिहा करती हैं, निश्चित ही यह खुशी की बात है, लेकिन इससे इनका इंसाफ पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि इंसाफ़ के साथ अफसोस और भरपाई का पहलू शामिल न हो. यानि जिस समय इन्हें बरी किया जाता है, अफसोस भी ज़ाहिर होना चाहिए कि उनके साथ जो कुछ हुआ, वो सिस्टम की गलती की वजह से हुआ. दूसरा यह कि सिस्टम की इस गलती की भरपाई हो. यह भरपाई मुआवजा, रोज़गार, पुनर्वास व अन्य रूप से भी हो सकती है. जब तक ये तीनों चीज़ें समान हों, यानि अफसोस का इज़हार, भरपाई की अनिवार्यता और इंसाफ़, उस समय तक किसी भी इंसाफ़ को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता.

- मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी, सचिव, जमीअत उलेमा-ए-हिन्द

दिल्ली की विशेष अदालत से बाइज़्ज़त बरी होने के बाद एक लंबे समय तक जेल में क़ैद रहने की पीड़ाओं से रिहाई हासिल करते हुए कश्मीर के नौजवान वापस अपनी खूबसूरत घाटी में पहुंच गए, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ. यकीनन गुज़रे हुए 12 वर्ष उन्हें एक खौफनाक ख्वाब की तरह परेशान कर रहे होंगे. संभव है, वे ख्वाब कभी आंखों से ओझल हो जाएं, इसलिए वे सोई हुई कौम के लिए कुछ उलझे हुए सवाल यकीनन छोड़ गए हैं. कश्मीर की समस्या एक अलग मसला हो सकती है. लिहाज़ा, हमारे देश व हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन और सर्वैधानिक स्वतंत्रता का अवैध इस्तेमाल हमारे समाज के लिए चिंता व गंभीर बहस का विषय क्यों नहीं बनते? इनके बेगुनाह साबित होने पर जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की आवाज़ क्यों नहीं उठती? इनके क़ीमती दिन, जो जेलों में गुज़र जाते हैं, उनके मुआवज़े के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती?

-एडवोकेट अबूबकर, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शइन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर)

होशंगाबाद, मध्य प्रदेश

तरक़्क़ी नहीं बर्बादी लाएगा कोका कोला प्लांट

कुमार कृष्णन

कौन नहीं चाहता कि राज्य फले-फूले, विकास हो, रोजगार बढ़े और समृद्धि आए, लेकिन यह भी सोचना ही पड़ेगा कि किस कीमत पर ऐसा किया जाना चाहिए. मध्यप्रदेश सरकार एक तरफ जहां जनभागीदारी के साथ नमामि देवी नर्मदे यात्रा कर रही है, वहीं ठीक इसके उलट जनता के हिस्से के पानी को बहुराष्ट्रीय कंपनी के हवाले किया जा रहा है. होशंगाबाद जिले के बाबई के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में कोकाकोला कंपनी के मेगा प्लांट की आधारशिला रखने का काम शिवराज सरकार के उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ला के द्वारा किया गया. साथ ही यह दावा किया गया कि इस प्लांट के लगने से क्षेत्र के 500 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा और इसके पांच गुना लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे. इस प्लांट की लागत 750 करोड़ है. होशंगाबाद जिले के बाबई में और खासकर नर्मदा के समीप इस प्लांट के स्थापित होने से स्थानीय लोग नर्मदा के संभावित प्रदूषण और जीवन जीने के आधार जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ खेती-किसानी के खत्म होने को लेकर भयभीत हैं. लिहाजा इसका विरोध आरंभ हो गया है. कारण यह कि नर्मदा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. लोगों का कहना है कि नर्मदा मैया हम सब की आस्था की केंद्र और जीवनदायिनी हैं और इसे किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं होने देंगे और खेती बर्बाद नहीं होने देंगे.

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील में भाजपा सरकार मुहासा औद्योगिक क्षेत्र बना रही है, जिसमें सरकार की तरफ से कोका कोला कम्पनी को 110 एकड़ जमीन दे दी गई है. कोका कोला कम्पनी यहां नर्मदा से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी निकालेगी और कोल्डड्रिंक बनाएगी. इससे न सिर्फ नर्मदा के पानी में कमी आएगी, बल्कि फैक्ट्री का अनुपयोगी पानी, कचरा व अन्य रासायनिक पदार्थ नर्मदा में जाएंगे, जिससे नर्मदा प्रदूषित होगी. इन सब से अविरल और निर्मल नर्मदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, साथ ही जल और भूमि दोनों बर्बाद होंगे और किसानी पर भयंकर संकट आएगा. बाबई मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जहां हजारों आम के पेड़ मौजूद हैं. मजे की बात यह है कि जब इसी बाबई को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के द्वारा रिलायंस कंपनी को सौंपे जाने की योजना बनाई जा रही थी, तो भाजपा के विधायकों और खासकर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के द्वारा विधानसभा में इसका कड़ा विरोध किया गया था. दिग्विजय सिंह सरकार के इस कदम के विरोध में भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन किया था. लेकिन अब जब भाजपा सत्ता में हैं, तो उसी बाबई के फार्म हाउस को औद्योगिक क्षेत्र बनाकर

वहां कोका कोला का प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है.

कोका कोला प्लांट के शिलान्यास के करीब डेढ़ महीने बाद स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हो गया है. सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय हंका बताते हैं कि मोहासा और गुराडिया मोती पंचायत में कंपनी के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं. मुहासा के 10 गांवों में लोगों का विरोध सामने आने लगा है. लोगों का तर्क है कि इसमें नर्मदा नदी से पानी लिया जाएगा और प्रतिदिन 18 लाख लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा. एक लीटर कोल्डड्रिंक बनाने में पांच लीटर पानी की बर्बादी होगी. बचे हुए रसायनिक पानी को बहा दिया जाएगा. इससे क्षेत्र की खेती और नर्मदा नदी दोनों प्रभावित होंगे. इसके विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है. लोगों का कहना है कि सरकार का यह दावा सच्चाई से कोसो दूर है कि यहां फैक्ट्री लगाने से रोजगार मिलेगा. मण्डीदीप, मालनपुर और पीथमपुर जैसे कई उदाहरण हैं, जहां कहा तो गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

कई साल पहले भोपाल के पास पीलूखेड़ी में भी कोका कोला का प्लांट लगा था, वहां आज पार्वती नदी सूख चुकी है. किसान परेशान और खेती बर्बाद हो रहे हैं. अब मोहासा का भी हाल पीलूखेड़ी जैसा न हो इसके लिए स्थानीय नागरिकों अक्षय हंका, विक्रांत राय, लक्ष्मी नारायण सोनी, मुकेश तिवारी, कुलभूषण पारासर, संजय मिश्रा आदि ने बीड़ा उठाया है. उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, कोका कोला की फैक्ट्री यहां नहीं लगने देंगे. अपनी जमीन और अपनी नर्मदा को बर्बाद नहीं होने देंगे. इस आंदोलन की शुरुआत 16 फरवरी 2017 को बन्द्रमान गांव से की गई. बन्द्रमान, सांगाखेड़ा, आरी और मुहसा गांव में जन संपर्क किया गया और लोगों को कोका कोला फैक्ट्री के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया.

केंद्र सरकार के सेंटर ग्राउंड वॉटर बोर्ड के कई आंकड़े भी कोका कोला प्लांट के भूजल दोहन पर सवाल खड़े करते हैं. लेकिन सरकार का वरदहस्त प्राप्त इस कंपनी के खिलाफ आम लोगों की लड़ाई आसान नहीं है. इसमें एक ओर वंचित हैं और दूसरी ओर ताकतवर. प्लांट लगाने के लिए तैयार कंपनी किसी भी तरह से ये गारंटी नहीं दे रही है कि वह भूजल का दोहन नहीं करेगी और पानी की किल्लत नहीं होने देगी या उसके प्लांट से कोई स्लज (अपशिष्ट) नहीं निकलेगा. अगर ऐसा हुआ तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी. कोला कंपनी ने मध्य प्रदेश में पहुंचकर एक तरह से अपने लिए भूजल का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन उन लोगों का क्या होगा, जो नदी के पास रहते हैं, लेकिन उनके कंठ सूखे और खेत खाली हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूजल दोहन को लेकर विवादों में रहा है कोका कोला

केरल के प्लाचीमाड़ा प्लांट से लेकर उत्तरप्रदेश में वाराणसी के मेंहदीगंज तक कोका कोला कंपनी अपने प्लांटों को लेकर सवालों और विवादों में रही है. उस पर भू जल के अत्याधिक दोहन और स्थानीय पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को भी असंतुलित करने के आरोप हैं. केरल का उसका इतिहास तो पारिस्थितिकी के क्षरण की दहलाने वाली दास्तान है. जहां कोका कोला ने स्थानीय पारिस्थितिकी और खेती को लगभग तबाह कर दिया. इस मामले में हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा था, फिर कंपनी ने भारी मुआवजा दिया और प्लांट भी बंद करना पड़ा. लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. कोका कोला ने वहां पानी की जो माइनिंग की उसमें 15 लाख लीटर पानी हर रोज अपने प्लांट के लिए निकालती थी. यह एक तरह से धरती को पानी से खाली कर देने जैसा था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पानी न तो कोका कोला का है और न ही राज्य सरकार का, जो कंपनी को प्लांट लगाने की मंजूरी देती है. जांच में यह भी सामने आया कि प्लांट से कई जानलेवा रसायनों का रिसाव होता था. क्रोमियम, लेड और कैडमियम जैसे पदार्थों की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई थी. वाराणसी के प्लांट में तो 1999 से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जब कोका कोला ने अपना प्लांट लगाया था. ■

बीएमसी चुनाव: एमआईएम की शानदार पारी

शाहिद नईम

महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जबरदस्त जीत दर्ज की तो वहीं, ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) ने भी शानदार पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया. खुद को धर्मनिरपेक्षता की ध्वजवाहक कहने वाली पार्टियां कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) इस चुनाव में ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं. इससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से जनता में घोर निराशा है.

एमआईएम के प्रदर्शन का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह पार्टी हैदराबाद से निकलकर धीरे-धीरे महाराष्ट्र की ज़मीन पर मज़बूती के साथ अपने क़दम जमा रही है और अन्य राज्यों में भी एंट्री की कोशिश में लगी हुई है. इसके कार्यकर्ताओं में गज़ब का उत्साह है. मुसलमानों में, विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं में इसकी लोकप्रियता में दिन-प्रतिदिन इज़ाफ़ा हो रहा है. सच्चाई यह भी है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम को केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस और भाजपा विरोधी लहर नसीब नहीं हुई. यह पार्टी वार्ड स्तर पर अपनी ज़मीन तलाश कर रही है. इसके विरोधी भी अब स्वीकारने लगे हैं कि एमआईएम को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

एमआईएम ने 2012 में पहली बार महाराष्ट्र की ज़मीन पर क़दम रखा और नांदेड़ नगरपालिका के चुनावों में हिस्सा लेते हुए 11 सीटें जीत कर सबको हैरान कर दिया. इसके बाद एमआईएम ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया और दो सीटें जीतकर महाराष्ट्र की सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. 2015 में एमआईएम ने औरंगाबाद नगरपालिका में 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जिनमें से 26 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और इसप्रकार अप्रत्याशित रूप से एमआईएम औरंगाबाद नगरपालिका में दूसरी बड़ी पार्टी बन कर उभरी. इस चुनाव में एमआईएम ने 15 उम्मीदवार मुस्लिम बहुल वार्डों और 12 उम्मीदवार दलित बहुल वार्डों में उतारे थे. इनमें से 21 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ-साथ पांच दलित उम्मीदवार भी कॉरपोरेटर बन गए. उल्लेखनीय है कि यहां धर्मनिरपेक्षता का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस महज़ 10 सीटों पर ही सिमट गई. इसके 8 मुस्लिम और 2 दलित उम्मीदवार ही कामयाब हो सके, जबकि एनसीपी केवल 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी. इसके अलावा, दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरी तरह से सफ़ाया हो गया. इसके बाद 2015 में ही कल्याण डमबोली नगरपालिका के चुनावों में एमआईएम ने 4 सीटें जीतकर अपने विरोधियों की नींद उड़ा दी. इन सभी सफलताओं से उत्साहित एमआईएम 2017 के महाराष्ट्र महानगरपालिका के चुनावों में उतरी और उसे शानदार कामयाबी हासिल हुई. इन चुनावों में एमआईएम के 26 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिनमें 22 मुस्लिम और 4 गैर मुस्लिम कॉरपोरेटर्स चुने गए. इन आंकड़ों को देखते हुए सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एमआईएम केवल मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, बल्कि वो सामाजिक एकता और अंबेडकर आंदोलन पर भी भलीभांति काम कर रही है. जिससे तथाकथित धर्मनिर्पेक्ष पार्टियों का बेचैन होना स्वदभाविक है.

हालिया चुनावों में अमरावती नगरपालिका में एमआईएम को आश्चर्यजनक सफलता मिली. यहां उसने 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, जिनमें से 11 उम्मीदवार सफल हुए. चुने गए कॉरपोरेटर्स में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ-साथ एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार कांबली भी शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि यहां कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि एनसीपी का पूरी तरह सफाया हो गया. हालांकि 2012 में अमरावती कॉरपोरेशन पर कांग्रेस और एनसीपी का क़ब्ज़ा था, लेकिन 2017 में यहां भाजपा क़ाबिज़ हो गई. यही स्थिति शोलापुर नगरपालिका में सामने आई. 2012 में शोलापुर नगरपालिका पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा था, लेकिन हालिया चुनावों में वो महज़ 14 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी और एनसीपी को केवल 4 सीटों पर सब्र करना पड़ा. शोलापुर में पहली बार चुनाव लड़ने वाली एमआईएम ने केवल 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें 9 सफल

(वीएमसी) में 2 सीटें, अकोला कॉरपोरेशन में एक सीट और एक सीट पुणे कॉरपोरेशन में जीती. पुणे कॉरपोरेशन की सीट एक ईसाई उम्मीदवार अश्विनी लांगड़े ने जीती.

एमआईएम के बारे में आम राय यह है कि वो केवल और केवल मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम से पता चलता है कि एमआईएम ने मुसलमानों के साथ-साथ इसाईयों और दलितों में भी गहरी पैठ बना ली है. यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाली कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र कॉरपोरेशन चुनावों में अपनी हार का ठीकरा एमआईएम के सर पर फोड़ रही हैं, लेकिन वे अपने गिरेबां में नहीं झांक रही हैं कि आख़िर उनका वोट बैंक एक नई पार्टी की ओर क्यों शिफ्ट हो रहा है?

दरअसल, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियों ने मुसलमानों की समस्याओं में कभी रूचि ही नहीं ली. वो भाजपा और आरएसएस का भय दिखाकर मुसलमानों के वोट प्राप्त करती रहीं और राज करती रही हैं. हद तो यह है कि अपने लंबे शासन काल के दौरान वे मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध नहीं करा सके. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसी मूल सुविधाएं भी उनके लिए सपना साबित हुईं, जिसके नतीजे में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई. यही वजह है कि मुसलमान अब धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जाल से निकलकर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में अपना भविष्य तलाश करने लगे हैं.

इस संबंध में चौथी दुनिया ने औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से एमआईएम के विधायक इम्तियाज़ जलील से बात की और उनसे पूछा कि क्या महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन चुनावों में एमआईएम ने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को नुक़सान और साम्प्रदायिक पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि एमआईएम के चुनावों में हिस्सा लेने से यदि किसी पार्टी को नुक़सान हुआ या किसी को फ़ायदा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. ज़ाहिर है कि हम किसी पार्टी की मसाज करके उसे सुकून पहुंचाने के लिए तो चुनाव नहीं ही लड़े हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके वजूद से पैदा होने वाली शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लंबी अवधि तक मुसलमानों को मूर्ख बनाकर राज किया और उनकी समस्याओं में भी दिलचस्पी नहीं ली. उन्होंने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्षता का बोझ आख़िर मुसलमान ही क्यों उठाएं, धर्मनिरपेक्ष तो हिन्दू भी हैं. वे अब धर्मनिरपेक्षता का बोझ क्यों नहीं उठा रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं. ज़ाहिर है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता को नहीं ठग सकतीं.

हक़ीक़त में, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोटों के बंटवारे के लिए आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए और गंभीरता के साथ अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आख़िर उन्हें एक के बाद एक चुनावों में शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जहां तक धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का एमआईएम पर वोटों के बंटवारे का आरोप है, वो गले से नहीं उतरता क्योंकि महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन चुनावों में एमआईएम बहुत कम सीटों पर लड़ी है और उसने अपने उम्मीदवार केवल मुस्लिम बहुल वार्डों में ही उतारे हैं, तो फिर बाकी वार्डों में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की क्यों हार हुई? आख़िर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का धर्मनिरपेक्ष हिन्दू और विशेष रूप से मराठा वोट बैंक कहां गया? ज़ाहिर है, धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाली पार्टियां आपसी फूट का शिकार हैं. जनसमस्याओं को हल करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है. मुसलमानों के प्रति इन्होंने हमेशा ही उपेक्षा बरती और उन्हें वोट बैंक से अधिक महत्व नहीं दिया. यही कारण है कि जनता अब धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से दूर होती जा रही हैं. लिहाज़ा, समय आ गया है कि ये पार्टियां एमआईएम पर वोटों के विभाजन का आरोप लगाने के बजाय, अपने गिरेबां में झांके और तथ्यों को समझे. अगर वे ऐसा नहीं करती हैं, तो बहुत देर हो जाएगी और समय इनके हाथ से निकल जाएगा, फिर दूसरी पार्टियां इनकी जगह ले लेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोमेंटम झारखंड

कब विकास में बदलेगा 'मोमेंट'!

रघुवर दास आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि झारखंड निवेश के मामले में पूरे देश में इतिहास रचेगा. पूरे राज्य में औद्योगिक माहौल बना है और सरकार औद्योगिक घरानों के साथ हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. निवेशकों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर विभाग तत्पर है. मुख्यमंत्री का मानना है कि इस बार हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. निवेशकों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है और उनलोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया जाएगा. अधिकारियों को भी इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं और कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

प्रशान्त शरण

झारखंड में हुए निवेशकों के सम्मेलन की सफलता से मुख्यमंत्री रघुवर दास अतिउत्साहित नजर आ रहे हैं. 'मोमेंटम झारखंड' में 210 कंपनियों के द्वारा 3 लाख 11 हजार करोड़ से अधिक के निवेश का एमओयू साइन हुआ. मुख्यमंत्री का दावा है कि इस सफल कार्यक्रम से झारखंड ने पूरी दुनिया में अपनी छवि बदली है, निवेशक गदगद दिखे और उन्होंने निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. मेक इन इंडिया में झारखंड की अहम भूमिका होगी, क्योंकि झारखंड अपनी सरल नीतियों और संसाधनों के साथ बदलाव की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है. हालांकि यहां की जनता में अभी भी कोई उम्मीद नहीं जगी है. आम लोगों का यह मानना है कि इससे पूर्व अर्जुन मुंडा एवं हेमन्त सोरेन की सरकार ने भी लगभग चालीस लाख करोड़ का एमओयू किया था, मित्तल जैसे उद्योगपतियों के साथ उद्योग लगाने के लिए करार हुआ था, लेकिन एक भी उद्योग जमीन पर नहीं उतर सका और न ही लोगों को रोजगार मुहैया हो सका. इसीलिए लोगों का मानना है कि 'मोमेंटम झारखंड' भी एक हसीन सपना है. अंतर सिर्फ इतना है कि पहले यह सपना अर्जुन मुंडा एवं हेमंत सोरेन ने दिखाया था और अब रघुवर दास यह सपना दिखा रहे हैं. वैसे झारखंड में उद्योग लगाना एक बड़ी चुनौती है. सबसे बड़ी चुनौती तो जमीन की उपलब्धता ही है. अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू है और इस वजह से कंपनियों को जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होती है. आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले अभी से ही शोर मचाने लगे हैं कि अगर ये कंपनियां झारखंड आईं, तो आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से तो वंचित होना ही होगा. लगभग तीस लाख से भी अधिक लोगों को पलायन का दंश झेलना पड़ेगा और आदिवासी जमीन विहीन हो जाएंगे. ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए और उद्योगपतियों को जमीन कैसे मुहैया कराई जाए. दरअसल, इससे पूर्व अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में मित्तल एवं अंबानी समूह ने जब सरकार के साथ एमओयू कर उद्योग बिठाने के लिए जमीन की तलाश शुरू की, तो इनलोगों को जमीन ही नहीं मिला. राज्य सरकार भी इनलोगों को जमीन नहीं दिला सकी, फलतः इन बड़े औद्योगिक घरानों ने झारखंड में उद्योग बैठाने की अपनी योजना ही रद्द कर दी. कई अन्य औद्योगिक घरानों के सामने भी यह समस्या आई.

राज्य सरकार ने देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्न महानगरों में रोड शो किया, विदेशों में भी रोड शो हुए, साथ ही निवेशकों के साथ कई बैठकें हुईं. उद्योगपतियों को झारखंड में प्रचुर खनिज संपदा के साथ ही बुनियादी चीजों की उपलब्धता बताई गई. राज्य सरकार ने निवेशकों को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा. 16-17 फरवरी को 'मोमेंटम झारखंड' का आयोजन किया गया. टाटा, रिलायंस, बॉम्बे-डाइंग एवं देश के जाने-माने उद्योगपति सहित 11 हजार से अधिक निवेशकों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें 600 से भी अधिक विदेशी निवेशक थे. इस आयोजन के लिए रांची को दुल्हन की तरह सजाया गया था. आयोजन की सफलता के लिए सरकारी खजाने से लगभग पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए. जाहिर है कि अगर रघुवर सरकार की यह योजना सफल रही, तो लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा एवं पूरे राज्य में विकास की बयार बहेगी. इस सम्मेलन में 210 कंपनियों ने लगभग चार लाख करोड़ के निवेश पर एमओयू किया. 'मोमेंटम झारखंड' के बाद व्यवसायिक जगत में दो-तीन शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं. ये संकेत अगर बरकरार रहे, तो निवेशकों के लिए झारखंड एक बेहतर मुकाम साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि निवेशकों को कोई समस्या नहीं आने दें और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाए.

रघुवर दास आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि झारखंड निवेश के मामले में पूरे देश में इतिहास रचेगा. पूरे राज्य में औद्योगिक माहौल बना है और सरकार औद्योगिक घरानों के साथ हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. निवेशकों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर विभाग तत्पर है. मुख्यमंत्री का मानना है कि इस बार हुए एमओयू को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. निवेशकों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है और उनलोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया जाएगा. अधिकारियों को भी इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं और कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वे स्वयं हर माह हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे. सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा. विपक्षी पार्टियों खासकर झारखंड नामधारी पार्टियों पर हमला बोलते हुए रघुवर दास ने कहा कि आदिवासियों का विकास नहीं चाहने वाले ही आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं. इनलोगों को भय है कि अगर आदिवासियों का विकास हो जाएगा, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी. उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार भाजपा समर्थक उद्योगपतियों को झारखंड में स्थापित करना चाहती है. विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की अस्मिता एवं संस्कृति की पहचान है, लेकिन भाजपा सरकार आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने पर उतारू है. एक साजिश के तहत विकास के नाम पर जमीन लूटकर उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, इसके कारण आदिवासियों की पहचान मिट जाएगी और तीस लाख से भी अधिक आदिवासी परिवार बेघर हो जाएंगे और उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी. उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में जमीन देने के लिए ही सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन किया गया है. इस संशोधन का पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है और राजनीतिक दल एवं कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.

वैसे रघुवर सरकार ने 'मोमेंटम झारखंड' को तो सफल बना दिया, पर अब अधिकारियों की बारी है. हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि थोड़ी सी अनदेखी हुई, तो परिणाम नकारात्मक होगा, वैसा ही जैसा पूर्व में हुए डेरों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हुआ था. राज्य के लोग खासकर व्यापार जगत पूर्व के एमओयू की असफलता को भूल नहीं पाया है और यही बात है कि इस बार भी इसकी सफलता को लेकर लोगों के मन में एक आशंका है. निवेश के लिए पहली आवश्यकता है, जमीन की उपलब्धता और यह फिलहाल सरकार के पास नहीं है. आमलोगों से जमीन लेने में व्यापक पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ता है. कंपनियां अगर खुद जमीन लेने की कोशिश करती है, तो उसे विरोध एवं गंदी राजनीति का सामना करना पड़ेगा. झारखंड में पहले भी निवेश की कई कोशिशें हुईं, पर इसका परिणाम गड़बड़ ही रहा है. अभिजीत और एस्सार ग्रुप इसके ताजा उदाहरण है. 'मोमेंटम झारखंड' में तीन लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. इनमें से कुछ भी कंपनियां अगर निवेश करती हैं, तो यह झारखंड के लिए बड़ी बात होगी और रघुवर सरकार के लिए भी उपलब्धि. अब देखना है कि झारखंड में इस बार एमओयू जमीन पर उतरता है या फिर इस बार भी पहले की तरह ही कागजों में सिमट कर रह जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

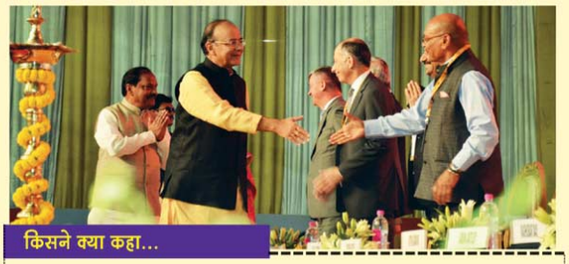

किसने क्या कहा...

ज़मीन की कोई कमी नहीं होगी - रघुवर

मुख्यमंत्री रघुवर दास पूरे आत्मविश्वास के साथ यह दावा कर रहे हैं कि उद्यमियों को जमीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. हर तरह के उद्योगों के लिए जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है. औद्योगिक घरानों को जमीन की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए लैण्ड बैंक की स्थापना की गई है. सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन आदिवासियों, मूलवासियों के हित में किया गया है. इस संशोधन के तहत आदिवासियों की जमीन भी नहीं बिकेगी और उनलोगों को जमीन के एवज में पैसा भी मिलता रहेगा.

मेक इन इंडिया में झारखंड की अहम भूमिका होगी- वैंकैया नायडू

'मोमेंटम झारखंड' में शिरकत करने आये केन्द्रीय मंत्री वैंकैया नायडू का मानना है कि मेक इन इंडिया की सफलता में झारखंड की अहम भूमिका होगी, क्योंकि झारखंड अपनी नीतियों के कारण तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, झारखंड बीमारू प्रदेश से विकास की ओर अग्रसर होता हुआ प्रदेश बन गया है. झारखंड में खनिज एवं वन संपदा की प्रचुरता है और यहां के लोग मेहनती हैं, ऐसे में झारखंड के विकास में संदेह की गुंजाईश ही कहां बनती है.

नए भारत का हिस्सा बनेगा झारखंड - रतन टाटा

टाटा समूह के रतन टाटा ने कहा कि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं. यहां वह हर चीज है, जो किसी औद्योगिक घराने को चाहिए. 'मोमेंटम झारखंड' के आयोजन से ऐसा अहसास हुआ कि झारखंड नए भारत का हिस्सा बनने को तैयार है. झारखंड खनिज संपदा के मामले में समृद्ध है और राज्य सरकार भी निवेशकों के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है, इसलिए औद्योगिक घरानों को झारखंड जैसे राज्यों के अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए. टाटा ने भी अपना कार्यक्षेत्र झारखंड को ही चुना था.

आदिवासियों की ज़मीन नहीं छीनने देंगे- हेमंत सोरेन

विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि रघुवर सरकार आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश में है. यह आदिवासियों के हक की लड़ाई है. इसके लिए हमारी पार्टी किसी भी स्तर तक उतरने को तैयार है. राज्य सरकार की तानाशाही के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, इसके लिए गैर भाजपाई दलों से भी समर्थन लिया जाएगा. हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया कि वे राज्य के गैर-मजरुआ जमीन एवं अन्य को चिन्हित कर लैंड बैंक बनाए और उद्योग के लिए इसी जमीन का आवंटन औद्योगिक घरानों को करे.

औद्योगिक विकास पर सवालिया निशान

झारखंड में पूरे तामझाम के साथ 'मोमेंटम झारखंड' का आयोजन तो हो गया, लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि क्या झारखंड में उद्योग स्थापित हो पाएंगे. अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण जमीन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जो औद्योगिकीकरण के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. औद्योगिक घरानों और रैयतों के साथ हुए जमीन विवाद में दर्जनों बार गोलीकांड की घटना हुई और कई लोग इस हिंसक घटना में मारे गए. एनएचपीसी को अपना महत्वाकांक्षी कोयलकारो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा. नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्ट ने अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी तपकरा गोलीकांड के कारण अपना बोरिया बिस्तर समेट कर प्रोजेक्ट बंद करने की घोषणा कर दी. हजारीबाग में एनटीपीसी को अपने प्रोजेक्ट के लिए अभी तक रैयतों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कई बार यहां भी हिंसक झड़पें हुई हैं. अभी हाल ही में हुए गोलीकांड में आधा दर्जन लोगों की जानें चली गई थी. रामगढ़ जिले के गोला में भी एक पावर प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था, यहां भी हिंसक झड़पें हुई और कई लोगों की जानें चली गईं. मित्तल समूह ने एमओयू के बाद जमीन की तलाश की. रांची से सटे तोरपा में जमीन भी चिन्हित हुए. भूमि मालिकों को जमीन की दोगुनी कीमत दी जा रही थी, पर यहां भी स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, परिणाम यह हुआ कि मित्तल को अपना कॉरपोरेट ऑफिस बंद करना पड़ा और उन्होंने झारखंड से अपना मुंह मोड़ लिया. कुछ यही हाल अडानी, एस्सार, आरपीजी समूह एवं अभिजीत ग्रुप के साथ भी हो रहा है और ये लोग भी कारोबार समेटने के मूड में हैं. अंबानी ने तो पावर प्रोजेक्ट से एक तरह से मुंह ही मोड़ लिया है. झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की भी घोर अभाव है, पूरा क्षेत्र नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है और विधि-व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि औद्योगिक घराने एमओयू को जमीन पर उतारने में कितनी रुचि दिखाते हैं. वैसे झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार है और मुख्यमंत्री रघुवर दास दृढ़ इच्छाशक्ति भी रखते हैं, तो यह संभव है कि एमओयू को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे.

हुर्रियत ने शिवरात्रि के लिए हड़ताल का आह्वान रद्द किया

हेरथ या शिवरात्रि दरअसल हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है. आम हिन्दुओं के मुक़ाबले कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को एक अलग ही अंदाज़ में मनाते हैं. आम हिन्दुओं के लिए तो यह महज़ एक दिन का त्यौहार होता है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो मूल रूप से शैव सम्प्रदाय को मानने वाले हैं, वे इस त्यौहार को 23 दिन यानि तीन सप्ताह से अधिक समय तक मनाते हैं. इस अवधि में हेरथ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. कश्मीरी पंडित इस त्यौहार के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां करते हैं.

हारून रेशी

बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में प्रत्येक शुक्रवार को अलगाववादियों के कहने पर एक आम हड़ताल होती है, लेकिन शिवरात्रि के कारण उस हफ्ते के शुक्रवार का आह्वान रद्द कर दिया गया. दरअसल, कश्मीरी पंडितों के त्योहार हीरथ के मद्देनज़र हुर्रियत नेताओं ने यह कदम उठाया. पंडितों ने शुक्रवार को शिवरात्रि मनाई. मुसलमान हमेशा से कश्मीरी पंडितों के इस त्यौहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. सदियों की इस संयुक्त संस्कृति में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों ने हमेशा एक-दूसरे को अपनी खुशियों और त्योहारों में शामिल रखा है. दोनों सम्प्रदाय हमेशा से एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते आए हैं. हालांकि पिछले ढाई दशकों से जारी हिंसक हालात के नतीजे में कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों के बीच संबंधों में एक खाई पैदा हो गई, लेकिन अबकी बार घाटी में इस खाई को पाटने की कोशिशें दोनों ओर से हुईं. सोशल मीडिया पर कश्मीरी मुसलमानों के ऐसे अनगिनत पोस्ट देखने को मिले, जिनमें पंडित भाईयों को शिवरात्रि की शुभाकामनाएं दी गईं. इसके साथ ही अधिकतर लोगों ने इस साझा संस्कृति से जुड़ी उन यादों का भी उल्लेख किया, जब घाटी के हर क्षेत्र में दोनों सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे के त्यौहारों को अपना त्यौहार समझकर इनमें हिस्सा लेते थे. इन फेसबुक पोस्ट्स के द्वारा लोगों ने एक दूसरे के साथ शिवरात्रि के इस त्यौहार की जानकारियां भी साझा की.

हेरथ या शिवरात्रि दरअसल हिन्दुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है. आम हिन्दुओं के मुक़ाबले कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को एक अलग ही अंदाज़ में मनाते हैं. आम हिन्दुओं के लिए तो यह महज़ एक दिन का त्यौहार होता है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो मूल रूप से शैव सम्प्रदाय को मानने वाले हैं, वे इस त्यौहार को 23 दिन यानि तीन सप्ताह से अधिक समय तक मनाते हैं. इस अवधि में हेरथ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. कश्मीरी पंडित इस त्यौहार के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां करते हैं. सबसे पहले वे अपने घरों और आसपास के वातावरण को साफ करने पर विशेष ध्यान देते हैं. पूजा के कमरों को सजाया जाता है. पूजा में काम आने वाले फूलों, अखरोटों और बर्तनों को तैयार रखा जाता है. इस समय पंडित घरों में एक विशेष प्रकार का हर्षोल्लास देखने को मिलता है. बूढ़े बुजुर्ग तो शिवरात्रि को पूजा का एक ज़रिया समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बस खुशियां मनाने का एक बहाना होता है. बुजुर्ग कश्मीरी पंडित इस दिन उपवास रखते हैं. आमतौर पर फरवरी या मार्च में आने वाला यह त्यौहार फागुन महीने के 13वें दिन मनाया जाता है. हेरथ या शिवरात्रि का यह त्यौहार शिव और पार्वती की शादी से संबंद्ध है. हिन्दू इस दिन भगवान कृष्ण से संबंधित पूजा भी करते हैं.

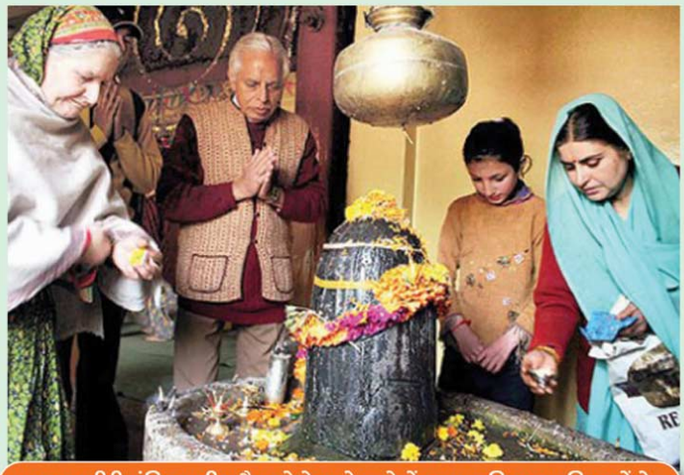

एक कश्मीरी पंडित सतीश रैना ने हेरथ के बारे में बताया कि अन्य हिन्दुओं के मुक़ाबले कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को ज़रा अलग ढंग से मनाते हैं. हम इस दिन वटक पूजा करते हैं. बाक़ी दुनिया के हिन्दू इस शब्द से भी अंजान हैं. दरअसल, वटक कश्मीरी भाषा का शब्द है. इसका मतलब कई चीज़ों के प्रयोग करने से है. हम इस विशेष पूजा में विभिन्न सामग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए इसे वटक पूजा कहा जाता है.

एक कश्मीरी पंडित सतीश रैना ने हेरथ के बारे में बताया कि अन्य हिन्दुओं के मुक़ाबले कश्मीरी पंडित इस त्यौहार को ज़रा अलग ढंग से मनाते हैं. हम इस दिन वटक पूजा करते हैं. बाक़ी दुनिया के हिन्दू इस शब्द से भी अंजान हैं. दरअसल, वटक कश्मीरी भाषा का शब्द है. इसका मतलब कई चीज़ों के प्रयोग करने से है. हम इस विशेष पूजा में विभिन्न सामग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए इसे वटक पूजा कहा जाता है.

इस पूजा में एक ऐसी चीज़ भी रखी जाती है, जिसे शिवजी के विश्वासपात्र गेट कीपर का एक प्रतीक समझा जाता है. पूजास्थल पर दो बर्तन रखे जाते हैं, जिन्हें शिवजी और पार्वती से संबंद्ध किया जाता है. इसके अलावा इस अवसर पर और चार बर्तन रखे जाते हैं, जिन्हें शिवजी के बारातियों का प्रतीक समझा जाता है. पूजा में काम आने वाली सबसे महत्वतपूर्ण चीज़ अख़रोट होते हैं. इन अख़रोटों को बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. सतीश कहते हैं कि अख़रोट चूंकि गोल होते हैं और ये ज़मीन के रंग जैसे होते हैं, इसलिए पूजा में इनका विशेष प्रयोग होता है. अखरोट के अन्दर मौजूद चार खानों को हम चार वेदों का प्रतीक समझते हैं.

कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हेरथ मूल रूप से हैरत शब्द से जुड़ा है. उनका कहना है कि कश्मीर पर जब पठानों की सत्ता थी, तो उस ज़माने के एक गवर्नर जब्बाहर खां ने अज्ञात कारणों की बुनियाद पर कश्मीरी पंडितों को सर्दियों में शिवरात्रि का त्यौहार मनाने से मना कर दिया और कहा कि वे गर्मियों में ये त्यौहार मनाएं. सर्दियों में यहां बर्फबारी होती थी और यह त्यौहार बर्फबारी में ही मनाया जाता था, इसलिए पंडितों को इसे गर्मियों के मौसम में मनाने पर आपत्ति थी. लेकिन गवर्नर के आदेश के आगे झुकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था. इसके बाद जब गर्मियों में शिवरात्रि मनाई जा रही थी, तो उम्मीद के उलट आश्चर्यजनक रूप से उस दिन घाटी में बर्फबारी हुई. यह देखकर सब हैरान हो गए और इस प्रकार से कश्मीर में शिवरात्रि का नाम 'हेरथ' (हैरत) पड़ गया.

घाटी में सशस्त्र आन्दोलन होने से पहले, जब यहां हर क्षेत्र में मुसलमानों और पंडितों की मिलीजुली आबादी हुआ करती थीं, तब हेरथ मुसलमानों के लिए भी उतनी ही खुशी का कारण होता था, जितना पंडितों के लिए. सतीश कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे मुहल्ले के मुसलमान बच्चे हैरथ के मौके पर अधिकतर समय हमारे साथ ही गुज़ारते थे. पाईन शहर के एक पूर्व अध्यापक फारूक़ अहमद शाह का कहना है कि बचपन में वे हेरथ के मौके पर अपने पड़ोसी पंडितों के घर इसलिए बार-बार जाते थे, क्योंकि वहां खाने-पीने के लिए बहुत चीज़ें मिलती थीं. इस दिन कश्मीरी पंडित अपने मुसलमान दोस्तों को खाने पर बुलाते थे और इनके घरों में प्रसाद भेजते थे.

1990 में जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी से चले गए, तो यहां के मुस्लिम समाज पर जो पंडितों के रहन-सहन, संस्कृति, सौहार्द और उनके त्योहारों के छाप थे, वे मिटने लगे. पत्रकार तारिक मीर कहते हैं कि 27 वर्ष एक बहुत बड़ा अर्सा होता है. इस अवधि में दोनों सम्प्रदायों की एक नई नस्ल परवान चढ़ गई. कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों की ये नई नस्ल इस बात से बेख़बर है कि इनके बुजुर्गों का रहन-सहन और संस्कृति किस प्रकार एक दूसरे के साथ रची-बसी था.

पिछले 27 वर्षों में दोनों सम्प्रदायों के बीच पैदा हुई इस खाई को पाटने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ के बुजुर्ग पुराने दिनों की यादें वापस लौटाएं और नई नस्लों को इस साझा संस्कृति और रहन-सहन से रूबरू कराएं, जो यहां सदियों तक देखने को मिला है.■

feedback@chauthiduniya.com

जन्मांक के हिसाब से इस सप्ताह आपका भविष्यफल

क्या कहता है आपका टैरो कार्ड

अलंकृता मानवी

लेखिका मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं. आप भी अगर टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो संपर्क करें- astro@chauthiduniya.com

जन्मांक 1: (जिनका जन्म 1, 19, 28 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह सूर्य है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, वज्र डाकनी. इस हफ्ते आप संगीत, कला से जुड़े काम करें. यह सप्ताह आरामदायक और आनंददायक रहेगा. कला से जुड़े काम करने से खुशियां मिलेंगी. होली में आपके लिए पीले और लाल रंग के गुलाल का इस्तेमाल बेहतर रहेगा.

जन्मांक 2: (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह चन्द्रमा है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, डेविल कार्ड. इस सप्ताह नकारात्मकता और परेशानी रहेगी, लेकिन घबराएं नही, धैर्य रखें. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. सोच-समझ कर खाना खाएं और काम करें. घर में नमक का पोछा लगाने से फायदा होगा. खिचड़ी-चावल या अन्न का दान करें. होली में गुलाबी और नारंगी रंग के गुलाल का इस्तेमाल करे.

जन्मांक 3: (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बृहस्पति है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, टेन ऑफ वज्रा. इस हफ्ते आप खास सावधानी बरतें, संभल कर चलें. ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें. वाहन संभल कर चलाएं, फल का दान करें. नीले और लाल रंग के गुलाल का इस्तेमाल अच्छा रहेगा.

जन्मांक 4: (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सफरिंग मैन. सेहत का ध्यान रखें. घर पर कोई बीमार पड़ सकता है. खाने में परहेज रखें. बीमारी से बचने के लिए कच्चे दूध और शहद का स्नान करें. होली में जामुनी और हरे रंग के गुलाल का उपयोग करें.

जन्मांक 5: (जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बुध है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सिक्स ऑफ ज्वेल्स. इस सप्ताह आप उदारता दिखाएं. इससे आपको लाभ मिलेगा. रिश्तों पर विशेष ध्यान दें और उदारता दर्शाएं. होली में आपके लिए पीला और गुलाबी रंग का अबीर बेहतर होगा.

जन्मांक 6: (जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शुक्र है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, द एलीफैंट. इस सप्ताह आपके जीवन मे स्थिरता आएगी. आपको मजबूती मिलेगी और प्रमोशन के भी मौके मिलेंगे. आपके लिए लाल और नीले रंग का अबीर अच्छा रहेगा.

जन्मांक 7: (जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वरुण है).
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, द फूल कार्ड. इस सप्ताह आप सोच-समझ कर काम करें. कोई भी नया निर्णय लेने से पहले या नया वेंचर शुरू करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें. पीला और जामुनी रंग का गुलाल आपके लिए बेहतर होगा.

जन्मांक 8: (जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शनि है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, द टावर. इस सप्ताह आपके जीवन में बड़ा और बेहतर बदलाव आएगा. आपको स्थिरता और प्रमोशन मिल सकती है. नए बदलाव के लिए तैयार रहें. मीठे पकवान का दान करें. आपके लिए नारंगी और नीले रंग का अबीर उत्तम रहेगा.

जन्मांक 9: (जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह मंगल है)
इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, टू ऑफ वज्र कार्ड. ये सप्ताह पार्टनरशीप के लिए बेहतर रहेगा. जो कार्य करेंगे उसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा. नए मित्र बन सकते हैं. वस्त्र का दान करें. गुलाबी और नारंगी रंग का गुलाल आपके लिए बेहतर होगा.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

वास्तविक जीडीपी परिणाम के लिए एक साल इंतज़ार करना होगा

आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के कारनामे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. वे दिल्ली के रामजस कॉलेज या जिस संस्था में भी उनकी पकड़ है, वहां हंगामा खड़ा कर रहे हैं. पिछले साल जेएनयू प्रकरण था, इस साल रामजस है. रामजस में जो हुआ, वो शर्मनाक है. लेकिन यदि उनका मक़सद नागरिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करना है, यदि देश में आम वाद-विवाद, बहस-मुबाहिसा के आदर्श को धीरे-धीरे समाप्त करना है, तो वे सही दिशा में जा रहे हैं. दरअसल, एबीवीपी को अपने विचारों के सिवा कोई और विचार स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए वे गुंडागर्दी, हुल्लड़बाजी और बल प्रदर्शन करेंगे.

चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. चुनाव प्रचार के दौरान हर दिन यह देखने को मिला कि अपने भाषणों का स्तर नीचे गिराने में राजनेता कैसे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे, खास तौर पर प्रधानमंत्री. वे निश्चत रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं. हम मानते हैं कि यह चुनाव का समय था और अपनी पार्टी का नेता होने के नाते वे चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे प्रधानमंत्री हैं. उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए. खास तौर पर ऐसी भाषा जैसे किसी को धमकाया जा रहा हो. ख़राब भाषा के प्रयोग से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है. बहरहाल, चुनाव तो चुनाव ही होते हैं. उनके कुछ सलाहकार होंगे, जो उन्हें ऐसी सलाह दे रहे होंगे, जिसके तहत उन्होंने यह रुख अपनाया हो.

आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के कारनामे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. वे दिल्ली के रामजस कॉलेज या जिस संस्था में भी उनकी पकड़ है, वहां हंगामा खड़ा कर रहे हैं. पिछले साल जेएनयू प्रकरण था, इस साल रामजस है. रामजस में जो हुआ, वो शर्मनाक है. लेकिन यदि उनका मक़सद नागरिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करना है, यदि देश में आम वाद-विवाद, बहस-मुबाहिसा के आदर्श को धीरे-धीरे समाप्त करना है, तो वे सही दिशा में जा रहे हैं. दरअसल, एबीवीपी को अपने विचारों के सिवा कोई और विचार स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए वे गुंडागर्दी, हुल्लड़बाजी और बल प्रदर्शन करेंगे. मैं आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस नए पुलिस आयुक्त के अधीन समझदारी के साथ मामले पर कार्रवाई करेगी. बीएस बस्सी के कार्यकाल में जैसा किया गया था, वैसा नहीं करेगी. बस्सी केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, बल्कि सरकार उनसे जितनी आशा कर रही थी, उससे कई क़दम आगे जा कर काम कर रहे थे.

> अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने देश में प्रवासियों को बुलाना नहीं चाहते हैं. हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी सरकार ने भारतीयों को अपने यहां काम दे कर भारत पर कोई एहसान नहीं किया है. उन्होंने भारतीयों को काम दिया, क्योंकि भारतीयों की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वे अपना काम मुनासिब तनख्वाह पर दूसरों से बेहतर कर सकते हैं. बहरहाल, अर्थशास्त्र का अपना तर्क होता है, भले ट्रम्प कुछ भी चाहते हों. लिहाज़ा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है.

उसके बाद ये सवाल कि क्या नोटबंदी ने जीडीपी को प्रभावित किया? यह उनके लिए बहुत आसान है. यदि वे कोई चुनाव जीत जाते हैं, जैसे कोई निगम चुनाव, तो ये कहते हैं कि नोटबंदी को लोगों ने स्वीकार लिया. हालांकि उसका नतीजों से कोई लेना देना नहीं होता है. जहां तक जीडीपी का सवाल है, तो दिसंबर और जनवरी की जीडीपी का हिसाब आज नहीं लगाया जा सकता है, जो उनके लिहाज़ से 7 प्रतिशत है. इस पर न केवल विश्वास करना मुश्किल है, बल्कि यह हास्यास्पद भी है. जीडीपी के लिए हमें एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा. मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो इन चीज़ों को उलझाते हैं. दरअसल, सरकार को नोटबंदी करने का पूरा अधिकार है, उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया, हालांकि नोटबंदी का क्रियान्वयन भौंडे तरीके से किया गया. वित्त मंत्री को विश्वास में नहीं लिया गया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को विश्वास में नहीं लिया गया. पिछले रिज़र्व बैंक गवर्नर ने इस पर नकारात्मक जवाब दिया था. लिहाज़ा नोटबंदी का बुद्धिमतापूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ. अब इसके दीर्घकालिक परिणामों के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा.

अब एच-1 बी वीजा की बात करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने देश में प्रवासियों को बुलाना नहीं चाहते हैं. हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी सरकार ने भारतीयों को अपने यहां काम दे कर भारत पर कोई एहसान नहीं किया है. उन्होंने भारतीयों को काम दिया, क्योंकि भारतीयों की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वे अपना काम मुनासिब तनख्वाह पर दूसरों से बेहतर कर सकते हैं. बहरहाल, अर्थशास्त्र का अपना तर्क होता है, भले ट्रम्प कुछ भी चाहते हों. लिहाज़ा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. हर देश को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, अमेरिका को भी करनी चाहिए. लेकिन बिल गेट्स हों, गूगल हो या कोई अन्य बड़ी कंपनी, सबका अपना हित होता और यह उनकी चिंता है कि अपनी सरकार से वीजा नियमों पर बात करें. मुझे यह ठीक नहीं लगता कि भारत से जयशंकर वहां जाएं और इस विषय पर बात करें. भारत को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए और हमें यहां के आर्थिक वातावरण को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए. एक तरफ आप विजय माल्या को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ सुब्रत रॉय को जेल में बंद कर रहे हैं. आप तो खुद अपने यहां माहौल ख़राब कर रहे हैं. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, लेकिन माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए. मैं समझता हूं कि अब चुनाव ख़त्म होने के बाद प्रधानमंत्री गंभीरता से विचार करेंगे कि व्यापार के लिए कैसे वातवरण को बेहतर बनाया जाए. देखते हैं क्या होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जश्न-ए-रेख्ता

उर्दू पुनरुत्थान आंदोलन में मील का पत्थर है

शुजात बुख़ारी

उर्दू का जश्न मनाने के लिए आयोजित तीन दिवसीय जश्न-ए-रेख्ता के समापन पर प्रतिभागी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा जैसे उर्दू के पुनरुत्थान का समय आ गया है. जश्न में पहुंचने वाले लोगों के सैलाब ने आयोजकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया. उन्होंने इतनी भारी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी. जैसे-जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, वैसे-वैसे यह महसूस हो रहा था कि उर्दू जिस शहर के गली-कूचों में परवान चढ़ी थी उसी शहर में अपने पुनरुत्थान की ओर कदम बढ़ा रही है. आम तौर पर भारत में जब उर्दू की हालत पर बात होती है तो उसे साजिश और पूर्वग्रह के दो शब्दों से ज़ाहिर किया जाता है. उर्दू से मोहब्बत करने वाले एक शख्स उद्योगपति संजीव सराफ ने कम से कम इस मिथक को तोड़ दिया कि युवा पीढ़ी में इस भाषा के लिए कोई आकर्षण नहीं है.

जश्न-ए-रेख्ता का यह लगातार तीसरा संस्करण था और इसमें शामिल होने वालों की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है. रेख्ता फाउंडेशन ने समारोह में आये लोगों के लिए उर्दू भाषा के सभी रंगों, बारीकियों और अलग-अलग विधाओं का मुकम्मल पैकेज पेश किया. यही कारण है कि आईजीएनसीए के विशाल लॉन में तीन दिनों तक एक साथ चल रहे अलग-अलग सत्रों में गुलजार, शर्मिला टैगोर, गोपीचंद नारंग, नादिरा बब्बर और प्रेम चोपड़ा जैसी हस्तियों को सुनने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई थी. अलग-अलग प्रस्तुतियों के बाद उर्दू के अलग-अलग विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ. दरअसल इस संदर्भ में आयोजकों ने लोकप्रिय संस्कृति, कविता, गद्य, नाटक, कला, सिनेमा किसी भी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की.

समापन सत्र में अन्नू कपूर और हंसराज हंस ने जब अपनी पेशकश सामने रखी तो इस रंगीन शाम में मौजूद उत्साहित दर्शकों ने हर शब्द पर ताल दी और हर हरकत पर ताली बजाई. आयोजकों ने न सिर्फ मुशायरा, दास्तानगोई, ड्रामा और संगीत के जरिया लोगों को आकर्षित किया, बल्कि ऐवान-ए-जायका के तहत फूड फेस्टिवल भी आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था, जिसमें कश्मीरी और मुग़लई व्यंजन भी शामिल थे. हालांकि यह दिख रहा है कि उर्दू को एक नया जीवन मिल रहा है, लेकिन इसके संरक्षण में कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं.

इस जश्न का संस्थानीकरण एक ऐसी भाषा के लिए, जो दिलों को जोड़ती है और बॉलीवुड पर जिसका प्रभुत्व रहा है (हालांकि अब इसे हिन्दुस्तानी कहा जाता है) के लिए शुभ संकेत है. लेकिन भाषा की मिठास दिल और दिमाग पर असर करती है और यही कामजश्न-ए-रेख्ता ने किया. लोग अलग-अलग कार्यक्रमों में स्थान पाने के लिए उत्साहित नज़र आये और घंटों जश्न के अलग-अलग रंगों का लुत्फ़ उठाते रहे. एक भाषा जो एक समुदाय से जुड़ी हुई है और जिसे आधुनिक संस्कृति के बोझ तले दबा दिया गया है, लेकिन विविधताओं को समेटते जश्न-ए-रेख्ता में एक और बात उभर कर सामने आई कि बिना किसी पूर्वग्रह के यह भाषा विभिन्न धर्मों के लोगों में अपनी जगह बना सकती है. रेख्ता ने जो मंच उपलब्ध कराये थे, वहां से कलाकारों ने धार्मिक कट्टरवाद के बंधनों को तोड़ दिया. जब प्रसिद्ध उर्दू लेखक सुबोध लाल ने उर्दू और सेकुलरिज्म के संबंध को उजागर करते हुए कहा कि उर्दू धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है तो वहां मौजूद लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजा का उनकी बात ताईद की. उन्होंने कहा कि उर्दू किसी भी धर्म के खिलाफ दुर्भावना नहीं रखती. संजीव सराफ कहते हैं कि उर्दू का उत्सव इसकी

विविधता और सुंदरता के लिए मनाया जाना चाहिए. सराफ ने बिना किसी बनावट के कहा कि रेख्ता उर्दू के समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे बढ़ावा देने का आंदोलन है और जश्न-ए-रेख्ता उसी आंदोलन की एक कड़ी है.

रेख्ता का दिल्ली के दिल में उर्दू का उत्सव मनाना बेशक किसी भाषा को बचाने का अनूठा प्रयास है. बहुतों का मानना है कि नई पीढ़ी का उर्दू समेत क्षेत्रीय भाषाओं से दूरी इन भाषाओं को ख़त्म कर देगी. आज तेजी से बदल रही प्रतिस्पर्धी दुनिया में ऐसी भाषाएं, जिनसे सभ्यताओं को आकार मिला है, अब कमजोर हो गई हैं. यूनेस्को के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 21वीं सदी के अंत तक लगभग 7,000 भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं. ऐसे लोग जो इन भाषाओं से जुड़े हुए थे, वे अब तेज़ी से इन भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं. वे ऐसी भाषाओं का चुनाव कर रहे हैं, जिनमें अधिक आर्थिक अवसर हों और जिनमें उनका भविष्य उज्ज्वल रहे. लोग उन्हीं भाषाओं को अपनाते हैं जिनमें बेहतर आर्थिक संभावनाएं हों. कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक शोध के लेखक तात्सुया अमानो का कहना है कि हमने (अपने शोध में) पाया है कि वैश्विक स्तर पर कई भाषाओं में आई गिरावट पूरी तरह से आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है. दरअसल यह गिरावट विशेषकर आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में दर्ज की गई है और यह खतरा दक्षिण एशिया की भाषाओं पर भी मंडरा रहा है. हालांकि उर्दू एक विलुप्तप्राय भाषा नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि इसके बोलने वालों की संख्या घट रही है. अब यह सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से एक नहीं रही है.

उर्दू और षडयंत्र सिद्धांत

उर्दू जैसी भाषाओं के पतन के बारे में एक आम बात कही जाती है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है. यह हकीकत है कि उर्दू भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, हालांकि पाकिस्तान में यह बहुमत की भाषा है लोग इसे बोलते हैं. इस भाषा में लिखते-पढ़ते हैं और इस भाषा को सीखते भी हैं. अब आर्थिक लाभ के अभाव में पाकिस्तान में भी युवा पीढ़ी अब अंग्रेजी को अपनाने लगी है. यही कारण है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाने के बारे में विचार करने लगी है. हालांकि पाकिस्तानी कुलीन वर्ग, जिनका नौकरशाही और नीति निर्माताओं में वर्चस्व है, इस कदम का विरोध कर रहा है. इस भाषा के लिए असली चुनौती यह है कि आज यह आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है और जो लोग इस भाषायी सौंदर्य के प्रशंसक हैं, उनकी संख्या बड़ी नहीं है.

भारत में भी, जहां इसकी पहचान मुस्लिमों से जोड़ दी गई है, इसकी आर्थिक संभावनाएं उज्ज्वल नहीं हैं. रोज़गार के साधन के रूप में इस भाषा को अपनाने वाले लोगों की संख्या घट रही है. यहां नीति निर्माता उर्दू को इसलिए नज़रंदाज़ कर रहे हैं क्योंकि यह आर्थिक रूप से बहुत उपयोगी नहीं है और यह तथ्य उर्दू के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है.

भारत में सरकारों ने इस भाषा के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया है. पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास के लिए दिया गया अनुदान सिर्फ 60 लाख रुपए था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के कार्यकाल में बड़ी वृद्धि देखी गई. मुरली मनोहर जोशी के मानव संसाधन विकास मंत्री रहते यह अनुदान 5 करोड़ हो गई थी. वर्ष 2012-13 में इस अनुदान को बढ़ा कर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया था और पिछले बजट में भी इसमें और इजाफा किया गया (हालांकि अब सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनुदान को एक साथ रखा गया है). हालिया कुछ वर्षों में उर्दू मीडियम स्कूलों की संख्या में वृद्धि के साथ वित्तीय सहायता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भाषा की चुनौतियां अभी बरक़रार हैं. भारत के मुसलमानों में उर्दू और हिन्दुस्तानी को दोनों की एक भाषा के रूप में पहचान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है.

उर्दू सिर्फ एक धर्म विशेष की भाषा न होकर एक बड़े समुदाय की भाषा है. इस धारणा को मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों सामान्य रूप से मानते हैं. यह नतीजा यूनिवर्सिटी ऑफ़ हाइडेल्बर्ग के साउथ एशियाई इंस्टिट्यूट के अंतर्गत अन्विता अब्बी, इम्तियाज हसनैन और आयशा किदवई द्वारा किए गए अध्ययन में कही गई. इन शोधकर्ताओं ने बिहार, लखनऊ, मैसूर, दिल्ली और शिमला में अपना अध्ययन किया.

अविभाजित भारत में उर्दू एक लोकप्रिय भाषा थी और विभाजन के बाद भी यह सरकारी भाषा के दावेदार के रूप में संविधान सभा के एजेंडे पर मौजूद थी. वोटिंग के दौरान हिंदी और उर्दू के बीच टाई हो गई थी और तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने हिन्दी का समर्थन किया था. इसमें विडंबना यह थी कि बेगम एजाज रसूल और मौलाना हसरत मोहानी दोनों ने उर्दू के खिलाफ मतदान किया था. मौलाना हसरत मोहानी ने आर्टिकल 370 का भी विरोध किया था, लेकिन उनके विरोध का बचाव गोपाल स्वामी आयंगर ने किया था.

हालांकि उर्दू बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दूसरी सरकारी भाषा है, लेकिन इसके अस्तित्व की चुनौतियां इसके मूल बोलने वालों की तरफ से ही हैं, जो अब यह सोचने लगे हैं कि इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है. सुप्रसिद्ध लेखक और कवि गोपीचंद नारंग बेशक यह कह सकते हैं कि उर्दू मेरी पहचान है, लेकिन यह उर्दू की व्यवहार्यता को लेकर लोगों को आश्वस्त करने के लिए काफी नहीं है. शायद जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसी जगह है, जहां एक बाहरी भाषा होने के बावजूद, इससे खतरे का सामना नहीं है. लेकिन यह हकीकत है कि सरकारी सतह पर यह उपेक्षित है.

रेख्ता की पहल ने इस आम धारणा को ख़ारिज कर दिया कि इस भाषा से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है. पिछले दिनों दिल्ली में जो देखा गया वो एक ऐसी भाषा के संरक्षण की एक आशाजनक शुरुआत थी, जो अलग-अलग समुदायों को एक सूत्र में पिरोने की अपनी क्षमता साबित कर चुकी है. दरअसल हमें हर जगह और अधिक रेख्ता की आवश्यकता है. संजीव सराफ और उनकी टीम को हमारा सलाम. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

इस चुनावी शोर में लोकतंत्र खो गया है

चुनाव बीत गए, लेकिन चुनाव की कड़वी यादें हमें बहुत दिनों तक परेशान करती रहेंगी. भारत में चुनाव पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सर्वाधिक पवित्र निशानी माना जाता था, जिसमें जनता फैसला करती थी कि कौन 5 साल तक सत्ता में रहेगा और कौन 5 साल तक जनता के हित में सरकार द्वारा न किए जा रहे कामों को लेकर आंदोलन करेगा. धीरे-धीरे लोकतंत्र का यह सर्वाधिक पवित्र कार्यक्रम किसी भी तरह सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े.

पहले भी लोकतंत्र में चुनाव होते थे. लोग एक दूसरे का विरोध भी करते थे लेकिन शाम को बैठ कर दिन भर की गतिविधियों का आनंद लेते थे. एक दूसरे के साथ मिल कर खाते-पीते थे और हंसते-हंसाते भी थे. लेकिन, पिछले 20-25 सालों से, मतदान के दौरान हुई बदमजगी अब हत्या तक पहुंच जाती है. जिनके घर के लोगों की हत्याएं होती हैं, उन्हें बाद में कोई नहीं पूछता. न वो जिनका पक्ष लेने के लिए उनकी हत्या हुई और न वो जो इस हत्या को लेकर दिमागी तौर पर परेशान रहे.

इस चुनाव ने, चाहे पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश रहा हो, कहीं पर भी मुद्दे सामने नहीं आए. जीतने वाली पार्टी क्या करेगी, उसने बताया नहीं. धर्म और जाति का मुद्दा आया. सत्ता पर किसी भी तरह कब्जा करना है, ये सवाल उठा. सामने वाला कितना चोर, लुटेरा और लुच्चा है, ये सवाल उठा, लेकिन हम क्या करेंगे, यह किसी पार्टी या नेता ने नहीं बताया. शायद वो ये सब बताना भी नहीं चाहते, दूसरी तरफ लोग जानना भी नहीं चाहते थे. जहां तक मतदाताओं का सवाल है, मतदाता इस प्रक्रिया से इतना अधिक निराश हो गया है कि वो यह भी नहीं देखता कि जिस उम्मीदवार या दल को वो वोट दे रहा है, उस दल ने 5 साल पहले उससे क्या वादा किया था. उस वादे को उसने निभाया या नहीं निभाया. वो ये भी नहीं देखता कि 5 साल में उसका उम्मीदवार कितनी संपत्ति का मालिक बन गया या 5 साल में वैध या अवैध तरीके से कितनी संपत्ति जमा की. वो ये भी नहीं देखता कि जिस उम्मीदवार को वो वोट दे रहा है, अगर वो पहले से जीता हुआ है, तो उसने विधानसभा में अपने क्षेत्र या प्रदेश के लिए कोई सवाल उठाया है या नहीं, बहस की भी है या नहीं.

इसलिए जैसी जनता, उसका वैसा प्रतिनिधि. जनता ने सवाल उठाना छोड़ दिया. जनता ने नेताओं पर कटाक्ष करना छोड़ दिया. जनता ने नेताओं को लेकर बहस और बातचीत बंद कर दी. दूसरी तरफ, नेताओं ने इस स्थिति को अपने लिए फायदेमंद समझा, व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के लिए भी. हमारा पूरा लोकतंत्र, पता नहीं किस चौराहे से मुड़ कर उस तरफ बढ़ने लगा, जिसका रास्ता एकाधिकारी शासन की तरफ जाता है.

अब चुनाव पार्टी का न होकर व्यक्तियों का हो गया है. पार्टियों से लोगों को मतलब कम, व्यक्ति से ज्यादा हो गया है. फिर अगर वो व्यक्ति अपराध तंत्र से जुड़ा है, यदि वो व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण देता है या यदि वो व्यक्ति अवैध धंधे चलाता है, तब भी इसका कोई प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ता है. हालांकि, सब जानते हैं कि वे जिसे चुन रहे हैं, वो प्रदेश या जिले के लिए कितना सही है.

इस चुनाव ने लोगों के दिलों में बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं. स्वयं भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, जिनमें

> वे लोग जो लोकतंत्र के प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र को सत्ता, शासन और जीवन की सबसे अच्छी शैली मानते हैं, उनके लिए यह चिंता की बात है कि मीडिया के लोग भी लोकतंत्र को रौंदने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे और न लोकतंत्र की इज्जत उतारने में किसी से पीछे रह रहे हैं. शायद मीडिया के लोगों को भी लोकतांत्रिक मान्यताओं से परहेज या गुरेज है. जाहिर है जब पूरा समाज भटक रहा हो, तो अकेले मीडिया को ही क्यों दोष दिया जाए? इसलिए मन में यह सवाल उठता है कि कहां हैं समाज सुधारक, कहां हैं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता, कहां हैं टेलीविजन पर भाइचारे और प्रेम का संदेश देने वाले साधु-महात्मा और मौलाना.

मंत्री नकवी और उमा भारती शामिल हैं, ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देती, तो अच्छा रहता. दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच ये भावना घर कर गई कि वे भाजपा के प्रति कितनी भी आसक्ति दिखाएं, उनके नेता कितना भी अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें द्वितीय ही नहीं, तृतीय स्तर का नागरिक मानेगी और उनके सत्ता में हिस्सेदारी के सवाल को प्रासंगिक ही नहीं मानेगी. हालांकि मुसलमानों के बहुत सारे नौजवान नेता अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए और अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम समाज को लेकर कोई सटीक योजना इस चुनाव में पेश नहीं की.

इस चुनाव में यादव और अति पिछड़े समाज में एक नई दूरी बन गई. सवर्ण जातियां पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गईं, उनका संवाद मायावती और अखिलेश यादव से बहुत कमजोर पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ यादवों का एक तबका भाजपा के पास चला गया, लेकिन बहुत बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ रहा. मायावती से यादव समाज सौ प्रतिशत दूर रहा. दलित समाज कमजोर हुआ क्योंकि दलितों के कई सारे हिस्से मायावती का साथ छोड़ भाजपा की तरफ जाते दिखे.

इन सारे मनोमालिन्य और अंतर्विरोधों के बीच अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली दूरी क्या लोकतंत्र की सेहत के लिए सही है. मुझे लगता है कि राजनेता इस दूरी को शायद सही मानेंगे. आम लोग इन बढ़ती दूरियों के बीच पिसते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र इन दूरियों के भंवर में चक्कर खाता हुआ सत्ता और सरकार के बीच नाचता रहेगा. वे लोग जो लोकतंत्र के प्रेमी हैं, जो लोकतंत्र को सत्ता, शासन और जीवन की सबसे अच्छी शैली मानते हैं, उनके लिए यह चिंता की बात है कि मीडिया के लोग भी लोकतंत्र को रौंदने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे और न लोकतंत्र की इज्जत उतारने में किसी से पीछे रह रहे हैं. शायद मीडिया के लोगों को भी लोकतांत्रिक मान्यताओं से परहेज या गुरेज है. जाहिर है जब पूरा समाज भटक रहा हो, तो अकेले मीडिया को ही क्यों दोष दिया जाए? इसलिए मन में यह सवाल उठता है कि कहां हैं समाज सुधारक, कहां हैं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता, कहां हैं टेलीविजन पर भाइचारे और प्रेम का संदेश देने वाले साधु-महात्मा और मौलाना. हम इस शोर में लोकतंत्र को तलाशें या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तलाशें तो आखिर तलाशें कैसे? ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

लोकतंत्र पर बहस के नाम पर विश्वविद्यालय बना अखाड़ा

सहमति-असहमति दोनों ज़रूरी

संगीता घोष

लोकतंत्र की रखवाली के मामले में हमारे विश्वविद्यालय अखाड़े बन गए हैं. जो लोग यह मानते हैं कि विश्वविद्यालय छात्रों के बीच न सिर्फ विभिन्न विचारों के उगने को प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि इन्हें आपस में टकराने की जगह भी देते हैं, उनकी न सिर्फ आलोचना हो रही है बल्कि उन्हें कुचलने की कोशिश भी की जा रही है. हाल में ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुआ. यहां 'विरोधी की संस्कृति' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हो रहा था. इसमें छात्र नेता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे उमर खालिद को बतौर वक्ता बुलाया गया था. इसी बात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस सेमिनार को बाधित करने की कोशिश की. कॉलेज के जिन छात्रों और अध्यापकों ने विद्यार्थी परिषद की इस कोशिश का विरोध किया, उन पर इस छात्र संगठन के गुंडों ने पत्थरों और बोतलों से हमले कर दिए. पत्रकारों पर भी हमले किए गए. वहां पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही. पुलिस ने न सिर्फ विद्यार्थी परिषद के गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि जो लोग पुलिस के इस रवैये के विरोध के लिए मौरिस नगर थाने पर जमा हुए थे, उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया.

यह घटना उसी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत मौजूदा सत्ताधीशों के विरोध में उठने वाली हर आवाज को शांत करने का

काम किया जा रहा है. यह संघ परिवार के दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत संघ उच्च शिक्षा के संस्थानों पर कब्जा जमाना चाहता है. वह भी बहस और ज्ञान के बूते नहीं, बल्कि हिंसा और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बल पर. इसी तरह की एक और घटना इसी साल की शुरुआत में हुई थी. जेएनयू में तुलनात्मक गवर्नेंस और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाली निवेदिता मेनन पर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने इस बात को लेकर पुलिस शिकायत दर्ज करा दी कि उन्होंने कथित तौर पर अपने भाषण में कश्मीर को लेकर गलत बयान दिया है. इसके बाद विद्यार्थी परिषद ने विरोध शुरू कर दिया और मेनन के बयान को राष्ट्रदोही करार दिया. नतीजा यह हुआ कि उस कार्यक्रम की आयोजनकर्ता व्यास विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की सहायक प्राध्यापिका राजश्री राणावत को निलंबित कर दिया गया. 2016 के सितंबर में भी इसी तरह से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो शिक्षक स्नेह मानव और मनोज कुमार को निलंबित करने और कठोर सजा देने की मांग की जा रही थी. इन दोनों ने महाश्वेता देवी की लघु कथा द्रौपदी पर आधारित एक नाटक का मंचन कराया था. विद्यार्थी परिषद ने इस नाटक को यह कहते हुए 'देशद्रोही' करार दिया कि इसमें भारतीय सेना का गलत चित्रण किया गया है, जबकि महाश्वेता देवी के नहीं रहने के बावजूद उनके साहित्यिक योगदान के लिए पूरे देश में याद किया जाता है.

इन विश्वविद्यालयों में वही सब हो रहा है जो साल भर पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू में हुआ था. जेएनयू में असल विवाद तो 9 फरवरी, 2016 को हुआ, जब कुछ छात्र अफजल गुरु की बरसी पर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन इसके पहले अगस्त, 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में एक डॉक्यूमेंट्री 'मुजफ्फरनगर बाकी है' के प्रदर्शन को लेकर तथाकथित 'देशभक्त' और 'देशद्रोही' आमने-सामने आ गए थे. उस वक्त डॉक्यूमेंट्री का विरोध अधार्मिक कहकर किया गया था.

ये सारी घटनाएं अलग-अलग और एक साथ यह बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने मई, 2014 में सत्ता में आने के बाद से उच्च शिक्षण संस्थानों को एक ही विचारधारा के कब्जे में लेने की कोशिश की है. इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए गए हैं. संघ के पसंद वाले लोगों को फिल्म सेंसर बोर्ड, फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान और भारतीय इतिहास शोध परिषद का प्रमुख बनाया गया. वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू में ऐसे कुलपति लाए गए, जो विद्यार्थी परिषद को अपने हिसाब से काम करने से नहीं रोक पाएं. जान-बूझकर इन संस्थानों में बौद्धिक बहस की संस्कृति और असहमति के हर स्वर को कुचलने का माहौल पैदा किया गया.

> हिंसा और उकसावे के इस काम पर संघ और भाजपा का एकाधिकार नहीं है, बल्कि दूसरे छात्र संगठन भी इन कामों में लगे हैं. विद्यार्थी परिषद जहां दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में गड़बड़ियां कर रही है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र नेताओं की एक बैठक को रद्द कर दिया. इसमें जेएनयू की छात्र नेता शेहला रसीद को आना था.

इससे अलग राह पर चलने वाले शिक्षकों और छात्रों को लगातार धमकियां मिल रही हैं. सरकार और उसके मंत्री अक्सर 'राष्ट्र विरोधी' का जुमला उछालते रहते हैं. इससे सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन को कुछ भी करने का हौसला मिलता रहता है. संदेश साफ है: अगर आप सत्ताधारी दल के खिलाफ हैं तो राष्ट्रद्रोही हैं. हिंसा की इस संस्कृति की वजह से स्वतंत्र सोच की संभावनाएं सिकुड़ती जा रही हैं.

हालांकि, हिंसा और उकसावे के इस काम पर संघ और भाजपा का एकाधिकार नहीं है, बल्कि दूसरे छात्र संगठन भी इन कामों में लगे हैं. विद्यार्थी परिषद जहां दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में गड़बड़ियां कर रही है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र नेताओं की एक बैठक को रद्द कर दिया. इसमें जेएनयू की छात्र नेता शेहला रसीद को आना था. छात्र संगठन का आरोप था कि शेहला ने एक फेसबुक पोस्ट में पैगंबर मुहम्मद का अपमान किया है. ये घटनाएं यह बता रही हैं कि विश्वविद्यालय जिन मूल विचारों पर खड़े होते हैं, वे विचार ही खतरे में हैं. विश्वविद्यालयों को ऐसी जगह माना जाता है, जहां विभिन्न विचारों पर चर्चा होती है, नए विचार उभरते हैं और जाने हुए व स्वीकार्य चीजों को चुनौती दी जाती है. जब सरकार, सरकारी एजेंसियां और भीड़ इस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो लोकतंत्र की मूल बात लोकतांत्रिक असहमति की रक्षा की कोशिश कर रहे हैं. ■

(लेखिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में सहायक संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

नौकरशाही की ऐतिहासिक गोलबंदी

राजभवन के सामने पांच दर्जन आईएएस अधिकारियों के सीना तान कर खड़ा होने और नौकरशाह की गिरफ्तारी का प्रतिवाद करने जैसी आईएएस अफसरों की गोलबंदी की मिसाल पहले नहीं मिलती. यहां तमाम सवालों के बीच महत्वपूर्ण यह था कि आखिर आईएएस एसोसिएशन ने इतना साहस कैसे जुटाया कि वे सब सीएमओ के खिलाफ खड़े हो गये? ऐसा तब हुआ जब एसआईटी इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि बीएसएसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है. आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार इस घोटाले में शामिल थे कि नहीं, यह अलग बात थी, लेकिन आम जनता में यह परसेप्शन बन चुका था कि आयोग के अध्यक्ष की नाक के नीचे घोटाला हुआ तो कहीं न कहीं या तो उनकी निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार थी या फिर वह प्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे थे.

इर्शादुल हक

बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की यह 'हिस्टोरिकल' गोलबंदी थी. नये-पुराने बैच के 60 से अधिक आईएएस अफसरान अपने चमचमाते और एयरकंडिशंड दफ्तरों से निकल कर राजभवन के सामने, खुले आकाश में मानव श्रृंखला बना कर सीना ताने खड़े हो गये थे. उनकी यह गोलबंदी उस नीतीश सरकार के खिलाफ थी, जिसके इशारों पर ये नौकरशाह उठक- बैठक करते नजर आते हैं. इससे पहले ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो. एक पूर्व आईएएस अधिकारी एमए इब्राहिमी इसलिए इस गोलबंदी को 'हिस्टोरिकल' कहने से खुद को नहीं रोक पाते. इब्राहिमी बिहार सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर साढ़े तीन दशक से ज्यादा समय बिता चुके हैं. कम से कम उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा तो कभी नहीं देखा. नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री कमोबेश 12 साल पूरा करने वाले हैं. उनके कार्यकाल में ऐसी चुनौती का सामने आना चकित करने वाला है क्योंकि वे देश के शायद एकमात्र सीएम हैं जो अपने नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा करने के लिए जाने जाते हैं. बल्कि यूं कहें कि उनकी पार्टी का एक बड़ा खेमा उनका सिर्फ इसलिए आलोचक रहा है क्योंकि वे राजनीतिक मामलों में भी ब्यूरोक्रेट्स को तरजीह देते हैं, अपने संगियों की तो सुनते ही नहीं.

इससे पहले कि बिहार के ब्यूरोक्रेट्स के बागी तेवर पर और चर्चा हो, इस हिस्टोरिकल गोलबंदी की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. जनवरी के आखिरी और फरवरी के प्रथम रविवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने क्लर्कों की नियुक्ति के लिए दो चरण की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था. ये परीक्षा चार चरणों में होनी थी. चंद हजार नौकरियों के लिए 18 लाख से ज्यादा प्रतियोगियों ने फॉर्म भरे थे. लेकिन प्रथन चरण की परीक्षा के पहले ही प्रश्नपत्र लीक हो गये. काफी हो-हल्ला मचा. आयोग इसे अफवाह करार देते हुए अगले चरण की परीक्षा की तैयारियों में जुट गया. तुर्रा यह कि पटना के एसएसपी मनु महाराज ने दो सदस्यीय टीम की जांच के हवाले से यह घोषणा कर दी कि लीक हुए प्रश्नों का ओरिजनल प्रश्नों से मिलान किया गया, लेकिन प्रश्न पत्र एक नहीं पाये गये. पर हकीकत यह थी कि दूसरे दिन दोनों प्रश्नपत्र समाचार पत्रों में छप गये थे. हो-हल्ला शांत होता कि इसी क्रम में दूसरे चरण की परीक्षा संपन्न हुई. फिर प्रश्नपत्र व्हाट्सएप पर वाइरल हो गया. आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार (आईएएस सुधीर गृहसचिव भी रह चुके हैं) व सचिव परमेश्वर राम ने एक स्वर में प्रश्नपत्र लीक को फिर अफवाह बता डाला. पर इस बार मामला शांत नहीं होना था, सो नहीं हुआ. मीडिया लगातार प्रश्नपत्र लीक की कहानियां बताता-सुनाता रहा. छात्र संगठन सड़कों पर आ गये. हो-हल्ला आंदोलन में बदल गया और आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया. छात्रों की टोली आयोग पहुंच गयी. तोड़-फोड़ की गयी और आयोग के सचिव परमेश्वर राम की जमकर पिटाई हुई. नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश डीजीपी को दे डाला. डीजीपी ने पटना के एसएसपी मनुमहाराज के नेतृत्व में एसआईटी के गठन के अलावा आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को भी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी. इसके बाद चीजें बड़ी तेजी से बदलने लगीं. धड़ा-धड़ छापेमारी हुई. गिरफ्तारियां शुरू हुईं और जांच दल इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रश्नपत्रों के लीक मामले में करोड़ों रुपयों का कारोबार हुआ है. दो हफ्ते के भीतर आयोग के सचिव परमेश्वर राम गिरफ्तार कर लिये गये. कई स्कूलों के मालिकान, कोचिंग संचालक और परीक्षा माफिया

पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सामने आकर सुधीर के पक्ष में खड़े हुए (ध्यान रहे कि मांझी ने अपने कार्यकाल में सुधीर को गृहसचिव बनाया था). फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक पंक्ति का बयान देते हुए कहा कि सुधीर कुमार ईमानदार अफसर हैं और कानून इस मामले पर अपना काम करेगा. इतना ही नहीं, इस मामले में विपक्ष भी कूद पड़ा. विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें सुधीर के साथ काम करने का जितना अनुभव है, उससे वे कह सकते हैं कि सुधीर ईमानदार अफसर रहे हैं. हालांकि मोदी ने यह भी जोड़ा कि परीक्षा घोटाला मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

तो पहले ही सलाखों के भीतर जा चुके थे. लेकिन इधर कुछ हलकों से यह आवाज उठती रही कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद आयोग के अध्यक्ष अब तक कैसे बचे हुए हैं? फिर एक दिन खबर आयी कि रात के अंधेरे में आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार को एसआईटी की टीम ने झारखंड के हजारीबाग से उठा लिया है. उन्हें आनन-फानन में जज के घर पहुंचाया गया, जहां से उन्हें फुलवारी जेल भेज दिया गया. यहां एक बात याद रहे कि जिस रात सुधीर को गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन महाशिवरात्रि की सरकारी छुट्टी थी. दूसरे दिन शनिवार और तीसरे दिन रविवार था. (छुट्टी से जुड़े मामले का जिक्र आगे आएगा).

रात को सुधीर की गिरफ्तारी हुई और सुबह होते-होते ब्यूरोक्रेट्स के गलियारे में कोहराम मच गया. आईएएस एसोसिएशन जो आम तौर पर गेट टुगेदर व चाय पार्टी के अलावा कुछ खास नहीं करता, सक्रिय हो गया. बल्कि यूं कहिए कि सक्रिय किया गया. एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यसचिव के घर पर जा धमके और सुधीर की गिरफ्तारी का प्रतिवाद किया. एक प्रतिनिधिमंडल सीएम नीतीश से भी मिला. शाम होते-होते एसोसिएशन के सचिव विवेक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी और साफ लफ्जों में सुधीर की गिरफ्तारी के तौर-तरीकों का विरोध किया गया. सुधीर को एक ईमानदार अफसर बताया गया और इशारा दिया गया कि इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे कुछ चुनिंदा अधिकारियों के इशारे पर यह सब हुआ है. इशारा उस एक्सट्रा कॉन्सटीट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ भी किया गया, जो सीएमओ में आधिकारिक रूप से कोई पद नहीं रखता, पर कथित तौर पर सीएमओ में खासा प्रभाव रखता है. एसोसिएशन ने गिरफ्तारी के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग के अध्यक्ष अपने बीमार पिता से मिलने हजारीबाग गये थे. उन्हें जानबूझ कर तीन दिनों की सार्वजनिक छुट्टी शुरू होने से पहले रात को गिरफ्तार किया गया, ताकि सुधीर कम से कम तीन दिन जेल में बिता सकें. एसोसिएशन के इस कड़े तेवर की बात के बाद हम फिर उस पड़ाव पर लौटते हैं, जहां से इस स्टोरी की शुरुआत की गयी थी.

राजभवन के सामने पांच दर्जन आईएएस अधिकारियों का सीना तान कर खड़ा होने और सुधीर की गिरफ्तारी का प्रतिवाद करने जैसी आईएएस अफसरों की गोलबंदी की मिसाल पहले नहीं मिलती. यहां तमाम सवालों के बीच महत्वपूर्ण यह था कि आखिर आईएएस एसोसिएशन ने इतना साहस कैसे जुटाया कि वे सब सीएमओ के खिलाफ खड़े हो गये? ऐसा तब हुआ जब एसआईटी इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि बीएसएसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है. आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार इस घोटाले में शामिल थे कि नहीं, यह अलग बात थी लेकिन आम जनता में यह परसेप्शन बन चुका था कि आयोग के अध्यक्ष की नाक के नीचे घोटाला हुआ तो कहीं न कहीं या तो उनकी निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार थी या फिर वह प्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे थे. हालांकि अभी तक आईएएस एसोसिएशन के अधिकारी सुधीर को महज इसलिए क्लीन चिट दे रहे थे कि उनकी छवि शुरू से ईमानदार अफसर की रही है. लेकिन एसोसिएशन की सक्रियता के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका था. पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सामने आकर सुधीर के पक्ष में खड़े हुए (ध्यान रहे कि मांझी ने अपने कार्यकाल में सुधीर को गृहसचिव बनाया था). फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक पंक्ति का बयान देते हुए कहा कि सुधीर कुमार ईमानदार अफसर हैं और कानून इस मामले पर अपना काम करेगा. इतना ही नहीं, इस मामले में विपक्ष भी कूद पड़ा. विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें सुधीर के साथ काम करने का जितना अनुभव है, उससे वे कह सकते हैं कि सुधीर ईमानदार अफसर रहे हैं. हालांकि मोदी ने यह भी जोड़ा कि परीक्षा घोटाला मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

यह मामला अभी चल ही रहा था कि नीतीश सरकार के सामने नौकरशाही से जुड़ी दूसरी चुनौती सामने आ गयी. 14 जनवरी यानी मकरसंक्रांति के दिन पटना में हुए नाव हादसे की जांच रिपोर्ट के अधार पर सरकार ने सारण के एसडीओ और एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया. इस मामले में पटना के किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किये जाने से नाराज बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की. नीतीश सरकार के सामने यह अनोखी चुनौती थी जब किसी समर्थक दल ने उन्हें आखें दिखाने के बजाय खुद उस सिस्टम के अफसरों ने बागी तेवर अपना लिये.

अब सवाल यह है कि नीतीश के सामने ऐसी चुनौती क्या सिस्टम के अधिकारी केवल अपने बूते उन्हें पेश कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में एक आईएएस अधिकारी, जो एसोसिएशन की बैठक में शामिल थे, ने कहा कि नये बैच के अधिकारी उस मीटिंग में अड़ गये थे और कहा था कि आईएएस अधिकारियों के साथ सीएमओ में बैठे कुछ अफसरान ज्यादती करते हैं इसलिए इसका प्रतिवाद होना ही चाहिए. लेकिन इस मामले में दूसरी सच्चाई यह भी है कि राजनीतिक स्तर पर अफसरों के इस तेवर का समर्थन खुद लालू प्रसाद से मिल चुका था. सुधीर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन लालू ने यह कह कर अधिकारियों का मनोबल बढ़ा दिया कि सुधीर ईमानदार अफसर हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून के दायरे में ही होगी. लालू का यह बयान नौकरशाहों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था. और एक तरह से लालू प्रसाद के इस बयान से ही नौकरशाहों ने इतना साहस दिखाया कि वह गवर्नर हाउस के सामने इंसानी जंजीर बन कर खड़े हो गये.

नीतीश कुमार अपनी तरह की पहली इस चुनौती से कैसे निपटेंगे इस पर सब की नजर रहेगी, लेकिन कुछ विश्लेषकों की राय है कि गठबंधन सरकार के बीच आंतरिक खींचतान और सत्ता संतुलन की कवायद का यह एक हिस्सा हो सकती है. पिछले एक साल से जब से यह सरकार चल रही है, लालू-नीतीश के बीच खट्टे-मीठे रिश्तों की खबरें मीडिया में आती रही हैं. लिहाजा इस प्रकरण से भले ही गठबंधन सरकार के स्वास्थ्य पर कोई खास असर न पड़े पर दोनों दलों के बीच इस मुद्दे को सत्ता संतुलन के लिए चले जाने वाले शह-मात का हिस्सा तो माना ही जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

दुर्गावती परियोजना- अधिकारियों की लापरवाही से 26 करोड़ की योजना पहुंची 1064 करोड़ तक

41 वर्षों बाद भी अधूरी है किसानों की आस

मौजूदा दौर में इस योजना में सालाना 67 करोड़ रुपए केवल विभिन्न स्तरों पर वेतन-भत्ते आदि में खर्च होते हैं. जल संसाधन विभाग बिना काम कराये अपनी राशि का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों पर कर रहा है. जबकि इस संबंध में एक आरटीआई पिछले तीन महीनों से विभागीय टेबल पर इधर-उधर घूम रहा है. क्या इससे योजना का बजट नहीं बढ़ेगा, जबकि यहां ठेकेदारों की कमाई अलग से है. अधिकारियों के साथ मिलकर व योजना के मानकों में छेड़छाड़ कर लूट में हिस्सेदारी करना अब आम बात हो गयी है. लूटतंत्र का जीवंत उदाहरण बनी दुर्गावती परियोजना दशकों से इंजीनियरों-अधिकारियों की पसंदीदा पोस्टिंग रही है.

राणा अवधूत कुमार

वर्ष 1970 के आसपास सिंचाई व्यवस्था के लिए रोहतास और कैमूर जिले के सर्वे के दौरान दुर्गावती नदी पर बांध बनाने की योजना बनी थी. इस बांध से दस प्रखंडों की भूमि सिंचित की जानी थी. जल संसाधन और वन विभाग के भूमि अधिग्रहण में विभागीय पेंच और कुछ अन्य मामलों में कानूनी अड़चन आने से यह प्रोजेक्ट लटक गया. कई साल तक दुर्गावती का मामला कागजों के हस्तानांतरण में ही बीत गया.

1977 में बांध स्थल के चयन और वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने की स्थिति में चयनित स्थल ही विवादों के घेरे में आ गया. दो करोड़ की राशि से तब कार्यस्थल पर प्रारंभिक कार्य होने लगे थे. लेकिन उच्चस्तरीय कमिटी गठित होने और अधिकारियों की लापरवाही से काम बंद होता गया. साल 1978 में बिहार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री सच्चिदानंद सिंह ने एकमुश्त 13 करोड़ की राशि आवंटित करने के साथ बांध स्थल के सभी विवादों पर विराम लगाकर 1980 तक नहरों में पानी पहुंचाने की घोषणा कर दी. इसके बावजूद नतीजा एक बार फिर ढाक के तीन पात साबित हुआ. 1985 तक बांध स्थल रोहतास के करमचट और कैमूर के भीतरी बांध इलाके में बांध बांधने के लिए आवश्यक उपकरणों और अधिकारियों की बढ़ती आवाजाही के बीच फिर से 1991 में नहरों में पानी देने का सपना भी पूरा नहीं हो सका.

रोहतास जिले के तीन प्रखंडों चेनारी, शिवसागर व सासाराम और कैमूर जिले के पांच प्रखंड भगवानपुर, रामपुर, कुदरा, दुर्गावती और मोहनियां प्रखंडों की करीब 20000

विभागीय आदेश के आलोक में अभी कार्य तेजी से जारी है. यदि 31 मार्च से पहले रिवर क्लोजर यानी मुख्य नहरों का कार्य पूरा हो गया तो इस साल सासाराम, कुदरा, भभुआ और मोहनियों के सैकड़ों गांवों के लाखों निवासियों का दशकों पुराना ख्वाब पूरा होता नजर आएगा. पिछले साल नहरों में पानी तो गया लेकिन निकटवर्ती गांवों को ही इसका लाभ मिल सका. कई गांवों में पानी को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो गये थे. इस संबंध में अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि दुर्गावती परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है. अभी दो-दो शिफ्ट में काम हो रहे हैं.

हेक्टेयर बंजर भूमि को उर्वर बनाने और कुल मिलाकर 35000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का मसला इस परियोजना से जुड़ा है. इन प्रखंडों से जुड़ने और इस परियोजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले 384 गांवों के लाखों लोगों का भविष्य इससे जुड़े होने के बाद भी काम की गति बेहद धीमी है और व्यवस्था ऐसी भ्रष्ट कि अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी अपनी सुविधानुसार इसे कमाई का साधन बनाने में जुटे हैं. तभी तो 26 करोड़ की योजना हर दो-तीन साल पर बढ़ती चली गयी. 1980 में 31 करोड़, 1991 में 101 करोड़, 2001 में 181 करोड़ और 2011 में 690 करोड़ से 2017 में 1064 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है.

मुख्य रूप से तीन नहर प्रणालियों के सहारे यह परियोजना संचालित होनी है. दायें किनारे के मुख्य नहर से रोहतास जिला और बांये नहर से कैमूर जिला को पानी देने की योजना है. एक और बड़ी कुदरा वीयर भी कैमूर जिला को सिंचित करती है. दुर्गावती नदी के पानी को बांधकर कैमूर और रोहतास दोनों जिलों के 35000 हेक्टेयर असिंचित यानी बंजर खेतों की सींचने की दूरगामी योजना है. दुर्गावती जलाशय परियोजना की परिकल्पना जगजीवन राम ने की थी. 10 जून 1976 को शिलान्यास होने के बाद दोनों जिलों के सात प्रखंडों के करीब 384 गांवों के लाखों किसानों इसे एक जीवनदायिनी योजना मानने लगे. वहीं अधिकारियों की नजर में यह योजना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान एक पसंदीदा साइट बनकर रह गई. नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी दुर्गावती को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया.

मौजूदा दौर में सालाना 67 करोड़ रुपए इस योजना में केवल विभिन्न स्तरों पर वेतन-भत्ते आदि में खर्च होते हैं. जल संसाधन विभाग बिना काम कराये अपनी राशि का दुरूपयोग सरकारी कर्मचारियों पर कर रही है. जबकि इस संबंध में एक आरटीआई पिछले तीन महीनों से विभागीय टेबल पर घूम रहा है. क्या यह योजना के बजट को नहीं बढ़ायेगी, जबकि यहां ठेकेदारों की कमाई अलग से है. अधिकारियों के साथ मिलकर योजना के मानकों में छेड़छाड़ कर भ्रष्टाचार के लूट में हिस्सेदारी अब आम बात हो गयी है. लूटतंत्र का जीवंत उदाहरण बन दुर्गावती प्रोजेक्ट दशकों से इंजीनियरों-अधिकारियों की पसंदीदा पोस्टिंग रही है.

हाल में मुख्यमंत्री के साथ विभागीय सचिव अरुण कुमार ने न सिर्फ कार्य प्रणाली पर आपत्ति जाहिर की, बल्कि ग्लोबल टेंडर के बाद निर्माण कार्यों के लिए अधिकृत एजेंसी बाबा हंसराज लिमिटेड की कार्यशैली में सुधार लाने के भी निर्देश दिए. इसके अलावा कार्य जल्द पूरा करने के लिए भी कड़े शब्दों में कहा गया. आश्चर्य की बात है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना पिछले 41 वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अधर में लटकी है. यह प्रोजेक्ट तत्कालीन प्राक्कलित राशि 25.30 करोड़ से बढ़कर अब 1064.28 करोड़ लील गयी है. मगर अब तक नतीजा सिफर ही रहा है. फरवरी में डैम का जायजा लेने पहुंचे सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रोजेक्ट पूरा होने में पैसों के आड़े नहीं आने देने की बात कहकर अफसरशाही पर लगाम तो कसी है, लेकिन देखना है कि इसका असर कितना और कब तक धरातल पर दिखता है.

परियोजना की वास्तविक स्थिति यह है कि इस वित्तीय वर्ष में 33 करोड़ की राशि आवंटित होने के बावजूद अबतक मात्र 30 लाख रुपए ही खर्च किये जा सके हैं. वह भी तब जब पिछले एक साल में मुख्यमंत्री तीन बार जिले में आये और दुर्गावती की प्रगति रिपोर्ट देखी और हर बार अधिकारियों को फटकार लगायी. इसके बावजूद डैम का मौजूदा हाल यह है कि डैम के ड्रव क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद नहीं है. किसानों के खेतों तक समुचित पानी आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई है. अभी 102 किलोमीटर लंबे माइनरों का निर्माण होना बाकी है. यह और बात है कि आधे-अधूरे दुर्गावती परियोजना का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2014 को ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कर दिया था. हालांकि इस अधूरी परियोजना का श्रेय लेने के लिए सभी दलों के नेताओं में आपाधापी मची हुई थी. कह कसते हैं कि अधिकारियों की लूट खसोट और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण चार साल का प्रोजेक्ट पिछले 41 साल से आधा-अधूरा पड़ा हुआ है. सिवाय भ्रष्टाचार के आखिर इस विलंब का और कोई दूसरा कारण क्या हो सकता है?

विभागीय आदेश के आलोक में अभी कार्य तेजी से जारी है. यदि 31 मार्च से पहले रिवर क्लोजर यानी मुख्य नहरों का कार्य पूरा हो गया तो इस साल सासाराम, कुदरा, भभुआ और मोहनियों के सैकड़ों गांवों के लाखों निवासियों का दशकों पुराना ख्वाब पूरा होता नजर आएगा. पिछले साल नहरों में पानी तो गया लेकिन निकटवर्ती गांवों को ही इसका लाभ मिल सका. कई गांवों में पानी को लेकर तो विवाद भी उत्पन्न हो गये थे. इस संबंध में अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि दुर्गावती परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है. दो-दो शिफ्ट में काम हो रहे हैं. बीच में नक्सलियों और कुछ स्थानीय व्यवधान आने से कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है. युद्ध स्तर पर नहरों का निर्माण कार्य चल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार-झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में हज़ारों एकड़ में हो रही अफ़ीम की खेती

संरक्षण देकर नक्सली वसूल रहे लेवी

सुनील सौरभ

बिहार-झारखंड की सीमा से लगे बिहार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों का कारोबार फल-फूल रहा है. गया जिले के जीटी रोड से लगे बाराचट्टी, आमस, नवादा जिले के कौवाकोल तथा जमुई जिले के जंगली क्षेत्रों के हजारों एकड़ वन में सरकारी तथा रैयती भूमि पर अफीम की खेती होती है. इस खेती को नक्सली संगठनों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है. साथ ही इन क्षेत्रों में पुलिस, सुरक्षा बलों और वन विभाग के कर्मियों को भी संदेह के घेरे में देखा जा रहा है. जब काफी हो-हल्ला मचता है तो पुलिस महज दिखावे के लिए दस-बीस एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट कर देती है. इसके बावजूद इन क्षेत्रों में अफीम की खेती दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है. जीटी रोड बगल में होने के कारण इस नशीले पदार्थ की तस्करी पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड आदि राज्यों में बड़ी आसानी से होती है.

21 मार्च 2016 को गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स अधिकारियों ने बाराचट्टी थाना के 71 माइल स्थित एक लाइन होटल से बिरजू यादव को डेढ़ किलो अफीम और करीब सवा क्विंटल डोडा के साथ गिरफ्तार किया था. उसी दौरान जानकारी मिली कि अफीम की खेती कराने में नक्सलियों का हाथ है. नक्सली अफीम का पौधा लगाने से लेकर अफीम तैयार होने तक विभिन्न स्तर पर लेवी वसूलते हैं. इस मामले में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की स्थिति भी संदिग्ध है. नारकोटिक्स के अधिकारियों ने बताया कि हर गांव में पुलिस के चौकीदार तैनात रहते हैं. इसके बाद भी इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही है. ऐसे में पुलिस बल व वन विभाग के अधिकारी भी संदेह के घेरे में हैं. वन विभाग के बड़े भू-भाग में अफीम की फसल लहलहा रही है और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है. यह बात समझ से परे है. एक दशक पूर्व गया जिले के बाराचट्टी के जंगली क्षेत्रों में एक-दो कट्ठे में चोरी-छिपे अफीम की खेती होती थी. ये

खेती करने वाले जब अंधाधुंध लाभ कमाने लगे, तो अन्य ग्रामीण भी चोरी-छिपे अफीम की खेती करने लगे. धीरे-धीरे सरकारी भूमि तथा वन विभाग की भूमि पर भी अफीम की खेती होने लगी. अब स्थिति यह है कि क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों ने अफीम की खेती करने वालों से लेवी वसूलना शुरू कर दिया है. नक्सली संगठनों का संरक्षण मिलने के बाद ग्रामीण भी बेखौफ हो गए और उन्होंने हजारों एकड़ में अफीम की खेती शुरू कर दी. 2016 में सुरक्षा बलों ने गया जिले के बाराचट्टी तथा आमस थाना के दो दर्जन गांवों के 373 एकड़ मे लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था. इस प्रकार नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के महुलियाटांड़ गांव में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया था. इसी से लगे जमुई जिले के जंगली क्षेत्रों में अफीम की खेती हो रही है. एक अनुमान के अनुसार जीटी रोड से प्रतिदिन लाखों रुपए के अफीम की तस्करी होती है. बिहार में पड़ने वाला करीब सवा दो सौ किलोमीटर लंबा जीटी रोड आज नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रमुख स्थल बन गया है. एक सिंडिकेट बनाकर अफीम की तस्करी की जाती है, जिसमें नक्सली, वनकर्मी से लेकर स्थानीय पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. जीटी रोड से लगे बाराचट्टी के जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थाई रूप से कोबरा बटालियन का कैम्प है. साथ ही गांव-गांव में पुलिस के चौकीदार और एसपीओ कार्यरत हैं. वन विभाग के कई कर्मी भी तैनात हैं. इसके बावजूद अफीम की खेती होने की भनक तक इन्हें नहीं मिलती, तो इसे भला क्या समझा जाए?

गया के डीएम कुमार रवि ने संबंधित सरकारी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अफीम की खेती की रोकथाम के लिए समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की बात कही. 10 फरवरी 2016 को गया के समाहरणालय कक्ष में हुई बैठक में डीएम ने प्रभावित क्षेत्र के आठ पंचायतों के मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से कहा था कि बुआई के समय इसकी तत्काल सूचना दें और पुलिस सुरक्षा बल इन खेतों को नष्ट कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करें. इसके लिए उन्होंने गांवों में जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया था. इसके बावजूद आज की तारीख में इन क्षेत्रों में हजारों एकड़ में अफीम की खेती लहलहा रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

बांझपन से बच सकती हैं महिलाएं
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
DR. MANJU SINHA (MS DGO)
NISHA CLINIC, Katari Hill Road, Gaya
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine
Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex
Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
डॉ मन्जू चिन्हा जो गया मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं साथ ही कटारी हिल रोड स्थित निशा क्लिनिक चलाती हैं। गायनो रेपोसिलिस्ट डॉ मन्जू ने बातचीत के दौरान बताया कि बच्चा होना या नहीं होना जिसे इन्फरलिटि कहा जाता है इसमें 60 प्रतिशत दोष महिलाओं का माना जाता है 40 प्रतिशत पुरूषों में कमी पायी जाती है। पूर्णतः महिलाओं को दोष देना पुरानी दकियानुसी मान्यता रही नहीं है। डॉ. मन्जू ने बताया कि आज भी सन्तान होना और नहीं होना अन्ततः किसी औरत के बच्चेदानी पर ही निर्भर करता है। महिलाओं में हारमोनल सिस्टम ठीक रहने के कारण, थाइराइड होना भी सन्तानहीनता का कारण बन जाता है। उन्होंने बताया कि पुरूष के स्पर्म और महिलाओं के अंडा के निषेचन के बाद नया बच्चा बनता है यदि यह निषेचन नहीं होता है तो नयी पद्धति द्वारा दोनों को बाहर निषेचित करा कर उसे पुनः गर्भाशय में डाला जाता है। आईसीएफ (इनविट्रोफर्टिलिटी) द्वारा किया गया गर्भाधारण ही टयूब बेबी कहा जाता है। डॉ मन्जू ने बताया कि हमलोग एक साल के ट्रिटमेन्ट और टेस्ट से पता कर लेते हैं कि बच्चा हो सकता है या नहीं इसके बाद नहीं होने की स्थिति में मातृत्व पाने के लिए बच्चा एडोप्ट करने की सलाह देते हैं। प्रजनन क्षमता को बढाने के कुछ टिप्स- 1)हमेशा ताजा सब्जी खायें एक सप्ताह की सब्जी एक ही बार नहीं लायें। 2) साबुत अनाज अपने भोजन में भरपूर मात्रा में शामिल करें 3) दूध के प्रोडक्ट भी अपने भोजन में शामिल करें जैसे कि लस्सी , छाछ और दही और पनीर। इनमें काफी मात्रा में कैल्शियम के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं शिशु के कंकाल तंत्र के निर्माण होने समय उसे मजबूती के साथ विकसित होने में मदद करते है 4) शतावरी का प्रयोग स्त्रीयों के लिए फायेमंद है। 5) खजूर का सेवन भी आपकी इनफरटिलिटी को खत्म करने में लाभप्रद है 6) आम का सेवन भी अपने खानपान में शामिल करें । 7) बादाम और अखरोट जैसे मेवे भी आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ने में भरपूर मदद करते है । स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सामान रूप से लाभदायक होता है। 8) पाचन तंत्र को दुरुस्त करें। 9)रोज सुबह टहलने जाएँ ■ – भारती
NOKSIRA
Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

सारे नेता बिजली की बेमानी बहस में जनता को भटकाते रहे

घोटालों पर चुप्पी साधे रहे...

बिजली सम्पदा की ऐतिहासिक लूट पर किसी भी नेता ने नहीं उठाई उंगली

प्रभात रंजन दीन

केंद्र सरकार ने सस्ता कोयला उपलब्ध कराने के लिए नजदीकी कोल ब्लॉक्स आवंटित किए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेश से कोयला आयात करने के संदेहास्पद फैसला ले लिया. ऊर्जा महकमे के वित्तीय समीक्षक कहते हैं कि नजदीकी कोल ब्लॉक्स से कोयला मंगाने से कोयले की उपलब्धता नियमित रहने के साथ-साथ उसकी कीमत भी कम पड़ती और इससे बिजली की कीमत भी काबू में रहती. आकलन था कि इससे प्रतिवर्ष बिजली की लागत पर 300 करोड़ से अधिक बचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहले भी बसपा के कार्यकाल में वर्ष 2009 से 2012 तक तीन लाख मिट्रिक टन से अधिक कोयले की खरीददारी इंडोनेशिया से की गई थी, वह भी दस गुना अधिक कीमत पर.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बिजली पर खूब बात हुई. बिजली को लेकर धार्मिक भेदभाव बरतने के आरोप लगे तो बिजली की 24 घंटे सप्लाई के भारी-भरकम सत्ताई दावे किए गए. बिजली मुद्दा रही, लेकिन बिजली का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना. यथार्थ और तथ्य यही है कि प्रदेश का बिजली घोटाला सामने रख दिया जाए तो वह आजादी के बाद से आज तक के सभी घोटालों पर भारी पड़ जाएगा. लेकिन इस पर किसी ने कोई बात नहीं की. ऊर्जा सेक्टर में हुए घोटालों की अकूत कमाई से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तो भरपूर फायदा उठाया ही, अपने सत्ता-काल में भारतीय जनता पार्टी ने भी ऊर्जा सेक्टर की धन-गंगा का पूरा आचमन किया था. खूबी यह है कि सारी पार्टियों ने एक-दूसरे के कार्यकाल में हुए घोटालों पर पर्दा डालने का काम किया है. सारे राजनीतिक दल चुनाव में एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल कर जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं, लेकिन असल में घपले-घोटालों में साझेदारी से लेकर पर्दादारी में सभी दलों में समझदारी है. इसीलिए मुलायम के कार्यकाल के घोटालों की जांच मायावती नहीं करतीं और मायावती के घोटालों पर अखिलेश कोई कार्रवाई नहीं करते. अब आगे जो आएगा वह अखिलेश काल के घोटालों को दबा देगा.

उत्तर प्रदेश में अब चुनाव बीत चुके हैं. अखबार प्रकाशित होने तक चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे. यही मौका है कि हम बिजली पर बयानबाजियों के बरक्स बिजली-घोटालों की कब्रगाह को उकेरते चलें और सियासत के असली प्रेत-चेहरों को समझाते चलें. 'चौथी दुनिया' ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटालों का पर्दाफाश करते रहने का सिलसिला चलाया है और अपने कई अंकों में घोटालों की अलग-अलग कहानियां प्रकाशित की हैं. इस बार हम यूपी के ऊर्जा घोटालों का समग्र अवलोकन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सनद रहे. इसके लिए हमने प्रमुख रूप से ऊर्जा सेक्टर के व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल से विस्तृत बातचीत की. इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर के कई ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से भी ब्यौरा लिया जो ऊर्जा विभाग की उन शाखाओं में तैनात हैं, जहां घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं की सूचनाएं रहती हैं. घोटालों की समेकित समीक्षा पेश करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज भी खंगाले गए जो पक्के तौर पर घोटालों का पर्दाफाश करते हैं और इनमें से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज 'चौथी दुनिया' के पास उपलब्ध हैं.

घोटालों में बसपा-सपा में भागीदारी भी थी और पर्दादारी भी

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में पिछले 10 वर्षों के दरम्यान हुए घपलों-घोटालों और उस पर सामने आए सरकारी रुख को देखें तो साफ-साफ लगेगा कि घोटालों को लेकर बसपा और सपा में स्पष्ट समझदारी रही है. इसी समझदारी का नतीजा है कि सपा सरकार में बसपा कार्यकाल के घोटाले दबे रह गए. 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर बसपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव मायावती के भ्रष्टाचार भूल गए और उन्हें अपनी बुआ बना लिया. गांव, गरीब, किसान-मजदूर, मध्य वर्ग का हित निरा खोखला राजनीतिक नारा साबित हुआ. प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली गई. जनता को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से जो बिजली मिलनी चाहिए थी, वह घपलों-घोटालों के कारण अनापशनाप कीमतों पर मिली. विडंबना यह है कि बसपा और सपा, दोनों कहती है कि उनके कार्यकाल में 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई. जबकि यह दावे फर्जी हैं. ऊर्जा सेक्टर के कर्मचारियों से बात करें तो आपको बिजली की बदहाली का अंदाजा लगेगा. कर्मचारी ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार और अराजकता का हाल यह है कि पांच रुपये का उपकरण खुलेआम 50 रुपये और पांच सौ रुपये में खरीदा जा रहा है. कोई पूछने वाला नहीं है. आखिरकार जनता की जेब से ही इसकी वसूली और भरपाई होती है. ऊर्जा सेक्टर के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की बेशुमार दौलत के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है. खुलेआम कमीशनखोरी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है. सत्ताधारी नेता से लेकर नौकरशाह तक सब केवल हिस्सा खाने वाले हैं.

देसी कोयला छोड़, क्यों मंगाया विदेश से बेशक़ीमती कोयला?

केंद्र सरकार ने सस्ता कोयला उपलब्ध कराने के लिए नजदीकी कोल ब्लॉक्स आवंटित किए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेश से कोयला आयात करने के संदेहास्पद फैसला ले लिया. ऊर्जा महकमे के वित्तीय समीक्षक कहते हैं कि नजदीकी कोल ब्लॉक्स से कोयला मंगाने से कोयले की उपलब्धता नियमित रहने के साथ-साथ उसकी कीमत भी कम पड़ती और इससे बिजली की कीमत भी काबू में रहती. आकलन था कि इससे प्रतिवर्ष बिजली की लागत पर 300 करोड़ से अधिक बचता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहले भी बसपा के कार्यकाल में वर्ष 2009 से 2012 तक तीन लाख मिट्रिक टन से अधिक कोयले की खरीददारी इंडोनेशिया से की गई थी, वह भी दस गुना अधिक कीमत पर. व्यवहारिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया से कोयला मंगाना उचित नहीं था. इंडोनेशिया से आयातित कोयला पहले देश के तटीय (बंदरगाह वाले) राज्यों में पहुंचता था और वहां से वह रेल और सड़क मार्ग से यूपी पहुंचता था. स्पष्ट है कि विदेश से कोयला आयात करने से लेकर उत्तर प्रदेश तक होने वाली उसकी ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) में भीषण कमाई की गई. ऊर्जा विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ कहते हैं कि यूपी में काम कर रही मशीनों के लिए 'सी' और 'एफ' ग्रेड के कोयले की जरूरत होती है, जबकि आयातित कोयला बिल्कुल ही अलग किस्म और कैलोरिफिक वैल्यू का था. समझा जा सकता है कि आयातित कोयले को भारतीय मशीन के मुताबिक माकूल करने की जब यहां मिक्सिंग मशीन ही उपलब्ध नहीं थी तो उस कोयले का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा? यह अलग किस्म का कोयला घोटाला है, जिसकी जांच हो तो उसकी गहराई की कुछ थाह मिले.

सीबीआई जांच पर जब केंद्र ही कुंडली मार कर बैठ गई

पांच हजार करोड़ रुपये अधिक का घोटाला उजागर होने के कारण दबाव में आई मायावती सरकार ने घोटाले की सीबीआई जांच के लिए दो मार्च 2008 में अधिसूचना जारी की थी. इसके बावजूद जांच नहीं हुई. दरअसल उस घोटाले का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल का भी था, लिहाजा प्रदेश से लेकर केंद्र तक एक हो गए और सीबीआई जांच की अधिसूचना के बावजूद उसकी जांच नहीं होने दी. तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी. सपा के साथ कांग्रेस का प्रेम-सम्बन्ध काफी पहले से चल रहा है. केंद्र का दबाव इस हद तक था कि सीबीआई ने ही कह दिया कि उसके पास इस घोटाले की जांच करने की क्षमता नहीं है. सीबीआई के इस कथन के दस्तावेज 'चौथी दुनिया' के पास हैं. सीबीआई ने अदालत के समक्ष यह भी झूठा बयान दिया कि उक्त घोटाले से कोई गैर-देशीय सूत्र नहीं जुड़ता. यह सीबीआई का सफेद झूठ था.

शेष पृष्ठ 13 पर

पृष्ठ 12 का शेष

उक्त घोटाला दक्षिण कोरिया की कंपनी के साथ मिल कर किया गया था और इस बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सतर्कता अधिष्ठान ने पहले ही कह दिया था कि घोटाले में अंतरराष्ट्रीय लिप्तता है और इसकी केंद्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कोरियाई कंपनी को 220 करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान का दस्तावेज भी बरामद हो गया था. इसके बावजूद जांच नहीं होने दी गई. हैरत की बात यह है कि हजारों करोड़ के घोटाल में लिप्त रहने के आरोपी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि मायावती के कार्यकाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने अपने कई सार्वजनिक बयानों में यह माना था कि ऊर्जा क्षेत्र में मायावती सरकार 25 हजार करोड़ रुपये का घाटा छोड़कर गई है. लेकिन इस घाटे की वजह जानने या उसकी उगाही करने की अखिलेश सरकार ने कभी जरूरत महसूस नहीं की. अकेले जेपी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए ही प्रदेश सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये की चपत लगाई जा चुकी है. इसी वजह से राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को बर्खास्त होना पड़ा, लेकिन घोटाले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में भी 750 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, लेकिन इस घोटाले में लिप्त तत्कालीन सीएमडी आईएएस आलोक टंडन समेत अन्य अधिकारियों और अभियंताओं का कुछ नहीं बिगड़ा. सपा के मौजूदा शासनकाल में बिजली बिलों में फर्जीवाड़ा कर हजार करोड़ रुपये का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया. यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अधिकृत बिलिंग कंपनी की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है. लेकिन इस मामले में भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई.

दस साल के बिजली घोटाले का हिसाब दे दें मायावती और अखिलेश

बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को दबाने में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसी सक्रियता दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी(सी)-1550/2012) तक वापस ले ली. जब मामले की जांच के लिए अखिलेश सरकार से आग्रह किया गया तो हिन्दी में दिए गए दस्तावेजी सबूतों को अंग्रेजी में रूपांतरित कर लाने का आदेश दिया गया. यह समाजवादी पार्टी की सरकार का हिंदी प्रेम था या घोटाला प्रेम, इसे आसानी से समझा जा सकता है. निवर्तमान बसपा सरकार और मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार यह बताने से लगातार कन्नी काटती रही है कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली क्षेत्र में गुणवत्ता लाने, बिजली का उत्पादन बढ़ाने, सुधार लाने और बिजली की दर तय करने के लिए क्या-क्या किया. आयोग के मौजूदा अध्यक्ष देश दीपक वर्मा हैं. आयोग यह नहीं बता पाया कि पिछले 10 साल में किन-किन बिजली कम्पनियों से किस-किस दर पर कितने मूल्य की बिजली खरीदी गई. वित्त विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें तकरीबन दो लाख करोड़ का घोटाला किया गया. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में भी 16 सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. कई गैर जानकार कंपनियों को संलग्न कराया गया और बिना काम के ही भुगतान कर दिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं होने दी और उसे राज्य सतर्कता अधिष्ठान के सुपुर्द (242/2009) कर दिया. बाद में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने भी देखा कि घोटाले के छींटे सपा पर भी आ रहे हैं तो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी. जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं ही सौंपी.

ग़लत टैरिफ पर सात सौ करोड़ रुपये हड़पे, एलआईसी लोन का स्कैम अलग से

बसपा सरकार के कार्यकाल में गलत टैरिफ दिखा कर उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम ने तकरीबन साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का घपला किया. इसमें कुछ कॉरपोरेट घरानों की भी लिप्तता रही. केंद्र सरकार ने इस मामले में आधिकारिक तौर पर यह माना था कि नियामक आयोग द्वारा गलत (कमतर) टैरिफ निर्धारित किए जाने के कारण जल विद्युत निगम को अपूरणीय क्षति पहुंची है. इसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला किसी भी कानूनी नतीजे तक नहीं पहुंचा. इतना ही नहीं जल विद्युत निगम के भ्रष्ट अधिकारी कमीशनखोरी के चक्कर में भी निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाते रहते हैं. ऐसा ही एक वाकया है एलआईसी लोन की बकाया रकम चुकाने का. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर एलआईसी लोन का बकाया 3010.28 करोड़ रुपये था और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम पर मात्र तीन सौ करोड़ रुपये. बकाया ऋण के एकमुश्त (वन-टाइम) भुगतान के लिए एलआईसी ने उत्पादन निगम के समक्ष यह शर्त रखी कि एक साथ पांच सौ करोड़ रुपये जमा करने पर शेष ऋण की राशि माफ कर दी जाएगी. उत्पादन निगम ने आनन-फानन पांच सौ करोड़ रुपये जमा कर अपना लोन क्लियर करा लिया. लेकिन जल विद्युत निगम के कमीशनखोर अधिकारियों ने एलआईसी के प्रस्ताव पर कुंडली मार दी. जबकि विद्युत उत्पादन निगम के तीन सौ करोड़ के बकाये के एवज में मात्र 75.41 करोड़ रुपये ही जमा करने थे. यह छोटी सी रकम भी जमा नहीं की गई और उस पर बकाया ऋण की राशि पांच सौ करोड़ से अधिक हो गई. विडंबना यह है कि एलआईसी ने जिस समय यह प्रस्ताव रखा था उस समय जल विद्युत निगम के पास 130 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े थे.

सात हज़ार करोड़ रुपये लूट लिए, सरकार को 450 करोड़ रुपये का नुक़सान सालाना

ऊर्जा सेक्टर में सात हजार करोड़ रुपये की सुनियोजित लूट के मामले में भी बसपा और सपा दोनों ही कठघरे में हैं. उस लूट का सिलसिलेवार नुकसान यह है कि उससे प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो रही है. नुकसान की यह राशि घोटाले की राशि से अलग है. उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने का सात हजार करोड़ रुपया एकमुश्त गायब हो गया. इसका हिसाब ही नहीं मिला. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के शीर्ष पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने साठगांठ करके इतनी बड़ी धनराशि का गड़बड़झाला कर दिया. ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के हजारों करोड़ रुपये का घपला करने वाले राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक आरएन यादव को सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार करने के लिए अखिलेश सरकार ने पुरस्कृत किया और उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के योजना महकमे का निदेशक बना दिया. अगर जांच होती तो यह मामला यादव सिंह प्रकरण से भी बड़ा घोटाला साबित होता. पूरा सिस्टम ऐसे लोगों पर कितना मेहरबान था इसका उदाहरण है कि जिस समय इस घोटाले की पटकथा लिखी गई उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक रहे एसके अग्रवाल को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बना कर महिमामंडित कर दिया गया और उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक रहे एके अग्रवाल को रिटायर होने के बाद कॉरपोरेशन का सलाहकार नियुक्त कर लिया गया. अग्रवाल ने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी खोल रखी है. ये सब भ्रष्टाचार करने में भी सलाहकार थे और अब भ्रष्टाचार की जांच में भी सलाहकार हैं. इसी प्रायोजित-प्रक्रिया से अखिलेश यादव प्रदेश से भ्रष्टाचार हटाने की कोशिश करते रहे.

निर्माण निगम को ठेका देने में सारे प्रावधान ताक पर रख दिए गए और काम शुरू करने के पहले ही एक हजार करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया. एक हजार करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की इतनी हड़बड़ी थी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सीधे अपने ही फंड से निर्माण निगम को पेमेंट जारी कर दिया. इस पेमेंट के बारे में डिवीजन को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि सारे भुगतान सम्बद्ध डिवीजन के जरिए ही होने चाहिए थे. बाकी बचे सब-स्टेशनों को बनाने का ठेका लार्सन एंड टूब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़ व कुछ अन्य नामी कंपनियों को दिया गया. इन कंपनियों ने बाकायदा सारी औपचारिकताएं पूरी कीं, योजना-प्रस्ताव दिया, अपना बजट-आकलन पेश किया और सब-स्टेशनों के निर्माण में लगने वाली सामग्री और उपकरणों का अग्रिम ब्यौरा भी प्रस्तुत किया. इन कंपनियों को कोई एडवांस भी नहीं दिया गया. प्रदेशभर में विद्युत सब-स्टेशन बन गए, लेकिन निर्माण के दरम्यान कभी उसका इंसपेक्शन नहीं हुआ और सामान व उपकरणों की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई.

सात हज़ार करोड़ रुपये ग़ायब, राजकीय निर्माण निगम ने हिसाब ही नहीं दिया

प्रदेशभर में तकरीबन 80 विद्युत सब-स्टेशनों (उप-केंद्रों) के निर्माण के लिए जो धनराशि दी गई थी, उसमें भीषण भ्रष्टाचार किया गया. इसमें केंद्र सरकार से करीब 20 हजार करोड़ रुपये यूपी के लिए आवंटित हुए थे. कानूनी प्रावधान है कि विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए उसी संस्था को ठेका दिया जाएगा, जिसे विशेषज्ञता और अनुभव हासिल हो. लेकिन पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने इस क्षेत्र में गैर-अनुभवी और गैर-विशेषज्ञ संस्था राजकीय निर्माण निगम को 51 सब-स्टेशन बनाने का बड़ा ठेका दे दिया. राजकीय निर्माण निगम की ओर से कोई योजना-प्रस्ताव, बजट-आकलन और निर्माण की तैयारियों का अग्रिम ब्यौरा भी नहीं दिया गया और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के निदेशक (ऑपरेशंस) आरएस पांडेय की तरफ से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया. निर्माण निगम के नाम से 220 केवी का 21 सब-स्टेशन बनाने और 132 केवी का 30 सब-स्टेशन बनाने की लॉटरी खोल दी गई. निर्माण निगम को ठेका देने में सारे प्रावधान ताक पर रख दिए गए और काम शुरू करने के पहले ही एक हजार करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया. एक हजार करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की इतनी हड़बड़ी थी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सीधे अपने ही फंड से निर्माण निगम को पेमेंट जारी कर दिया. इस पेमेंट के बारे में डिवीजन को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि सारे भुगतान सम्बद्ध डिवीजन के जरिए ही होने चाहिए थे. बाकी बचे सब-स्टेशनों को बनाने का ठेका लार्सन एंड टूब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़ व कुछ अन्य नामी कंपनियों को दिया गया. इन कंपनियों ने बाकायदा सारी औपचारिकताएं पूरी कीं, योजना-प्रस्ताव दिया, अपना बजट-आकलन पेश किया और सब-स्टेशनों के निर्माण में लगने वाली सामग्री और उपकरणों का अग्रिम ब्यौरा भी प्रस्तुत किया. इन कंपनियों को कोई एडवांस भी नहीं दिया गया. प्रदेशभर में विद्युत सब-स्टेशन बन गए, लेकिन निर्माण के दरम्यान कभी उसका इंसपेक्शन नहीं हुआ और सामान व उपकरणों की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई. सारे विद्युत सब-स्टेशन बन गए और मुख्यमंत्री ने फीता काट कर उसे शुरू भी करा दिया. राजकीय निर्माण निगम समेत अन्य निर्माता कंपनियों का भुगतान भी हो गया. लेकिन करीब सात हजार करोड़ रुपया हिसाब से गायब है. उसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है. दस्तावेज बताते हैं कि 6972.35 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है. कॉरपोरेशन ने सात हजार करोड़ रुपये में से 5921.88 करोड़ रुपये रूरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (आरईसी) और पावर फिनांस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में लिए थे. ब्याज को देखते हुए साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का जो नुकसान हो रहा है, वह घोटाले की राशि से अलग है. अराजकता का हाल यह है कि सब-स्टेशनों के निर्माण के बाद राजकीय निर्माण निगम ने खर्चे (कैपिटलाइजेशन) का ब्यौरा प्रस्तुत करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी. जबकि यह कानूनी अनिवार्यता है. निर्माण निगम ने बिजली घरों के निर्माण के बाद उसे हैंडओवर करने के समय न कोई सामान बचा हुआ दिखाया और जो उपकरण लगे उसका भी कोई विवरण (टेक्निकल स्पेसिफिकेशन) नहीं दिया. हैरत की बात यह है कि कई मान-मुनहार के बाद निर्माण निगम ने महज छह बिजली घरों के निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत किया वह भी सिर्फ एक पन्ने में. ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने इस एक पन्ने के पूंजीकरण को भी बिना जांचे-परखे पास कर दिया. भद्दा मजाक यह है कि कॉरपोरेशन ने उस एक पन्ने के ब्यौरे पर लिखा कि निर्माण निगम खुद ही अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से इसकी जांच करा ले. निर्माण निगम द्वारा बनाए गए सब-स्टेशन अब असली औकात पर आ रहे हैं. जो ट्रांसफार्मर लगाए गए, वह कम क्षमता वाले निकल रहे हैं. उस पर भी इंजीनियरों पर दबाव दिया गया कि वे क्लीन-चिट दे दें. जो विद्युत सब स्टेशन बने, उनमें 36 साल पुराने ट्रांसफार्मर लगा दिए गए जो अब लगातार फुंकते जा रहे हैं और राजस्व पर अतिरिक्त नुकसान चढ़ा रहे हैं.

ऊर्जा सेक्टर में सौ-दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले की तो कोई औक़ात ही नहीं!

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में सौ-दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले की तो कोई औकात ही नहीं है. ऐसे घोटाले तो भरे पड़े हैं. बसपा कार्यकाल में जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुए सौ करोड़ के एक अन्य घोटाले में सपा सरकार सीधा संरक्षण दे रही है. इस प्रकरण में ऊर्जा सचिव की जांच रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार से औपचारिक मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा. घोटाले के दस्तावेज भी गायब कर दिए गए. बिजली विभाग में भी पेड़ घोटाला होता है. बुंदेलखंड में 10 करोड़ पेड़ लगाने की योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए लेकिन जल विद्युत निगम के अधिकारियों ने कागज पर पेड़ लगा दिए. ललितपुर के जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट ने भी खुलासा किया कि पेड़ नहीं लगे, लेकिन अखिलेश सरकार ने इस जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई. इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में अंडरग्राउंड केबिल के जरिए विद्युत आपूर्ति के नाम पर सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़प ली गई. विद्युत प्रणाली सुधार योजना के अंतर्गत विश्व बैंक से 70 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से 32 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे. बताया गया कि इस राशि से लखनऊ के यूपीआईएल, राजेन्द्र नगर, अमीनाबाद, हनुमान सेतु, शिवाजी मार्ग, विक्टोरिया पार्क, नीबू पार्क जैसे कई स्थानों पर तकरीबन 465 किलोमीटर की एलटी लाईन और 33 केवी और 11 केवी की 116 किमीटर भूमिगत केबिल बिछाई गई. लेकिन इस केबिल के जरिए आजतक बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाई. इस काम को भी राजकीय निर्माण निगम द्वारा ही कराया गया था. बिजली विभाग के कर्मचारी ही कहते हैं, 'केबिल बिछती तब तो बिजली सप्लाई होती'. यह बात सब जानते हैं, लेकिन जांच कराने को कोई तैयार नहीं.

जो कंपनी थी नहीं, उसे भी दे दिया करोड़ों का ठेका, लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट्स का भट्ठा बैठा

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बिजली को लेकर कितनी चिंतित है उसका नायाब उदाहरण है बिजली को लेकर राज्य में लगातार हो रही भीषण मारामारी. उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों एवं एजेंसियों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है. अपने ही राज्य में सस्ते में बिजली उपलब्ध हो, इसकी चिंता सरकार को नहीं है. उत्तर प्रदेश की तकरीबन डेढ़ दर्जन लघु जल विद्युत परियोजनाएं ठप्प पड़ी हैं. यह उन परियोजनाओं का हाल है, जो मंजूरी की सभी सरकारी औपचारिकताओं से गुजर चुकी हैं और जिनके लिए चयनित कंपनी से बाकायदा करार भी हो चुका है. परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिला सस्ता ऋण और 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपये हजम हो गए. न केंद्र ने ध्यान दिया, न प्रदेश सरकार ने कोई फिक्र की. सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के ठेके उस कंपनी को दे दिए जो अस्तित्व में ही नहीं थी. उस कंपनी से जुड़े लोग एक तरफ बुंदेलखंड में खननराज चलाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा से सम्बद्ध हैं तो दूसरी तरफ वे समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं. अंधेरगर्दी का हाल यह रहा कि ठेका हथियाने वाली कंपनी 'ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड' को जिस समय ठेका मिला उस समय वह कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी. राज्य विद्युत नियामक ने यह भी जिम्मेदारी नहीं निभाई कि जिस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, उसका सम्बद्ध क्षेत्र में कोई अनुभव और विशेषज्ञता है कि नहीं, इसकी जांच कर ले. प्रावधान तो यह है कि परियोजना का काम उसी कंपनी को दिया जाएगा, जिसे उस क्षेत्र में कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो और उसकी ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि (कम से कम तीन साल का ऑडिटेड एकाउंट) ज्ञात हो. 'ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड' ऐसी कोई भी शर्त पूरी नहीं कर रही थी.

अब आते हैं ऊर्जा विभाग की सम्पदा पर नेताओं और नौकरशाहों के ऐश की लत पर. बसपा और सपा की सरकार के मंत्रियों को ऊर्जा विभाग के केवल धन से ही नहीं बल्कि उसकी गाड़ियों, गेस्ट हाउसों, विद्युत उपकरणों, मसलन एसी, गीजर, हीटर, कूलर, वाटर कूलर, कलर टीवी वगैरह की भी लत लगी हुई है. बसपा कार्यकाल के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने तो ऊर्जा महकमे के सभी निगमों से दो दर्जन से अधिक गाड़ियां ले रखी थीं. यही काम अब सपा के मंत्री भी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री के सरकारी सुविधाओं पर गुलर्छे का विरोध करने पर एक आईजी का त्वरित तबादला लोगों को अभी याद ही है. लोगों को विद्युत चिमनियों के धराशाई होने की घटना भी याद है, जिसमें सरकारी राजस्व को छह सौ करोड़ का नुकसान पहुंचा था. यह घपला हुआ था मायावती के काल में और इस पर मिट्टी डाली गई अखिलेश के कार्यकाल में.■

साहित्य, संस्कृति और कला का मिलाप

अनंत विजय

उस दिन मुंबई के मरीन ड्राइव पर सुबह टहलनेवालों का जमावड़ा लगा था तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दिन में जब धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा तो मायानगरी की सियासत का पारा भी ऊपर जाएगा. बेहद शांत समंदर इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा था कि चढ़ते सूरज के साथ मायानगरी मुंबई में कोई सियासी तूफान आनेवाला है, जो तमाम कयासों को ध्वस्त कर देगा. बौद्धिक जुगाली करने वालों को और राजनीतिक चारा मिलेगा और हेतु-हेतु मदभूत वाली चर्चा को पंख लगेंगे. सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि मुंबई महानगरपालिका में किसकी सरकार बनेगी. इस उत्सुकता की वजह यह भी थी कि पच्चीस साल बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने बीएमसी का चुनाव अलग-अलग लड़ा था. एक तरफ सियासी उत्सुकता का वातावरण था तो वहीं मरीन ड्राइव पर देशभर के तमाम साहित्यकार, कलाकार और संगीत से जुड़े लोगों का जमावड़ा होने लगा था. साहित्य, कला और संस्कृति के इस उत्सव लिट-ओ-फेस्ट के तीसरे संस्करण को लेकर मुंबई में हलचल शुरू हो रही थी. सियासी कयासों के बीच लिट-ओ-फेस्ट की फेस्टिवल डायरेक्टर ने जब इसके शुरुआत का औपचारिक ऐलान किया तो समारोह के दौरान भी कई लोग अपने मोबाइल पर बीएमसी के चुनाव नतीजे देख रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे सत्र शुरू हुए तो लोग साहित्य और कला की दुनिया में लौटने लगे. उद्घाटन के बाद पहला बड़ा सत्र खोए वक्त की दास्तां को लेकर था, जिसके पैनल में कथाकार, संस्कृतिकर्मी, राजनीति विश्लेषकों से लेकर हिंदी के प्रकाशक भी मौजूद थे. यह सत्र बहुत दिलचस्प रहा और इसमें लेखन की परंपरा, विरासत और नए विमर्शों पर खुलकर चर्चा हुई. अरुण महेश्वरी, मीरा जौहरी, संदीप भूतोड़िया, गीताश्री और अभय दूबे ने खुलकर अपने विचार रखे. खोए वक्त की दास्तां की चर्चा अंततः सृजनात्मकता के विमर्श पर हावी होने को लेकर हो गई. इसके बाद कई और दिलचस्प सत्र हुए. एक और उल्लेखनीय सत्र रहा-बॉडी शेमिंग यानी महिलाओं को अपने रंग रूप और उनके शरीर को लेकर समाज किस तरह का व्यवहार करता है.

आत्मकथा बनाम जीवनी वाला सत्र भी जीवंत रहा, जिसमें किरण मनराल के साथ लता मंगेशकर पर बड़ी किताब लिखनेवाले यतीन्द्र मिश्र, मोहम्मद रफी की जीवनी लिखनेवाली सुजाता देव और दारा सिंह पर किताब लिखनेवाली सीमा सोनिक ने अपने विचार रखे, लेकिन इसमें दिलचस्प रहा वक्ताओं का अपने अनुभवों को बांटना. फिल्म लेखक आनंद नीलकंठम के साथ मिथक लेखन पर स्मिता पारिख ने बेहद संजीदगी से बात की. इस सत्र में एक बात उभर कर आई कि भारतीय समाज हर तरह के लेखन को लेकर कमोबेश उदार रहता है. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर लेखन के

खिलाफ ज्यादा विरोध आदि नहीं होता है. यही भारतीय समाज और भारतीय पाठकों की बहुलतावादी संस्कृति और हर तरह के विचारों का स्वागत करने की प्रवृत्ति को पुख्ता करती है. आनंद नीलकंठम ने भी माना कि हमारे मिथकों को लेकर, हमारे पुराने ग्रंथों को लेकर पूर्व में लेखकों ने इतना लिखा है कि आगे के लेखकों को उनमें से किसी ग्रंथ को उठाकर लेखन करने की छूट मिल जाती है. इस सत्र में यह बात भी निकल कर आई कि अगर लेखक की मंशा किसी भी मिथकीय चरित्र को अपमानित करने की ना हो तो पाठक भी उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखता है. इन दिनों तमाम तरह के लिटरेचर फेस्टिवल में मिथकों पर अंग्रेजी लेखन को लेकर खासी चर्चा होती है. अलग-अलग सत्रों में अलग-अलग अंग्रेजी लेखकों ने भारतीय पुराणों और धर्मग्रंथों में मिथकीय चरित्र को लेकर बेस्ट सेलर लिखे जाने और उसकी वजहों पर सार्थक चर्चा यहां भी हुई. अश्विन सांघी ने माना कि वो मिथ और हिस्ट्री को मिलाकर मिस्ट्री की रचना करते हैं. उन्होंने भी माना कि कई बार इतिहास और मिथक के बीच आवाजाही करते हुए उनको यथार्थ से मुठभेड़ करना पड़ता है, लेकिन अगर लेखकीय ईमानदारी होती है तो इस मुठभेड़ का स्वरूप विद्रूप नहीं होता है.

किसी शहर पर मुकम्मल किताब हिंदी में कम लिखा गया है. इन दिनों शहरों को केंद्रित कर कुछ अच्छी किताबें आ रही हैं जिनमें फैजाबाद और लखनऊ को केंद्र में रखकर दो किताबें शहरनामा फैजाबाद और दूसरा लखनऊ प्रकाशित होकर पाठकों द्वारा पसंद की जा रही है. नदीम हसनैन की पुस्तक दूसरा लखनऊ के बहाने से लखनऊ और वहां की संस्कृति पर अनूप जलोटा, नदीम हसनैन और अभय दूबे ने विमर्श किया. अनूप जलोटा ने लखनऊ के अपने दिनों को बेहद शिद्दत से याद किया और बताया कि मोहब्बत के उस शहर में अब हजरतगंज में कंधों से कंधे टकराते हुए इश्क की दास्तां कम लिखी जाती है, लेकिन वहां प्यार कम नहीं हुआ है. अनूप जलोटा ने उर्दू के यूपी में सिमटते जाने पर गहरी चिंता प्रकट की. उन्होंने बेबाकी से कहा कि अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो वहां जाकर उर्दू को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और आवश्यकता हुई तो वहां स्थायी रूप से टिककर गालिब और मीर की यादों को जिंदा करेंगे. शाम को संगीत पर एक सत्र में गायक अंकित तिवारी और अनूप जलोटा के साथ सौरभ दफ्तरी ने बेहद ही दिलचस्प बातचीत की. इस सत्र में अंकित तिवारी और अनूप जलोटा के साथ सौरभ दफ्तरी ने भी अपनी गायकी से वहां मौजूद श्रोताओं का मन मोह लिया. सौरभ दफ्तरी की संगीत की समझ चकित करनेवाली थी. एक सत्र में कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने अदिति महेश्वरी गोयल और प्रतिष्ठा सिंह से बात करते हुए ईमानदारी से राजनीतिक सवालों के जवाब दिए. कांग्रेस में नेतृत्व की खोज के सवाल पर उन्होंने माना कि उनकी पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है. प्रिया दत्त भले ही आत्मंथन की बात करें पर इस वक्त कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की नहीं, बल्कि खुद को रीइनवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए. यह मेला इस मायने में भी अनूठा रहा कि इसमें किशोरों को साहित्यिक से जोड़ने की कोशिश की गई. आर्यमन ने एक हाइपर पैरेसेंट्स पर अपनी बात बेहतरीन ढंग से कही.

अपने देश में जिस तरह से लिटरेचर फेस्टिवल में सितारों का जमावड़ा लगता है और फिल्म अभिनेता से लेकर स्टार लेखकों को जुटाया जाता है, वैसे में यह कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है कि किसी लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन में गांव को भी केंद्र में रखा जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में छोटे-बड़े करीब साढ़े तीन सौ लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं और कमोबेश सभी एक जैसे ही होते हैं. पिछले दो संस्करणों में लिट-ओ-फेस्ट भी उसी राह पर चलता नजर आ रहा था, लेकिन तीसरे संस्करण के पहले उसने नई राह बनाई. अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए लिट-ओ-फेस्ट ने साहित्य, कला और संगीत को गांवों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया. मुंबई के पास के शाहपुरा जिले के दहीगांव को लिट-ओ-फेस्ट ने गोद लिया है. लिट-ओ-फेस्ट इस गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास, स्वच्छता अभियान आदि के बारे में वहां के लोगों को जागरूक बना रही है. लिट-ओ-फेस्ट की फेस्टिवल डायरेक्टर स्मिता पारिख ने लिटरेचर के साथ-साथ लिटरेसी के महत्व को भी रेखांकित किया. इतना खूबसूरत साहित्य सृजन हुआ है, उसके पाठक बनाना भी हमारा फर्ज है. अपनी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए लिट-ओ-फेस्ट ने महानगर के पास के गांव में पाठक तैयार करने का बीड़ा उठाया है. इस योजना को पंख लगाने के लिए दहीगांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है. लिट-ओ-फेस्ट से जुड़े प्रकाशकों ने इस पुस्तकालय के लिए किताबें देने का एलान भी किया.

दो साल पहले मुंबई के मशहूर जेजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स से जो सफर शुरू हुआ था, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से होते हुए ग्रांट मेडिकल कॉलेज जिमखाना तक पहुंचा. इस लिटरेचर फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसके आयोजक नवोदित लेखकों की पांडुलिपियां मंगवाते हैं और फिर उनकी जूरी उनमें से चुनाव कर उसको प्रकाशित भी करवाते हैं. पिछले वर्ष चुनी गई पांडुलिपियों का प्रकाशन और विमोचन हुआ, जिसमें बिंदू चेरुन्गात का उपन्यास मेरी अनन्या भी है. मूलतः मलयाली बिंदू ने हिंदी में छोटा पर अच्छा उपन्यास लिखा है. इस वर्ष चुनी गई पांडुलिपियों का एलान भी समारोह में किया गया. इस साल भी आमंत्रित पांडुलिपियों में से जूरी ने चुनाव कर लिया है. कश्मीर की कहानियों को चुना गया है. अगर हम समग्रता में विचार करें तो मुंबई में आयोजित होनेवाले इस लिटरेचर फेस्टिवल ने तीन साल में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है. लिटरेचर फेस्टिवल को गांवों से जोड़ने की अनूठी पहल कर इसके आयोजकों ने अन्य लिटरेचर फेस्टिवल्स के सामने एक मिसाल तो पेश की है, चुनौती भी दी है. अगर शब्द के कद्रदान बचेंगे तभी तो सृजन भी बचेगा और सृजन का उत्सव भी. ■

anant.ibn@gmail.com

कचनार

परिचय

सम्पूर्ण भारतवर्ष के जंगलों में हिमालय के तराई प्रदेशों तथा निचली पहाड़ियों पर कचनार के स्वयं-जात वृक्ष पाए जाते हैं. पुष्प भेद से कचनार की विभिन्न जातियां, जैसे रक्त पुष्पी, श्वेत पुष्पी तथा पीत पुष्पी पाई जाती हैं. पीले कचनार के वृक्ष वृहदाकार तथा पर्वतीय प्रदेशों में होते हैं. इसके पत्र तथा पुष्प दोनों से बड़े होते हैं. औषधार्थ व्यवहार में प्रायः लालफूल वाले रक्त कचनार का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु गुण-धर्मों में सभी प्रकार के कचनार समान हैं, इसलिए एक के अभाव में दूसरे को प्रयुक्त किया जा सकता है. प्राचीन आयुर्वेद निघंटुओं तथा संहिताओं में अनेक स्थानों पर कचनार का वर्णन मिलता है. कई स्थानों पर कचनार की पत्तियों का साग बनाकर खाया जाता है. आयुर्वेदीय मतानुसार पुष्पों के रंगभेद से कई प्रकार के कचनार के वृक्ष होते हैं. उनमें से तीन प्रकार के कचनारों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है. 1. कचनार लाल- इसमें कुछ जामुनी लाल रंग के पुष्प आते हैं. अन्य कचनारों की अपेक्षा यह प्रायः सर्वत्र सुलभता से प्राप्त होते हैं. 2. कचनार श्वेत- इसके पुष्प श्वेत वर्ण के तथा सुगंधित होते हैं. 3. कचनार पीला- इसके पुष्प पीतवर्णीय होते हैं. प्रायः कचनार के पौधों की छाल के रेशों से रस्सी आदि भी बनाई जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

श्वेत/पीला कचनार

- **मुख रोग-** श्वेत कचनार छाल का क्वाथ, फांट या हिम बनाकर कुल्ला करने से मुखपाक का शमन होता है.
- **उदर रोग-** पीले कचनार के पत्रों को सुखाकर, चूर्ण बनाकर रख लें, 5 ग्राम चूर्ण का सेवन कर अनुपात में 2 चम्मच सौंफ का अर्क पीने से आमातिसार में लाभ होता है.
- पीले कचनार के 10 ग्राम पुष्पों को जल में उबाल-छानकर दिन में दो बार पिलाने से आमातिसार में लाभ होता है.
- 20 ग्राम पीले कचनार की छाल को 400 मिली पानी में पकाकर, चतुर्थांश क्वाथ बनाकर, 10-25 मिली पिलाने से आंत के कीड़े मर जाते हैं.
- **त्वचा रोग-** पीले कचनार के बीजों को सिरके में पीसकर लेप करने से घाव के अन्दर के कीड़े मर जाते हैं.
- पीत कचनार पत्र कल्क का लेप विद्रधि में तथा त्वक् कल्क का लेप रसोली एवं घाव में हितकर है.
- **सर्वशरीर रोग-** 5 मिली कांचनार छा सरस में 2 ग्राम जीरे का चूर्ण या 250-500 मिलीग्राम कपूर मिलाकर दिन में दो बार पिलाने से जलन में लाभ होता है.
- **सर्पदंश-** पीत कचनार के बीजों को

पीसकर दंशस्थान पर लेप करने से दंशजन्य वेदना, दाह तथा शोथ आदि विषाक्त प्रभावों का उपशमन होता है.

रक्त कचनार

- **शिरो शूल-** लाल कचनार की छाल को पीसकर मस्तक पर लगाने से शिर:शूल का शमन होता है.
- **मुख रोग-** रक्त कचनार की सूखी टहनियों की राख को या कोयलों को घिसकर दांतों पर मंजन करने से दांत दर्द में कुछ दिनों में आराम हो जाता है.
- **मुख के छाले-** कचनार वृक्ष की छाल और अनार के फूल का क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छालों में लाभ होता है.
- कचनार वृक्ष की 50 ग्राम अंतर छाल को आधा लीटर पानी में उबालें, जब आधा पानी शेष रह जाए तो इस पानी से कुल्ले करने चाहिए. किसी भी औषधि से ठीक न होने वाले छाले भी इससे ठीक हो जाते हैं.
- **कण्ठ रोग-** 10-20 ग्राम कचनार छाल को 400 मिली पानी में उबालकर, चतुर्थांश क्वाथ बनाकर 10-20 मिली की मात्रा में पिलाने से गंडमाला में लाभ होता है.
- रक्त कचनार की छाल के 20 मिली क्वाथ में 1 ग्राम सोंठ चूर्ण बुरक कर सुबह-शाम पिलाने से भी गले की गांठों में लाभ होता है.
- रक्त कचनार छाल या फूल के 10-20 मिली क्वाथ को ठंडा करके शहद मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से लाभ होता है तथा रक्त का शोधन होता है.
- **उदर रोग-** रक्त कचनार की 10-20 ग्राम जड़ों का क्वाथ बनाकर दिन में दो बार पिलाने से जठराग्नि का दीपन होता है.
- 2-5 ग्राम शुष्क पुष्प चूर्ण में समभाग चीनी मिलाकर खाने से कब्ज में लाभ होता है.
- कोविदार पत्र कल्क में व्याघ्र एरण्ड से प्राप्त आक्षीर मिलाकर सेवन करने से पीलिया में लाभ होता है.
- **त्वचा रोग-** कचनार की जड़ को चावलों के धोवन के साथ पीसकर पुल्टिस बनाकर बांधने से फोड़े जल्दी पक जाते हैं.
- 20 मिली कचनार छाल क्वाथ में 250 मिग्रा प्रवाल भस्म मिलाकर दिन में 3-4 बार कुछ समय तक लगातार सेवन करने से लाभ होता है.
- कचनार पुष्प का क्वाथ बनाकर पीने से खांसी, पेशाब के रास्ते से खून आना तथा अत्यधिक रक्तस्राव में लाभ होता है. इस काढ़े की 20 मिली मात्रा को दिन में दो बार पीना चाहिए.
- कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मसूढ़ों की पीड़ा मिटती है.
- दूषित पृथ्वी, जलवायु और सड़े हुए फल से पैदा हुए ज्वर में जो मस्तक पीड़ा होती है, उसको मिटाने के लिए सफेद कचनार के 10-20 ग्राम पत्तों को 400 मिली जल में उबालकर चतुर्थांश क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिए. ■

प्रयोज्यांग : *मूल, पत्र, त्वक् तथा पुष्प.*
मात्रा : *पत्र-स्वरस 12-24 मिली. चूर्ण 3-6 ग्राम. क्वाथ 50-100 मिली. या चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

श्री साईं बाबा के संदर्भ में शोध की आवश्यकता

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

अतीत के शिरडी साईं बाबा सारे संसार में आज एक अद्भुत/दिव्य विभूति के रूप में जाने जा रहे हैं. बाबा के प्रचार-प्रसार के लिए भारत एवं अन्य देशों में जो आशातीत एवं आश्चर्यजनक असंख्य क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस आधार पर यह बात निःसंकोच कही जा सकती है. पिछले कुछ वर्षों में शिरडी में बाबा से संबंधित गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल शिरडी में प्रतिदिन औसतन लगभग 40 हजार श्रद्धालु आते हैं. महत्वपूर्ण और त्यौहार के दिनों में यह संख्या कुछ लाख तक भी पहुंच जाती है. इस संबंध में और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत एवं विदेशों में भक्तों द्वारा खुद-ब-खुद शिरडी साईं बाबा के हजारों मंदिरों एवं उनसे संबंधित (संस्था) भवनों का निर्माण किया गया है. यदि विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मंदिरों के निर्माण के इतिहास को देखें तो ऐसा मिलेगा कि इस प्रकार के मंदिर-निर्माण का कार्य सामान्यतः मुख्य संस्था (जैसे कि श्री साईं के संदर्भ में शिरडी स्थित शिरडी साईं संस्थान है) द्वारा प्रारंभ होता है. बाद में अन्य स्थानों पर उसकी शाखाएं भी खोली जाती हैं. फिर मुख्य ट्रस्ट और उसकी शाखाएं मंदिर के निर्माण की योजना तैयार करती हैं, आवश्यक धन-राशि की व्यवस्था करती हैं और निर्माण-कार्य अपने निरीक्षण में करती हैं. परन्तु बाबा के संबंध में ऐसा नहीं है. यहां बाबा के कई भक्त-व्यक्तिगत रूप से या भक्तों की मंडली स्वयं प्रेरित होकर बाबा के मंदिरों का निर्माण करते हैं. साथ में वे धर्म-संबंधी एवं अन्य लोकोपकारी कार्य भी कर रहे हैं और इसके लिए साधन वे खुद ही जुटा रहे हैं. निःसंदेह भक्तों के मन में कार्य कर रही यह अन्तःप्रेरणा श्री साईं के कारण है, जो आज भी सूक्ष्म रूप से सक्रिय है.

बाबा के बहुत से भक्त उनसे भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और वे बाबा के नाम पर उनका कार्य करने के लिए किसी भी सीमा तक कष्ट उठाने एवं त्याग करने के लिए तैयार हैं. जिस गति से बाबा के भक्तों और बाबा से संबंधित संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है, वह बहुत ही विस्मयकारी है.विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं आदि के रूप में बाबा से संबंधित बहुत सी प्रकाशित सामग्री है, जिसकी संख्या हजारों में है. भक्तों में सदैव बाबा के अतीत और उनसे संबंधित वर्तमान गतिविधियों को अधिकाधिक जानने की उत्कंठा बनी रहती है. बाबा से संबंधित अनेक प्रकार की वेबसाइट्स इंटरनेट इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं. बाबा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के होते हुए भी कुछ ऐसे कार्य जो कि बाबा के नाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए आवश्यक हैं, इस दिशा में भारी कमी है. अर्थात् बाबा के संबंध में गंभीर शोध-कार्य जिसमें कि आधुनिक शोध-पद्धतियों का भी प्रयोग किया गया हो, आशानुरूप नहीं हैं. भारत एवं विदेशों के कई विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से या शोध संस्थानों के सहयोग से बाबा से संबंधित अनुसंधान किये हैं और इस संबंध में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है. तत्संबंधी कुछ पुस्तकें एवं शोध-संबंधी जानकारियों के बारे में लेख, पुस्तकें आदि प्रकाशित हुई हैं. तथापि इन रचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि इन शोधकर्ताओं/लेखकों के लिए बाबा के जीवनकाल या

उनके पश्चात् की ऐसी बहुत सी जानकारियां या दस्तावेज अनुपलब्ध थे. इसलिए वे उनका उपयोग नहीं कर पाये. इसका मूल कारण यह था कि प्रारंभ में बाबा पर लिखी बहुत सी पुस्तकें एवं लेख मराठी भाषा में थे और फिर बहुत बाद में उनके अंग्रेजी-रूपांतर या अंग्रेजी भाषा में लिखी गई स्वतंत्र रचनाएं बाजार में उपलब्ध हो पाई. अब तक शायद ही कोई ऐसा पुस्तकालय हो जहां कि बाबा से संबंधित साहित्य का व्यापक एवं समग्र संग्रह हो.

इस संबंध में गम्भीर अनुसंधान के लिए एक ऐसे उत्कृष्ट पुस्तकालय का होना आवश्यक है, जहां कि बाबा से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज अर्थात पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, पाण्डुलिपियां, हस्तलिखित टिप्पणियां, फोटो, चित्र, रेखा-चित्र, मानचित्र, शोधपत्र एवं इन सभी की सुव्यवस्थित सूची जरूर हो. दुर्भाग्य से अब तक ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं है, जिससे कि बाबा के संबंध में गंभीर अनुसंधान करने के लिए सहायता मिल सके. बाबा के अनेक भक्तों और विशेष रूप से लेखकों के पास बाबा से संबंधित अनेक प्रकार के दस्तावेज हैं, परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में एक ऐसी केन्द्रीय संस्था बने जो कि इस बहुमूल्य संपदा को संभाल कर रखे और उसकी हिफाजत करे. बाबा के हर भक्त का यह प्रयास होना चाहिए कि बाबा से संबंधित पुराने दस्तावेजों को एकत्र करे और उन्हें सुरक्षित रखे ताकि आने वाले समय में अनुसंधान करने वाले उनका उपयोग कर सकें. इस प्रकार का कार्य बाबा के लिए उनका एक महान योगदान होगा. नववर्ष पर हम इस दिशा में कार्य करने का संकल्प करें. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

कंगारुओं के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाज़ों ने डुबोई लुटिया

अपने ही जाल में फंस गई विराट की सेना

सैयद मोहम्मद अब्बास

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार विजय रथ पर सवार थी लेकिन कंगारुओं ने विराट सेना को चौंका दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज से लेकर न्यूजीलैंड जैसी टीम को धूल चटाई. इतना ही नहीं, उसने इंग्लैंड जैसी टीम को भी पराजित किया. क्रिकेट के जानकारों की मानें तो टीम इंडिया का असली इम्तिहान कंगारुओं के खिलाफ होना है. पुणे टेस्ट में स्मिथ की सेना ने विराट की युवा टीम को चारों-खाने चित कर दिया. भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया भले ही इतिहास रचने का दावा करती हो, लेकिन कंगारुओं ने भारत की मांद में घुसकर सेंध लगायी है. पिच के सहारे यानी स्पिन के जाल में विरोधियों को पछाड़ने का दावा करने वाली भारतीय टीम अपने ही जाल में फंस गई है. स्मिथ की अगुआई वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिन के कुछ जांबाज खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ कर रख दी. अब तक भारतीय विकेटों पर टीम इंडिया के स्पिनरों का बोलबाला रहा है, लेकिन इसके उलट पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई स्पिन अटैक टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर भारी पड़ गया. पुणे टेस्ट में तीन दिनों के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को निपटा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से पहले टेस्ट में भारत को 33 रन के भारी अंतर से पराजित कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. इस टेस्ट में टीम इंडिया को बहुत कुछ सीखने को मिला. बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के अलावा टीम इंडिया की फिल्डिंग भी सवालों के घेरे में है. पुणे टेस्ट में जहां एक ओर बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे थे, वहीं टीम के कई खिलाड़ी अहम मौकों पर कैच टपकाने में आगे रहे. इसका खामियाजा टीम को हार के रूप में चुकाना पड़ा. खराब फिल्डिंग ने कंगारुओं के हौसले भी खूब बढ़ाये. कंगारू टीम ने भारत कूच करने से पहले ही अपनी तैयारी को पुख्ता कर लिया था. उसे मालूम था कि भारत में तेज गेंदबाजों का कोई खास रोल नहीं रहता है, नतीजतन उसने तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिनरों पर ध्यान लगाया. इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने अनुभवी स्पिनर नाथन लॉयन के साथ-साथ युवा ओकीफी को टीम में शामिल किया. मलेशिया में जन्मे बाएं हाथ के प्रतिभावान खिलाड़ी ओकीफी ने टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम को उखाड़कर फेंक दिया. हालांकि टीम इंडिया के कोच अनिल कुम्बले वापसी का दावा कर रहे हैं. भले ही टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अगले कुछ टेस्ट में विराट की युवा टीम वापसी करने का दम-खम रखती है.

क्रिकेट पंडितों के अनुसार, अगर विराट की सेना कंगारुओं को टेस्ट सीरीज में परास्त करने में कामयाब रही तो सचमुच यह नम्बर वन टीम है. कंगारुओं की सेना विराट की टीम से लोहा लेना के लिए मैदान में है. उसने पहली लड़ायी में मैदान मारने का हौसला दिखा दिया है. कंगारुओं ने पहले टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया. पेस बैटरी से लेकर स्पिनरों ने भारतीय मजबूत बल्लेबाज क्रम को कहीं का नहीं छोड़ा. जो बल्लेबाज रनों का अंबार लगाते थे, वही स्मिथ की सेना के सामने बेहद कमजोर साबित हुए. पुणे टेस्ट में जहां एक ओर पहली पारी में टीम इंडिया की गेंदबाजी चल पड़ी, वहीं गेंदबाजों की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पारी फेर दिया. कंगारुओं को पहली पारी में केवल 260 रन पर रोकने वाली टीम इंडिया अपने बल्लेबाजों के बेहद गैरजिम्मेदाराना खेल की वजह से अब संकट में दिख रही है. कहने का मतलब यह है कि पुणे टेस्ट में मिली हार से यह साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हराने का माद्दा रखती दिख रही है. अभी टीम इंडिया को पहले टेस्ट में हार मिली, लेकिन यह केवल शुरुआत है. इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में किसी तरह से 260 रन के स्कोर पर पहुंच सकी. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कंगारुओं को बांधे रखा. पहले विकेट की साझेदारी में वार्नर और मैट रैनशॉ ने 82 रन जोड़कर मेजबान टीम को चिंता में डाल दिया था, लेकिन इसके बाद उमेश यादव की तेज गेंदें मेहमान टीम को लगातार झटके दे रही थी. उनके साथ आर अश्विन ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया. उमेश चार और आर अश्विन तीन विकेट लेकर मेहमान टीम को कम स्कोर पर रोकने में कामयाब रहे. जवाब में भारत की पहली पारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. जो बल्लेबाज अब तक रंग में दिखते थे वे अब मेहमान टीम की बलखाती और खतरनाक स्पिन के आगे घुटने टेकते दिखे. विराट टीम की सबसे मजबूत कड़ी बल्लेबाजी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर विकेट से गेंदबाजों की मदद मिल रही हो तो भारतीय बल्लेबाजी चरमरा जाती है. पुणे टेस्ट में भी यही देखने को मिला. आलम तो यह था कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 260 रन के जवाब में टीम इंडिया की पूरी टीम 105 रन के स्कोर पर चलती बनी. इतना ही नहीं, टीम इंडिया के अंतिम सात विकेट केवल 11 रन के स्कोर पर धराशायी हो गए. इस हाल को देख क्रिकेट के कई पूर्व खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कड़ी आलोचना करने से भी नहीं चूके. विराट इससे पूर्व बल्लेबाजी में लगातार करिश्माई खेल दिखा रहे थे, लेकिन कंगारुओं के सामने उनका बल्ला भी बेबस दिखा. यह भी एक इत्तेफाक है कि वे ढाई साल बाद शून्य के स्कोर पर आउट हुए हैं. यही हाल मुरली विजय का भी रहा. जो बल्ला लगातार विजय गाथा लिख रहा था वह मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के आगे एकदम फीका साबित हुआ. रहाणे भी रंग में नहीं दिखे, जबकि साहा तो एकदम फ्लॉप रहे. वहीं लोकेश राहुल ने थोड़ा संघर्ष किया और और 64 रन की पारी खेली जबकि पुजारा का बल्ला भी शांत रहा. साहा को बतौर विकेट कीपर पार्थिव पटेल की जगह शामिल किया गया था. पार्थिव ने अपने बल्ले से लोगों को खूब प्रभावित किया था, लेकिन साहा के फिट होने के बाद उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. ऐसे में अब साहा पर थोड़ा दबाव बढ़ेगा. पहली पारी में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया को कंगारुओं पर लगाम लगाने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन खराब फिल्डिंग ने रही-सही कसर पूरी कर दी. टीम इंडिया के क्षेत्ररक्षकों ने कई अहम कैच छोड़े जिसके बाद कंगारुओं के हौसले बुलंद होते दिखे. स्मिथ जैसे खतरनाक बल्लेबाज का कैच छोड़ना भी काफी भारी पड़ा. स्मिथ ने दूसरी पारी में 109 रन की जुझारू पारी से टीम को संभाल लिया. उनकी पारी की बदौलत कंगारू दूसरी पारी में 285 रन का स्कोर बनाने में कामयाब रहे. इस तरह से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 441 रन की चुनौती मिली. पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टीम इंडिया की कहानी नहीं बदली. स्टीफ न कीफी की स्पिन के आगे एक बार फिर ढेर हो गई. दूसरी पारी में टीम के सात बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके. इतना ही नहीं दो बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके. भारतीय टेस्ट इतिहास में यह सबसे घटिया प्रदर्शन था. बात अगर टीम इंडिया के ओवरऑल प्रदर्शन पर की जाये तो इतना तो साफ है कि टीम ने उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं दिखाया. गेंदबाजी में टीम इंडिया का प्रदर्शन ठीक-ठाक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पहली पारी में कंगारुओं को सस्ते में समेटने में उमेश यादव का खास योगदान रहा. उमेश यादव की गेंदबाजी में अच्छी रफ्तार देखने को मिली. उमेश यादव ने पेस के साथ-साथ स्विंग का भी अच्छा इस्तेमाल किया, जबकि अश्विन का कमाल दूसरी पारी में देखने को मिला. क्रिकेट के जानकारों की मानें तो अभी सबकुछ खत्म नहीं हुआ है. भारत के रिकॉर्ड पुरुष सचिन तेंदुलकर ने वापसी का भरोसा जताया है. जीत और हार खेल का हिस्सा होते हैं.

हाल के दिनों में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई इतिहास रचे हैं, लेकिन कभी-कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी घातक साबित होता है. इससे पूर्व टीम इंडिया ने लगातार छह टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर विश्व क्रिकेट में अपनी हनक पैदा की थी, लेकिन कंगारुओं ने इसे तोड़ दिया. भारत को लगता था कि वह अपनी फिरकी की बदौलत कंगारुओं को निपटा देंगे, लेकिन यही दांव उनपर उलटा पड़ गया. दूसरी ओर बल्लेबाजों ने भी बेहद घटिया प्रदर्शन किया. पूरे मैच में भारत की तरह से एक अर्धशतक लगा, जबकि सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. दूसरी ओर कंगारुओं के पास वार्नर और स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, जो बल्ले से प्रहार करने में ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं. अगर इन दोनों बल्लेबाजों को काबू कर लिया जाये तो टीम इंडिया को फायदा होगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास पेस बैटरी का अच्छा जखीरा मौजूद है, साथ ही उसमें अब स्पिन भी शामिल हो गया है, जो भारतीय पिचों पर नहले पर दहला साबित हो रहा है. ऐसे में अगले टेस्ट में टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी और फिल्डिंग में अच्छा सुधार करने की जरूरत है, तभी वह ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोकने में सफल हो सकती है. ■

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई इतिहास रचे हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी घातक साबित होता है. इससे पूर्व टीम इंडिया ने लगातार छह टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर विश्व क्रिकेट में अपनी हनक पैदा की थी, लेकिन कंगारुओं ने इसे तोड़ दिया. भारत को लगता था कि वह अपनी फिरकी की बदौलत कंगारुओं को निपटा देगा, लेकिन यही दांव उनपर उलटा पड़ गया. दूसरी ओर बल्लेबाजों ने भी बेहद घटिया प्रदर्शन किया. पूरे मैच में भारत की तरफ से एक अर्धशतक लगा, जबकि सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. दूसरी ओर कंगारुओं के पास वार्नर और स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, जो बल्ले से प्रहार करने में ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अपने दौर के चॉकलेटी हीरो थे ऋषि कपूर

प्रवीण कुमार

अपने दौर के स्टार कलाकार रह चुके ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसने बॉलीवुड के 100 साल में से 85 वर्ष का योगदान दिया है. वे एक फिल्म अभिनेता-निर्माता भी हैं. अपने दौर में ऋषि कपूर ने अभिनय से लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई. वे बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते थे. ऋषि कपूर का जन्म 4 सितम्बर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था. ऋषि कपूर बॉलीवुड के शो मैन यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं. राज कपूर की मां का नाम कृष्णा राज कपूर है. ऋषि कपूर का निक नेम चिंटू है. ऋषि कपूर के दो भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर. ऋषि कपूर के दोनों भाई उन्हीं की तरह बॉलीवुड अभिनेता हैं. ऋषि की प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल, मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर में हुई. ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर से हुई है. बता दें, ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को पांच साल तक डेट किया, उसके बाद वे शादी के बंधन में बंध गए. ऋषि कपूर के दो बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर.

फ़िल्मी करियर

फ़िल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा फिल्मों में अभिनय करने में रुचि रखते थे. ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म *मेरा नाम जोकर* से डेब्यू किया था. इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था. ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी में अभिनय किया था. इस फिल्म में उनके अपोजिट डिंपल कपाड़िया थीं. ऋषि कपूर ने अपने करियर में 1973-2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है. इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया है. ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरोज में से एक थे. उन्होंने बॉलीवुड में कई रोमांटिक हिट फिल्में दीं. ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया है. साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया. ऋषि कपूर अभी तक बॉलीवुड में सक्रिय हैं.

ऋषि कपूर के कुछ रोचक क़िस्से

1- ऋषि कपूर बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक व अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं. वे कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी हैं.

2- फिल्म *बॉबी* जो कि *मेरा नाम जोकर* का रीमेक थी, इसमें उनके पिता की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उन्हें इस फिल्म में अपने बेटे यानी ऋषि कपूर को साइन करना पड़ा.

3- ऋषि का अफेयर अपनी पहली को-स्टार डिंपल कपाड़िया से भी रह चुका है.

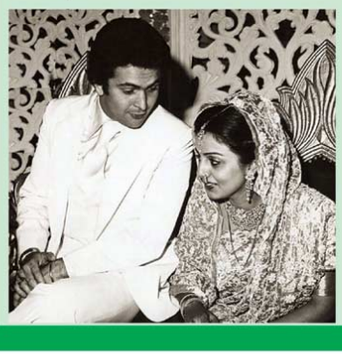

4- ऋषि कपूर ने नीतू से 5 साल के लंबे अफेयर के बाद शादी की थी.

6- ऋषि कपूर ने अपने चालीस साल के फ़िल्मी करियर में पहली बार 2012 में आई फिल्म अग्निपथ के लिए ऑडिशन दिया था. बाद में उन्होंने अग्निपथ में नकारात्मक भूमिका निभाई, जो उनके फैंस को बेहद पसंद आई थी.

7- ऋषि कपूर की पहली फिल्म *बॉबी* है, इसके पहले वे *मेरा नाम जोकर* सहित कई फिल्मों में बचपन का किरदार निभा चुके थे.

8- ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लांच करने के लिए *बॉबी* बनाई थी. इस बात की हकीकत बताते हुए ऋषि कपूर ने कहा कि *मेरा नाम जोकर* की असफलता के बाद राज कपूर की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वे एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे.

9- नीतू कपूर के साथ ऋषि की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया. ख़ासतौर पर युवा इस जोड़ी के दीवाने थे. दोनों ने कई फिल्में कीं और अधिकतर सफल रहीं.

10- कहा जाता है कि *बॉबी* की शूटिंग के दौरान डिम्पल को

ऋषि पसंद करने लगे थे. उन्हें प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल ने अचानक राजेश खन्ना से शादी कर सभी को चौंका दिया. बाद में नीतू सिंह को ऋषि पसंद करने लगे.

11- ऋषि कपूर शूटिंग के समय नीतू सिंह के साथ सेट पर शरारतें कर उन्हें तंग करते थे और नीतू को इससे बेहद चिढ़ होती थी. *अमर अकबर एंथोनी* के सेट पर ऋषि ने नीतू के चेहरे पर काजल फैला दिया था. इस वजह से नीतू को फिर से मेकअप करना पड़ा था.

12- ऋषि के साथ रिश्ते की शुरुआत के समय नीतू इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश में थीं, जबकि ऋषि एक सफल अभिनेता थे. नीतू और ऋषि की पहली फिल्म *जहरीला इंसान* थी.

13-अपनी शादी में नीतू कपूर भीड़ के कारण बेहोश हो गई थीं, वहीं ऋषि को भी चक्कर आ गया था.

14-राज कपूर ने फिल्म *हिना* ऋषि कपूर को लेकर ही प्लान की थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. बाद में रणधीर कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया और हीरो के रूप में ऋषि को ही लिया.

15- ऋषि कपूर ने एक फिल्म भी निर्देशित की है. ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना को लेकर उन्होंने *आ अब लौट चलें* बनाई. ■

feedback@chauthiduniya.com